

सीधी भर्ती से आने वालों के लिए प्रवेशिका पुस्तिका
2019
**INDUCTION HANDBOOK FOR DIRECT RECRUITS
2019**



पूर्व रेलवे
EASTERN RAILWAY
कार्मिक विभाग
PERSONNEL DEPARTMENT
(प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के नियम अनुभाग द्वारा तैयार)
(Prepared By – PCPO's Ruling Section)

सीधी भर्ती से आने वालों
के लिए
प्रवेशिका पुस्तिका
2019

**INDUCTION HANDBOOK
FOR
DIRECT RECRUITS
2019**

पूर्व रेलवे
कार्मिक विभाग
**EASTERN RAILWAY
PERSONNEL DEPARTMENT**

(प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के नियम अनुभाग द्वारा तैयार)
(PREPARED BY – PCPO'S RULING SECTION)

सीधी भर्ती से आने वालों के लिए प्रवेशिका पुस्तिका

प्रस्तावना

यह प्रवेशिका पुस्तिका सभी नई भर्तियों को उस संगठन के बारे में, जिसमें सेवा करने के लिए उनकी भर्ती की गई है और साथ ही एक रेल सेवक के रूप में उसके प्रति उनके अधिकारों तथा दायित्वों की सही जानकारी देने के उद्देश्य से लिखी गई है। यद्यपि, इसका सटीक एवं सुसंगत होना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती गई है, तथापि इस विषय पर इस पुस्तिका और वर्तमान आदेशों/अनुदेशों में कोई विरोधाभास होने की स्थिति में उत्तराद्ध अभिभावी रहेगा। इसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी विवाद अथवा मुकदमें में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, न ही यह किसी कानूनी व्याख्या/साक्ष्य के लिए कोई स्थानापन्न है। इस पुस्तिका में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णय के किसी भी परिणाम के लिए उपयोगकर्ता पूरी तरह जिम्मेवार होगा। आगे, यह ध्यान रखें कि यह कार्यालय सीधे रेल सेवकों से प्राप्त होने वाले सेवा मामलों के संदर्भों पर विचार नहीं करता है। शिकायतों इत्यादि के स्पष्टीकरण/निवारण के लिए प्राप्त होने वाले किसी अनुरोध को उचित माध्यम से संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाए जाने चाहिए।

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय -1	परिचय	3
अध्याय -2	संरचना	4 - 5
अध्याय - 3	कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं	6 - 7
अध्याय - 4	सेवा की सामान्य शर्तें	8 - 12
अध्याय -5	पदोन्नति एवं प्रशिक्षण	13 - 17
अध्याय -6	वेतन एवं भत्ते	18 - 19
अध्याय - 7	सुविधाएं एवं लाभ	20 - 29
अध्याय - 8	नई भर्तियों के लिए करें 'और नहीं करें'	30
	अनुलग्नक - क, अनुलग्नक - ख और अनुलग्नक - ग संलग्न हैं।	

अध्याय- 1

परिचय

भारतीय रेल, जो देश का प्रमुख परिवहन संगठन है, एशिया का और एक प्रबंधन में विश्व का द्वितीय विशालतम रेल नेटवर्क है। यह भारतीय उप-महाद्वीप का प्रथम रेलवे है जो बम्बई से ठाने के बीच 21 मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दिनांक 16 अप्रैल, 1853 को एक औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें अपराह्न 3.30 बजे “विशाल जन-समूह की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 21 बन्दूकों की सलामी देकर” बोरीवली से 14 सवारी डिब्बों वाली एक रेल को लगभग 400 अतिथियों के साथ रवाना किया गया था। पूर्वी भारत को दिल्ली के साथ जोड़ने के उद्देश्य से सन् 1845 में ईस्ट इंडियन रेलवे (ईआईआर) कम्पनी की स्थापना की गई। 15 अगस्त, 1854 को हावड़ा और हुगली के बीच 24 मील की दूरी तक पहली रेल गाड़ी चलाई गई। इस प्रकार, उप महाद्वीप की पूर्वी दिशा में रेल परिवहन की शुरुआत का उद्घाटन करके ईस्ट इंडियन रेलवे के पहले रेल खण्ड (सेक्शन) को आम जनता के आवागमन के लिए खोल दिया गया।

दिनांक 1 जनवरी, 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार ने ईस्ट इंडियन रेलवे का प्रबंधन अपने नियंत्रण में ले लिया। पूर्व रेलवे का गठन दिनांक 14 अप्रैल, 1952 को ईस्ट इंडियन रेलवे के तीन छोटे-छोटे मंडलों : हावड़ा, आसनसोल और दानापुर, सम्पूर्ण बंगाल नागपुर रेलवे (बीएनआर) और उस समय के बंगाल असम रेलवे के सियालदह मंडल को एक में मिलाकर किया गया। 1 अगस्त, 1955 को, बीएनआर के कुछ हिस्सों को पूर्व रेलवे से अलग करके दक्षिण पूर्व रेलवे का गठन किया गया। बाद के दिनों में तीन अतिरिक्त मंडलों : धनबाद, मुगलसराय और मालदा का गठन किया गया।

30 सितम्बर, 2002 तक पूर्व रेलवे के सात मंडल थे। दिनांक 1 अक्टूबर, 2002 को पूर्व रेलवे से दानापुर, धनबाद और मुगलसराय मंडलों को अलग करके एक नए जोन, पूर्व मध्य रेलवे का गठन किया गया। वर्तमान में, पूर्व रेलवे के अंतर्गत चार मंडल अर्थात् हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा हैं, जो मंडल रेल प्रबंधकों के नियंत्रण में हैं और लिलुआ, कांचरापाड़ा और जमालपुर में अवस्थित तीन कारखाने हैं, जिनका नियंत्रण मुख्य कारखाना प्रबंधकों के हाथों में है।

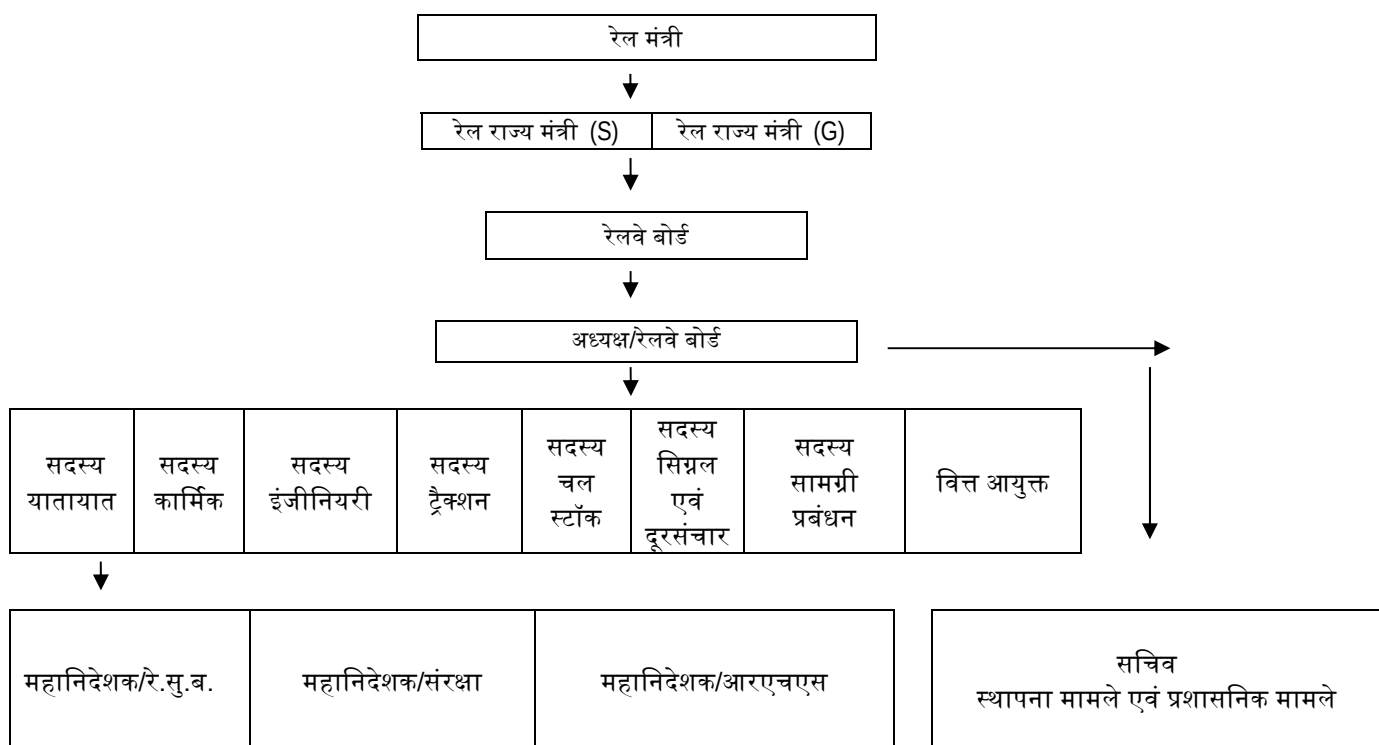
अध्याय- 2

संरचना

महामहिम राष्ट्रपति ने भारत सरकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाए हैं। रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को आबंटित विषय रेल मंत्री (MR) के प्रभार में हैं, जो केन्द्रीय स्तर के मंत्री हैं और उनके सहयोग के लिए दो रेल राज्य मंत्री (MOSR) हैं। रेलवे बोर्ड एक प्रमुख प्रशासनिक एवं कार्यकारी निकाय है, जो रेल मंत्री की, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करता है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1905 को पारित एक संकल्प द्वारा किया गया था। रेलवे बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है :

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड – भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव
2. वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड और
3. सात सदस्य, जिनमें से प्रत्येक को ट्रेक्शन, कार्मिक, यातायात, इंजीनियरी, चल स्टॉक, सिग्नल एवं दूरसंचार और सामग्री प्रबंधन का प्रभार दिया गया है और दो महानिदेशक अर्थात् आरएचएस एवं रेलवे सुरक्षा बल हैं।

रेल मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना



कार्य संचालन एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से भारतीय रेल को सोलह (16) क्षेत्रों (जोन) में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों का नियंत्रण महाप्रबंधकों के पास होता है जो इनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और रेलवे के कार्यों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर रेलवे बोर्ड के समक्ष जवाबदेह होते हैं। ये क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

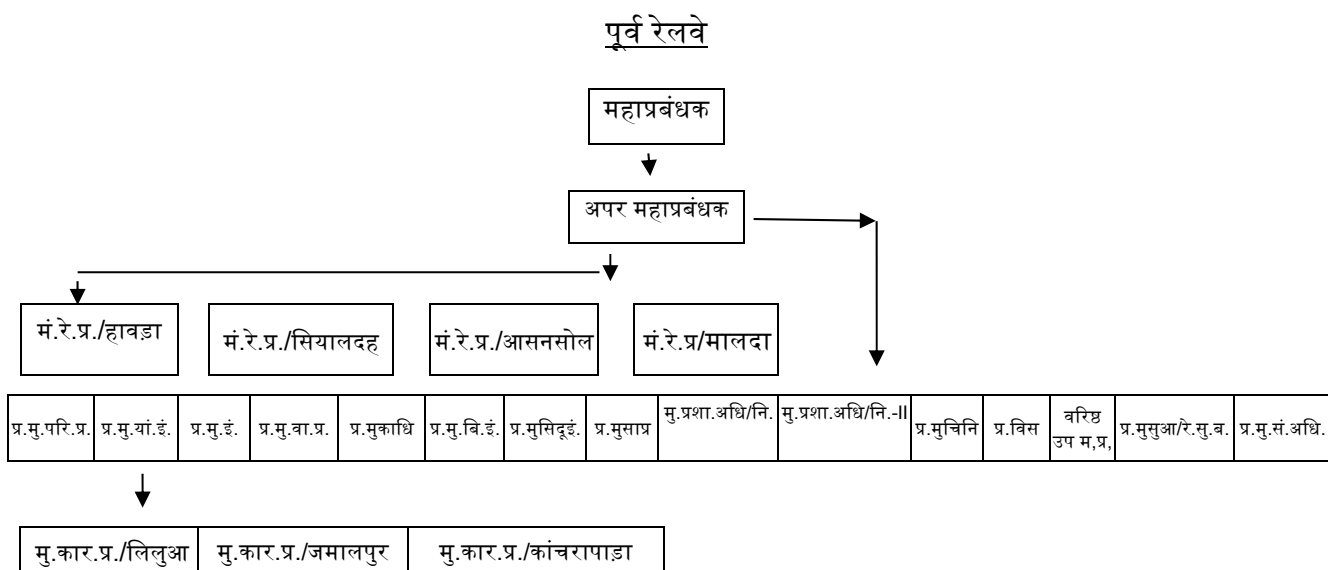
क्र.सं.	क्षेत्रीय रेल	मुख्यालय	गठन की तिथि
1.	दक्षिण रेलवे	चेन्नई	14.04.1951
2.	मध्य रेलवे	मुम्बई	05.11.1951
3.	पश्चिम रेलवे	-वही-	-वही-
4.	पूर्व रेलवे	कोलकाता	14.04.1952
5.	उत्तर रेलवे	नई दिल्ली	14.04.1952

6.	पूर्वोत्तर रेलवे	गोरखपुर	14.04.1952
7.	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे	मालीगाँव	15.01.1958
8.	दक्षिण पूर्व रेलवे	कोलकाता	01.08.1955
9.	दक्षिण मध्य रेलवे	सिकंदराबाद	02.10.1966
10.	उत्तर मध्य रेलवे	इलाहाबाद	01.04.2003
11.	उत्तर पश्चिम रेलवे	जयपुर	01.10.2002
12.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	हुबली	01.04.2003
13.	पश्चिम मध्य रेलवे	जबलपुर	01.04.2003
14.	पूर्व मध्य रेलवे	हाजीपुर	01.10.2002
15.	पूर्व तटीय रेलवे	भुवनेश्वर	01.04.2003
16.	दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे	विलासपुर	01.04.2003
उपर्युक्त के अलावा, मेट्रो रेल/कोलकाता भी मंत्रालय के नियंत्रण में क्षेत्रीय रेल के रूप में कार्य कर रही है।			

प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में प्रत्येक महाप्रबंधक के सहयोग के लिए अपर महाप्रबंधक और प्रत्येक विभाग अर्थात् परिचालन, इंजीनियरी, यांत्रिक, बिजली, सिगनल एवं दूरसंचार, लेखा, वाणिज्य, कार्मिक, भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा विभाग के प्रधान विभागाध्यक्ष/ समन्वयक विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष हैं।

उपर्युक्त सोलह (16) क्षेत्रीय रेलों के अलावा, छः (6) उत्पादन इकाइयाँ हैं अर्थात् चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्टरी, रेल-पहिया संयंत्र, डीजल कलपुर्जा कारखाना और रेल कोच फैक्टरी। रेलवे भर्ती बोर्ड भी रेलवे बोर्ड के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। रेलवे बोर्ड से सम्बद्ध और भी अन्य संगठन हैं, जैसे- मेट्रो रेल/कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में चल रही मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट परियोजनाएं, नई दिल्ली स्थित सेन्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉर्डनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, इलाहाबाद स्थित सेन्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन, क्रिस, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी और रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विस।

क्षेत्रों को पुनः मंडलों तथा कारखानों में विभाजित किया गया, जिनका नियंत्रण क्रमशः मंडल रेल प्रबंधकों और मुख्य कारखाना प्रबंधकों को सौंपा गया। मंडल के बाहर भंडार विभाग भी कार्यरत है, जो प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।



मंत्रालय से सम्बद्ध अन्य कार्यालय हैं- इंडियन रेलवे कॉन्फरेंस (आईआरसीए), रेल संरक्षा आयुक्त, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परिषद, रेलवे टैरिफ इनक्वायरी कमिटी, रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) और रेलवे भर्ती बोर्ड/कक्षा।

अध्याय-3

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं

रेलवे से तात्पर्य उस रेलवे, अथवा रेलवे के किसी भाग से है, जो यात्रियों अथवा माल के सार्वजनिक वहन के लिए है और इसमें शामिल हैं – (ए) बाड़ों अथवा चहारदीवारी के अन्य चिह्नों के भीतर आने वाली पूरी जमीन, जो किसी रेलवे के अधीन भूमि की सीमा को दर्शाता है; (बी) पटरियों की सभी लाइनें, साइडिंगें अथवा यार्डें अथवा किसी रेलवे के उद्देश्य के लिए अथवा उस सिलसिले में प्रयुक्त होने वाली शाखाएं; (सी) किसी रेलवे के उद्देश्य से अथवा उस सिलसिले में प्रयोग में लाए जाने वाले विद्युत कर्षण के सभी उपकरण, विद्युत आपूर्ति एवं वितरण के प्रतिष्ठापन; (डी) सभी चल स्टॉक, स्टेशन, कार्यालय, गोदाम, घाट, कार्यशालाएं, कारखाने, स्थिर संयंत्र एवं मशीनरी, सड़क एवं गलियाँ, रनिंग रूम, विश्रामालय, संस्थान, अस्पताल, जल के कार्य, जलापूर्ति के प्रतिष्ठापन, कर्मचारी आवास और रेलवे के उद्देश्य से अथवा उस सिलसिले में निर्मित अन्य कार्य; (ई) सभी वाहन, जिनका उपयोग रेलवे के यातायात के उद्देश्य से किसी सड़क पर किया जाता है और जो रेलवे के स्वामित्व में, किराये पर लिये गये अथवा रेलवे द्वारा संचालित होते हैं; और (एफ) सभी नौकाएं, जलपोत, बोट, और बेड़े, जिनका उपयोग किसी रेलवे के यातायात के उद्देश्य से किसी नहर, नदी, झील अथवा नौवहन के अंतर्देशीय समुद्र में किया जाता है और जो रेल प्रशासन के स्वामित्व में, किराये पर ली गई अथवा रेल प्रशासन द्वारा संचालित होती हैं।

[संदर्भ: रेल अधिनियम, 1989 का नियम 31]

रेल सेवक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो किसी सेवा का एक सदस्य अथवा रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में किसी पद पर हो। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, वित्त आयुक्त पद पर अथवा उसका एक सदस्य है। इस परिभाषा की सीमा में वैसे व्यक्ति नहीं आते हैं, जिन्हें वैसी सेवा अथवा पद से, जो रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हो, वैसी सेवा अथवा पद के लिए, जो इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं, उधार पर लिया गया है। इस शब्द में अनियत मजदूर शामिल नहीं हैं।

प्रशिक्षु/प्रशिक्षणार्थी से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है, जिसे रेल सेवा में रोजगार की दृष्टि से किसी ट्रेड अथवा व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, जो इस प्रशिक्षण के दौरान सरकार से मासिक दरों पर वेतन प्राप्त करता है परन्तु जो किसी विभाग के संवर्ग में किसी मूल रिक्ति में अथवा उसके लिए नियोजित नहीं किया गया है।

संवर्ग का अर्थ है एक पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत कोई संख्या अथवा कोई सेवा अथवा किसी सेवा का कोई भाग।

स्थानांतरण का अर्थ है किसी रेल सेवक का उस मुख्यालय स्टेशन से, जहां वह नियोजित है, या तो (ए) किसी नए पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा (बी) उसका मुख्यालय बदलने के परिणामस्वरूप किसी अन्य स्टेशन में गमन।

मूल वेतन का अर्थ है विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा परिलब्धियों को छोड़कर वह वेतन जिसे राष्ट्रपति द्वारा उप-नियम 35(iii) के अधीन वेतन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिस पद के लिए कोई रेल सेवक मूल रूप से नियुक्त किया गया है अथवा किसी संवर्ग में अपने मूल पद पर होने के कारण पाने के लिए पात्र है।

टिप्पणी : ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसका किसी स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार किसी राज्य सरकार के पास है, मूल वेतन का अर्थ है वह मूल वेतन जो संबंधित राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों में परिभाषित है।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 103]

निष्ठा की शपथ- सेवा में आने वाले सभी नवागंतुक विभाग/कार्यालय प्रमुख अथवा उनके द्वारा मनोनीत किसी राजपत्रित रेल सेवक के समक्ष अवश्य शपथ लें। शपथ ग्रहण पर विवेकपूर्ण तरीके से आपत्ति जताने वाला व्यक्ति इसकी विधिवत अभिपुष्टि करे। शपथ ग्रहण अथवा अभिपुष्टि निम्नलिखित फार्म में की जाएगी :

“मैं शपथ लेता/ विधिवत पुष्टि करता हूँ कि मैं भारत और भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा और कानून द्वारा स्थापित सच्ची निष्ठा रखूंगा और कि मैं अपने कार्यालय के कर्तव्यों को निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाऊंगा, इसलिए भगवान मेरी मदद करें”।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 221]

किसी रेल सेवक का मुख्यालय— (क) सामान्य नियम के अनुसार और यदि किसी खास मामले में कोई विशेष आदेश नहीं दिया गया हो, किसी रेल सेवक या रेल मंत्रालय के किसी कर्मचारी का मुख्यालय, उस समय क लिए भारत सरकार के मुख्यालय हैं।

(ख) किसी अन्य रेल सेवक का मुख्यालय या तो वह स्टेशन है, जिसे यात्रा भत्ता के उद्देश्य से उसके मुख्यालय के रूप में विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका मुख्यालय घोषित किया गया है अथवा ऐसी घोषणा नहीं किए जाने की स्थिति में वह स्टेशन है, जहाँ उसके कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हैं।

टिप्पणी - निलम्बन के अधीन किसी अधिकारी को, यदि अन्य सभी शर्तें पूरी की जाएं, सेवा पर माना जाएगा, जैसा कि सामान्यतया रेल सेवकों पर लागू होता है, और वह पूर्व अनुमति लिए बिना स्टेशन नहीं छोड़ सकता है। इसलिए, किसी रेल सेवक का मुख्यालय सामान्यतया उसके अंतिम कार्य स्थल को माना जाना चाहिए। तथापि, यदि कोई निलम्बित व्यक्ति मुख्यालय बदलने का अनुरोध करता है तब, किसी सक्षम प्राधिकारी को मुख्यालय बदलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि वह आश्वस्त हो कि ऐसा करने से रेल प्रसासन को कोई अतिरिक्त व्यय, जैसे- यात्रा भत्ता की स्वीकृति अथवा अन्य जटिल स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 234]

परिवार से तात्पर्य है किसी रेल सेवक की पत्नी/का पति, वैध बच्चे और साथ रहने वाले एवं उसपर पूरी तरह आश्रित सौतेले बच्चे। इसमें वे माता-पिता, बहनें और नाबालिग भाई भी शामिल हैं जो उनके साथ रहते हैं और पूरी तरह उसपर आश्रित हैं। परन्तु यह भी कि नियम 615 के अनुसार इसमें केवल वैसे आश्रित परिजन शामिल हैं जो पास नियमों के अंतर्गत पास पाने के लिए पात्र हैं। इस परिभाषा में एक से अधिक पत्नियां शामिल नहीं हैं। 'वैध बच्चे' के अंतर्गत कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे शामिल हैं।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 103(17)]

पुनर्ग्रहणाधिकार का अर्थ है किसी रेल सेवक का वह अधिकार जिसमें वह या तो अनुपस्थिति के तत्काल बाद अथवा अनुपस्थिति की अवधि अथवा अवधियां समाप्त होने पर नियमित आधार पर कोई पद धारण कर सकता है, जिसमें वह सावधिक पद शामिल है, जिसपर उसकी नियमित आधार पर नियुक्ति हुई है और जिसपर वह परिवीक्षाधीन नहीं हो। किन्तु किसी नियमित पद पर बने रहने का अधिकार इस शर्त पर निर्भर करता है कि उस ग्रेड में कनिष्ठतम व्यक्ति को, यदि हकदार व्यक्तियों की संख्या उस ग्रेड में उपलब्ध पदों से अधिक हो, निम्नतर ग्रेड में पदावनत कर दिया जाएगा।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 103(28)]

अध्याय - 4

सेवा की सामान्य शर्त

ऐसे कुछ प्रावधान/अनुदेश हैं, जिनकी जानकारी रखना सेवा में प्रवेश करने वाले सभी नवागंतुकों के लिए अनिवार्य है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे वर्णित हैं :

- रेल सेवा(आचरण) नियम,1966 में वर्णित प्रावधानों का लिखित और भावनात्मक रूप से पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई रेल सेवक वर्णित प्रावधान का किसी प्रकार उल्लंघन करता है तब उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। रेल सेवा(आचरण) नियम,1966 के विवरण के लिए कृपया अनुलग्नक-ए देखें।

[संदर्भ: भारतीय रेल स्थापना नियमावली खण्ड-I का अनुलग्नक-I]

- अभिप्रमाणन फार्म में कोई गलत जानकारी देने अथवा कोई तथ्यात्मक सूचना छिपाने पर इसे अभ्यर्थी की अयोग्यता समझा जाएगा और उसे सरकार के अधीन रोजगार हेतु अयोग्य माना जा सकता है।

[संदर्भ: फार्म ईआर-जी6]

- ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा जो पति/पत्नी के जीवित रहते किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर लेता/लेती है, जिसमें उस पति/पत्नी के जीवित रहते इस विवाह को होने से रोका जा सकता है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा ; और

- कोई भी महिला, जिसके विवाह को उनके पति की इस विवाह के समय कोई पत्नी जीवित रहने के कारण, अमान्य घोषित कर दिया गया हो अथवा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी इस विवाह के समय कोई पत्नी जीवित है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी ।

- रेल सेवा में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अपनी जन्म तिथि की घोषणा करेगा, जो रेल सेवा में प्रवेश करने से पहले किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए व्यक्त अथवा उपलब्धित से भिन्न नहीं होगा। इन नियमों के अनुसार दर्ज जन्म तिथि को बाध्यकारी माना जाएगा और बाद में उस तिथि में सामान्यतः कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 225]

- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा व्यक्ति लिखित रूप में वचन देगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों की उचित देखभाल करेगा, जो रेल सेवक के आश्रित हो गए हैं और यदि बाद में यह साबित हो जाता है कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है अथवा उचित देखभाल नहीं की जा रही है तब अनुशासन नियमों/अस्थायी सेवा नियमों के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाए बिना महाप्रबंधक की शक्ति का प्रयोग कर आगे से उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

[संदर्भ : आरबीई सं. 44/2002 (प्र.मुकाधि/पू.रे.का परिपत्र सं. 62(05)/2002]

- यदि यह पाया जाता है कि कोई सरकारी/रेल सेवक भर्ती नियमों आदि के अनुसार सेवा में आरंभिक भर्ती के लिए योग्य अथवा पात्र नहीं था अथवा उसने नियुक्ति पाने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत किए थे, तब उसे सेवा में बरकरार नहीं रखा जाएगा।

[संदर्भ : आरबीई सं. 110/93 (प्र.मुकाधि/पू.रे.का परिपत्र सं. 102/93]

- रेल सेवकों द्वारा अपने-अपने परिवार की देखभाल करने में विफल होने की शिकायतों की जाँच की जाएगी और यदि मामले को प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है तब उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

[संदर्भ : आरबीई सं. 62/2005 (प्र.मुकाधि/पू.रे.का परिपत्र सं. 40(04)/2005]

- नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को स्वयं आश्वस्त होना चाहिए कि नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का चरित्र और पूर्ववृत्त ऐसा हो कि वह रेलवे बोर्ड द्वारा रेल प्रशासन के लिए समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अनुपयुक्त नहीं हो।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I के खण्ड - घ का पैरा 101]

- प्रशिक्षु अथवा प्रशिक्षणार्थी के रूप में भर्ती किए गए व्यक्तियों को अपने प्रशिक्षण/प्रशिक्षु रहने की अवधि के लिए उसके अपने रेल प्रशासन द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति जमा का भुगतान करना जरूरी होगा।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I के अध्याय -1 के उप खण्ड -II का पैरा 119]

- कोई भी रेल सेवक उचित प्राधिकार के बिना अपने प्रभार की सीमा से अधिक गुजारी गई किसी अवधि के लिए वेतन अथवा भत्ते पाने का हकदार नहीं है।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 235]

- जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हो, किसी रेल सेवक का सम्पूर्ण समय उसे वेतन देने वाली सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है, और उसे उचित प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा स्वीकार किए बिना किसी भी तरह नियोजित किया जा सकता है चाहे क्यों न उसकी सेवाएं इस तरह अपेक्षित हो जैसे सामान्यतया भारत सरकार की समेकित निधि से, स्थानीय निधि से अथवा किसी निकाय की निधि से, जो सरकार में शामिल हो अथवा नहीं, जो पूर्णतया अथवा काफी हद तक सरकार के स्वामित्व में अथवा उसके नियंत्रण में हो, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 237]

- किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा कार्यालय के अधीन नियुक्त किसी स्थायी रेल सेवक के पुनर्ग्रहणाधिकार को रेलवे में दो वर्षों की अवधि के लिए (अपवाद के मामले में तीन वर्ष) रखा जा सकता है। यदि इस अवधि के भीतर उसका नए पद पर स्थायी समायोजन नहीं किया जाता है तब उक्त अवधि समाप्त होने पर तुरन्त उसे या तो रेल सेवा से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अपने मूल कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 244]

- किसी भी रेल सेवक के लिए पाँच वर्षों से अधिक की लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- जब तक कि मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति अन्यथा तय न करे, लगातार पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक अवकाश लेकर अथवा अवकाश लिए बिना छूटी से, विदेश सेवा को छोड़कर, अनुपस्थित रहने वाले रेल सेवक के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है; किन्तु उप नियम (2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उस रेल सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारण बताने का यथोचित अवसर दिया जाएगा।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 510]

- यदि अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अवकाश नहीं बढ़ाता है, वैसी स्थिति में अनुपस्थित रहने वाला रेल कर्मी अवकाश समाप्त होने के बाद अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए No Leave Salary का हकदार है और यह अवधि अर्द्ध वेतन अवकाश के रूप में उसके अवकाश खाता में देय अवकाश से उतनी ही सीमा में काट ली जाएगी, इस तरह की छुट्टी से अधिक की अवधि को असाधारण छुट्टी माना जाएगा। अवकाश समाप्त होने के बाद छूटी से जानबूझ कर अनुपस्थित रहने पर रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I का नियम 518]

- किसी रेल सेवक की सेवा में व्यवधान होने के फलस्वरूप उसकी पिछली सेवा जब्त कर ली जाएगी, किन्तु निम्नलिखित मामलों को छोड़कर: - (क) अनुपस्थिति के लिए अधिकृत छुट्टी; (ख) अनुपस्थिति के लिए अधिकृत छुट्टी के क्रम में अनधिकृत अनुपस्थिति जब तक कि अनुपस्थित व्यक्ति के पद को पूरी तरह नहीं भर दिया जाता है; (ग) निलम्बन, जहां इसके बाद या तो उसी पद पर अथवा किसी भिन्न पद पर तुरंत पुनर्बहाली की जाती है अथवा जहां रेल सेवक की निलम्बन में रहते मृत्यु हो जाती है अथवा उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है; (घ) सरकार के नियंत्रण में किसी प्रतिष्ठान में गैर-अर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन-हित में इस स्थानांतरण का आदेश दिया जाता है; (ङ.) एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के दौरान योगदान देने का समय।

[संदर्भ: पेंशन नियम, 1993 का नियम 42]

- सभी भर्ती ग्रेडों में दो वर्षों तक परिवीक्षा अवधि में रहना अनिवार्य है और जहां आरंभिक प्रशिक्षण अवधि में रहना निर्धारित किया गया है, जैसे प्रशिक्षु रेल पथ निरीक्षक, यातायात प्रशिक्षु इत्यादि के मामलों में, वहां परिवीक्षा अवधि प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद प्रारंभ होगी। नियुक्ति प्राप्तकर्ता को परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद ढंग से पूरा करना है। जिस रेल सेवक ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर ली है उसकी सेवा की पुष्टि पर विचार किया जा सकता है। पदोन्नति वाले सभी ग्रेडों में 12 महीनों की परिवीक्षा अवधि विहित की जानी चाहिए।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I के खण्ड-छ के भाग –II का पैरा 111 से 113]

- जब किसी रेलवे चिकित्सक के क्षेत्राधिकार में रहने वाला कोई रेल कर्मचारी बीमार होने के कारण झूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ हो जाता है, तब उसे 48 घंटों के भीतर सक्षम रेलवे चिकित्सक द्वारा विहित फार्म में जारी अस्वस्थता प्रमाणपत्र अवश्य जमा करना चाहिए। यह अनिवार्य है कि यदि चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर अनुपस्थिति के लिए अवकाश अपेक्षित है तब छुट्टी के इस अनुरोध के साथ रेलवे चिकित्सक द्वारा जारी अस्वस्थता प्रमाणपत्र अवश्य होना चाहिए।
- जब किसी रेलवे चिकित्सक के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने वाले किसी रेल कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर छुट्टी की जरूरत हो, तब उसे 48 घंटों के भीतर किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी अस्वस्थता प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए। उस प्रमाणपत्र में बीमारी की प्रकृति और जिस अवधि तक रेल कर्मचारी के अपनी झूटी करने में असमर्थ होने की संभावना हो सकता है, उसका उल्लेख होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी अपने स्वविवेक से प्रमाणपत्र को स्वीकार कर सकता है अथवा वैसे मामलों में, जहां उसके सही होने पर शंका के कारण हों, मामले को सलाह अथवा जाँच के लिए प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी के पास भेज सकता है।
- कर्मचारी द्वारा छुट्टी के लिए अपने आवेदन पत्र के समर्थन में प्रस्तुत पंजीकृत निजी चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकारी, किसी रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसका आवश्यक सत्यापन किए जाने और उस सत्यापन के पश्चात् दी गई सूचना के आधार पर ही अस्वीकृत कर सकता है।
- अस्वस्थता प्रमाणपत्र केवल चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र के समान होगा और इसका होना स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं समझा जाएगा जब तक कि सक्षम रेलवे चिकित्सक द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I का पैरा 538]

- छुट्टी की स्वीकृति : - अवकाश नियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार किसी प्रमाणपत्र को स्वीकृत किए जाने मात्र से ही रेल कर्मचारी को छुट्टी का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। छुट्टी की स्वीकृति के लिए प्रमाणपत्र को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए और उस प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

[संदर्भ : भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द I का पैरा 551]

- जब कभी कोई सरकारी/रेल सेवक अपने सेवा संबंधी अधिकारों अथवा शर्तों से जुड़े मामलों में कोई दावा करना अथवा किसी शिकायत का निवारण कराना चाहता है, तब उसके लिए यह उचित होगा कि वह तुरंत अपने तत्काल उच्चतर अधिकारी अथवा अपने कार्यालय प्रमुख अथवा उचित स्तर के ऐसे अन्य प्राधिकारी के पास आवेदन करे जो संगठन में ऐसे मामले को सम्भालने के लिए सक्षम हो। पत्राचार के निर्धारित माध्यम से इतर रास्ता अपनाते हुए सीधे अन्य प्राधिकारियों के पास इस तरह अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर इसे गंभीरता से लिया जाना है और इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

[संदर्भ: आरबीई सं.162/15 (प्र. मुकाधि /पू,रे, का क्रमिक परिपत्र सं. 4/16)]

अनुरोध पर स्थानांतरण

सामान्यतया, किसी रेल सेवक को उस रेलवे अथवा रेलवे प्रतिष्ठान में उसकी सम्पूर्ण सेवा के लिए नियोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम नियुक्ति पर उसे पदस्थापित किया गया है और वह किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण का दावा करने का अधिकार का नहीं होगा। तथापि, सेवा अत्यावश्यक होने पर राष्ट्रपति के पास रेल सेवक को किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे अथवा रेलवे प्रतिष्ठान सहित भारत में अथवा बाहर किसी परियोजना में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा। ग्रूप सा और ग्रूप डी रेल सेवक के संबंध में स्थानांतरण संबंधी इस नियम के अधीन राष्ट्रपति के अधिकार का प्रयोग भारत में महाप्रबंधक अथवा किसी निम्नतर प्राधिकारी द्वारा, जिसे अधिकार पुनः प्रत्यायोजित किया जा सकता है, किया जा सकता है।

रेल मंत्रालय का निर्णय - ग्रूप सी एवं डी के रेल सेवकों के अपने कष्ट के विशेष मामलों के आधार पर एक रेलवे से दूसरे रेलवे में स्थानांतरण पर रेल प्रशासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। ऐसे कर्मचारियों को, जिनका एक रेलवे से दूसरे रेलवे में स्थानांतरण उनके अनुरोध पर किया गया है, नए प्रतिष्ठान में पदोन्नति ग्रूप के संबंधित ग्रेड में सभी पुष्टि प्राप्त और स्थानापन्न कर्मचारियों के नीचे रखा जाएगा, चाहे स्थानांतरित कर्मचारियों की पुष्टिकरण की तारीख अथवा स्थानापन्न सेवा की अवधि जितनी भी हो।

[संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I का नियम 226]

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार एक वरिष्ठता इकाई से दूसरी में स्थानांतरण की अनुमति निम्नलिखित तरीके से दी जाती है :

- क) सीधी भर्ती वाले ग्रेडों में सीधी भर्ती कोटा के रिक्त पदों पर निम्नतम वरिष्ठता क्रम में, किन्तु शर्त यह है कि स्थानांतरण का अनुरोध करने वाला कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित योग्यता को पूरा करता हो; और
- ख) निजी अनुरोध पर समनुरूप संवर्ग के किसी ग्रेड में परस्पर अदला-बदली अथवा उस कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार, जिसके साथ अदला-बदली कर रहा है, इन दोनों में जो भी निम्नतर हो। यह इस शर्त पर निर्भर है कि परस्पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारी एक ही कोटा के हों अर्थात् सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अनुसूचित जनजाति। तथापि, भर्ती ग्रेडों में परस्पर स्थानांतरण की भी इस प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि परस्पर स्थानांतरण चाहने वाले दोनों कर्मचारियों की सीधे खुले बाजार से भर्ती की गई हो।
- ग) लेवल-1 (तत्कालीन ग्रेड वेतन रु.1800) में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, समनुरूपी संवर्ग की शर्त को छोड़ दिया गया है।
- घ) दो भिन्न ग्रेडों के समनुरूपी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के बीच संवर्ग के केवल भर्ती ग्रेड में उनकी अपनी अपनी नई इकाई में निम्नतम वरिष्ठता के साथ परस्पर स्थानांतरण की भी अनुमति दी जा सकती है।

- ड) निजी अनुरोध पर निम्नतम वरिष्ठता के साथ एकतरफा स्थानान्तरण पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि रेलवे में योगदान देने के पाँच वर्ष पूरे नहीं हो जाएं।
- च) आरबीई सं. 12/17 (प्र.मुकाधि का क्रमिकपरिपत्र सं. 15/17) के अनुसार परस्पर स्थानान्तरण, पति/पत्नी होने के आधार पर स्थानान्तरण, अशक्त बच्चे तथा शारीरिक रूप से विकलांग रेल सेवकों की देखभाल करने वाले रेल सेवकों को सेवा में 5 वर्षों की छूट दी गई है।
- छ) पति/पत्नी होने के आधार पर स्थानान्तरण के सभी मामलों पर आरबीई सं. 23/2010 (प्र. मुकाधि का क्रमिक परिपत्र सं. 21/2010) में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार विचार किए एवं निर्णय लिए जाएंगे।
- ज) ऐसे सभी अनुरोध विहित प्रपत्र पर सभी सही एवं पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना और नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से संबंधित कार्मिक शाखा के अधिकारी के पास पंजीकरण हेतु भेजे जाने हैं।

रेलवे से बाहर के पदों के लिए सेवारत रेल कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों का प्रेषण :

- क) रेल कर्मचारियों को सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अथवा काफी हद तक वित्तपोषित और नियंत्रित स्वशासी निकायों के नोटिसों के जवाब में आवेदन करने के एक वर्ष में 4 अवसर दिए जा सकते हैं किन्तु उस स्थिति को छोड़कर, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी आवेदन को जनहित में रोककर रखना न्यायोचित समझा गया हो।
- ख) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के जवाब में किए गए आवेदनों को उपर्युक्त चार अवसरों के साथ नहीं गिना जाएगा।
- ग) यदि कोई रेल कर्मचारी किसी निजी संस्थान के किसी पद के लिए आवेदन करना चाहता है तब उसे पहले रेल सेवा से इस्तीफा देना अथवा सेवानिवृत्त होना पड़ेगा।
- घ) अन्य पदों के लिए सरकारी सेवकों के आवेदनों को अग्रसारित नहीं किया जाना चाहिए यदि उनके विरुद्ध वृहत् अथवा लघु शास्ति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन हो।
- ड) जहां किसी सरकारी सेवक ने अपने ही अथवा किसी अन्य विभाग में किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया हो और चयन प्रक्रिया चल रही हो, तब प्रशासनिक कारणों से उसे पूर्ववर्ती पद से इस्तीफा देना होगा, इस इस्तीफे को तकनीकी इस्तीफा कहा जा सकता है और ऐसे मामलों में आरबीई सं. 21/2017 (प्र. मुकाधि का क्रमिक परिपत्र सं. 26/2017) द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन सेवा के सभी लाभ दिए जाएंगे।

अध्याय - 5

पदोन्नति एवं प्रशिक्षण

प्रशिक्षण:

भारतीय रेल के समक्ष उत्पादकता में सुधार के द्वारा संसाधन तैयार करके और तकनीक में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करके ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी चुनौतियों का सामना केवल पुरुष तथा महिला रेलकर्मियों में सही दृष्टिकोण विकसित करके उनके ज्ञान एवं कौशलता को निरंतर उन्नत करने के द्वारा ही कारगर ढंग से किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति में प्रशिक्षण की भूमिका पर अत्यधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। सही कहा गया है कि कार्य के वातावरण के लिए क्या करना है, केवल इसकी जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें यह जानना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे और क्यों किया जाना है।

प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए, रेलवे बोर्ड द्वारा भारत सरकार की “राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति” के साथ समन्वय करते हुए ‘प्रशिक्षण प्रबंधन नियमावली’ (इसके पश्चात् नियमावली पुकारा जाएगा) प्रकाशित किया गया है।

एक निर्माण संगठन में, प्रशिक्षण, सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें सुनियोजित तरीके से सीखने के अवसर तैयार किए जाते हैं जिससे कर्मचारियों में ज्ञान, कौशलता और अभिवृत्ति विकसित की जा सके, जो उनके कार्यों के कारगर निष्पादन हेतु जरूरी है। इसके द्वारा हम बहुत कम खर्च में अपने पास उपलब्ध उपायों को अपनाकर संगठनात्मक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। नियमावली के अनुसार, प्रशिक्षण क्रियाकलापों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है :

- प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (ट्यूटर/ट्रेनर द्वारा)
- कार्य आधारित परियोजनाएं
- व्यक्तिगत पढ़ाई
- ऑन-द-जॉब कोचिंग/मेंटरिंग
- डेस्क निर्देश/परफॉर्मेंस आधारित सहायता
- खुली शिक्षा
- कार्यशालाएं
- सम्मेलन/प्रदर्शनियाँ
- दूसरी व्यवस्था/दौरा

प्रशिक्षण को मोटे तौर पर निम्नलिखित चार प्रकारों में कोटिबद्ध किया जा सकता है :-

- (1) आरंभिक/प्रवेशिका प्रशिक्षण (संगठन में नया प्रवेश करने वालों को दिशानिर्देश देने के उद्देश्य से)
- (2) पुनश्चर्या प्रशिक्षण (ज्ञान को पुनः ताजा करने के उद्देश्य से)
- (3) पदोन्नति प्रशिक्षण (कर्मचारियों को उच्चतर दायित्व संभालने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से) और
- (4) संरक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण (विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से) इत्यादि ।

भारतीय रेल के पास 297 प्रशिक्षण केन्द्रों का एक विशाल नेटवर्क है जहां रेल सेवक आरंभिक, पुनश्चर्या, पदोन्नति तथा विशेषज्ञताप्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण को अधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाने के उद्देश्य से इसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन किए गए हैं। वे निम्नानुसार हैं :

- तनाव से मुक्त होने में सहायता करने के उद्देश्य से सभी कर्मचारियों को अनिवार्य योग प्रशिक्षण।
- बेहतर ग्राहक पटल (कस्टमर इंटरफेस) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगली पंक्ति के कर्मचारियों के लिए सॉफ्ट स्किल /ग्राहक सेवा प्रशिक्षण की भी शुरुआत की गई है,

- प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास के लिए एक पृथक योजना शीर्ष की भी अधिसूचना जारी की गई है जिससे प्रशिक्षण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके,
- मेस की सुविधाओं में सुधार।

इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट सुरक्षा योजना (2003-13) पर नियंत्रक एवं महालेखाकार की रपट को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों (संरक्षा एवं गैर-संरक्षा दोनों और अनुरक्षण कर्मचारी) के लिए अग्नि शमन/ अग्नि शमन यंत्रों के उपयोग पर आरंभिक तथा आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की शुरुआत की गई है। पूर्व रेलवे में कार्यरत प्रशिक्षण केन्द्रों सहित बहु-विषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (MDZTC) और बहु-विषयक मंडल प्रशिक्षण संस्थानों (MDDTC) की सूची।

पूर्व रेलवे में निम्नलिखित प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं :

बहु-विषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (MDZTI)	क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान (ZRTI)/भूली/धनबाद
बहु-विषयक मंडल प्रशिक्षण संस्थान (MDDTC)	क) मंडल यातायात प्रशिक्षण केन्द्र/मधुपुर/आसनसोल, ख) मंडल कर्षण प्रशिक्षण केन्द्र/बामनगाछी/हावड़ा, ग) सवारी एवं मालडिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र/नैहाटी/सियालदह, घ) सिगनल एवं दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र/मालदा।
आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्र	क) आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्र/जमालपुर और लिलुआ ख) सिगनल प्रशिक्षण केन्द्र/ आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्र/कांचरापाड़ा
विशेषज्ञताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र	क) सिगनल एवं दूरसंचार- सिगनल एवं दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र/लिलुआ ख) बिजली – विद्युत लोको प्रशिक्षण केन्द्र/आसनसोल और पायलट प्रशिक्षण विद्यालय/जमालपुर ग) इंजूनियरी – इंजीनियरी प्रशिक्षण केन्द्र/बेलियाघाट/सियालदह (पहले से ही उन्नत ट्रेक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित) घ) सुरक्षा – रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र/कांचरापाड़ा ङ) यांत्रिक- फ्रेट स्टॉक एवं मेमू/डेमू बॉक्स एन प्रशिक्षण केन्द्र/अंडाल और एलएचबी, आईसीएफ, पावर कार, टीएल एंड एसी- टिकियापाड़ा सवारी एवं माल डिब्बा प्रशिक्षण केन्द्र।

परियोजना सक्षम-II, 2019: प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 30/10/2017 को 'परियोजना सक्षम' की शुरुआत की गई। जनवरी, 2018 से सितम्बर, 2018 तक लगभग 13 लाख रेल कर्मचारियों को 5 दिवसीय ऑन-जॉब प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी लाइन पर चलते हुए दिनांक 20/03/2019 से 'परियोजना सक्षम-II, 2019' की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक नौ महीनों की अवधि में 5 दिवसीय ऑन-जॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

मिशन सत्यनिष्ठा - दिनांक 27 जुलाई, 2018 को आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है- सभी रेलकर्मियों को अच्छे आचार-विचार एवं कार्य में ईमानदारी के उच्च मानक बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज सम्पूर्ण भारतीय रेल में इस विषय पर वार्ता एवं व्याख्यान के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मिशन के उद्देश्य हैं :

1. प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में आचार-विचार की आवश्यकता एवं महत्ता को समझने के लिए प्रशिक्षित करना।
2. जीवन की तथा सार्वजनिक प्रशासन में आचार-विचार संबंधी दुविधाओं को दूर करना।
3. आचार-विचार एवं ईमानदारी के संबंध में भारतीय रेल की नीतियों और इन्हें बनाए रखने में कर्मचारियों की भूमिका को समझने में मदद करना।
4. आंतरिक गुणों को उभारकर अंतर्मन के शासन को विकसित करना।

कैरियर प्रगति एवं पदोन्नति :

भर्ती करने के छः तरीके हैं :- (क) पदोन्नति (ख) सीधी भर्ती (ग) प्रतिनियुक्ति (घ) आमेसन (ङ) पुनर्नियोजन (च) अल्पकालिक अनुबंध। प्रत्येक तरीके से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत, जो किसी पद अथवा सेवा विशेष के लिए विहित किया जा सकता है, कई विचारों के न्यायिक सम्मिश्रण पर निर्भर करता है।

जिस तरीके से पदों के किसी खास ग्रेड अथवा समूह के लिए भर्ती की जानी चाहिए उसका निर्धारण योग्यता, अनुभव एवं पद के कुशल प्रबंधन हेतु अपेक्षित पूर्ववर्ती प्रशिक्षण के संबंध में विचार किया जाना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि सेवा के निचले ग्रेडों अथवा निचले पदों पर नियोजित व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हों जिससे उनमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा बनी रहे। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण 1989) के अध्याय-I, खण्ड-बी, उप खण्ड-III में भिन्न-भिन्न विभागों के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए विस्तृत भर्ती नियम निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, इस अध्याय में सबसे निचले ग्रेड अर्थात् लेवल-1 (ग्रेड वेतन रु.1800) में कार्यरत कर्मिकों के लिए पदोन्नति के रास्तों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, नई भर्तियों के पास कैरियर में प्रगति के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा(GDCE)/ सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE) में बैठने का अवसर है। सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसर को विस्तृत किया गया है ताकि इसमें वैसे पदों की सभी कोटियों को सम्मिलित किया जा सके, जिनका सीधी भर्ती कोटा 25% और उससे अधिक है। निचले ग्रेडों में कार्यरत युवा, प्रतिभावान एवं योग्यताप्राप्त कर्मिक उच्चतर ग्रेडों में तेजी से प्रगति करने के लिए LDCE और GDCE का रास्ता चुन सकते हैं। GDCE योजना को जारी रखने के लिए इसे समय-समय पर विस्तार दिया जाता रहा है और अंतिम बार इसे दिनांक 31/03/2020 तक बढ़ाया गया है।

इसी तरह, रेलवे में विभिन्न पदों के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में LDCE में बैठने का अवसर उपलब्ध कराया गया है, जिनमें प्रमुख हैं- योग्यताप्राप्त कोटा में तकनीशियन, ग्रेड-III/लेवल-2 का पद, 16-2/3% विभागीय कोटा के लिए लेवल-2 में वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक, गाड़ी लिपिक, कार्यालय लिपिक, भंडार लिपिक इत्यादि के पद, 20% कोटा के अंतर्गत लेवल-7 में मुख्य कर्मिक एवं कल्याण निरीक्षक, लेवल-6 में कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हेतु इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा आदि। LDCE/GDCE में सम्मिलित होने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना है जैसे- वर्तमान अनुदेशों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और निवास इत्यादि।

पदोन्नति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन नीचे किया गया है :

- पदोन्नति में निचले ग्रेड से उच्चतर ग्रेड में, एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में और एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण शामिल है। एक रेल सेवक को किसी भी पद को भरने के लिए चाहे वह चयन पद हो अथवा गैर-चयन पद, पदोन्नत किया जा सकता है यदि उसे उस पद से संबंधित कार्यों के निर्वहन के लिए योग्य समझा जाता है।
- पदों की केवल दो कोटियाँ रहेंगी – ‘चयन पद’ और ‘गैर-चयन पद’। ‘चयन पद’ वे पद, ग्रेड अथवा श्रेणियाँ हैं जिनकी अधिसूचना रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से यह मान कर जारी की गई है कि उनकी पदोन्नति चयन बोर्ड की सहायता से इस उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सकारात्मक चयन प्रक्रिया अपनाकर चयन हेतु पात्र कार्मिकों के बीच से की जानी अपेक्षित है। ‘चयन पद’ पर पदोन्नति के लिए पदों को भरने के तरीके अपनाकर या तो योग्यता और वरिष्ठता, दोनों के आधार पर अथवा केवल योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा।
- वैसे कर्मचारियों को, जो स्पष्ट रूप से अथवा अन्य तरीके से पदोन्नति लेने से इंकार करते हैं (अर्थात् न तो वह पदोन्नति लेने से इन्कार की सूचना लिखित रूप में देता है और न ही जिस पद के लिए उसका चयन हुआ है उसपर अपना योगदान देता है), भविष्य में एक वर्ष के लिए पदोन्नति लेने से रोक दिया जाएगा।
[भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I का पैरा 224]
- जहां किसी संवर्ग के किसी ग्रेड में अगली पदोन्नति हेतु कोई पदोन्नति पाठ्यक्रम पूर्वनिर्धारित हो वहां उस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने से छूट नहीं दी जाए। यदि कर्मचारियों को पदोन्नति पाठ्यक्रम के लिए बुक किया जाता है, तब उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।
[भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I का पैरा 227]

कुछ महत्वपूर्ण लोकप्रिय कोटियों में पदोन्नति के मानक अवसर (AVC)

(क) समूह ‘ग’, लेवल -1/ग्रेड वेतन रु.1800 (इससे पहले समूह ‘घ’) :

- 1) समूह ‘घ’ कोटियों के जिन रेल सेवकों के लिए नियमित पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, उनकी पदोन्नति के लिए वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक, गाड़ी लिपिक, कार्यालय लिपिक, भंडार लिपिक इत्यादि के निचले ग्रेडों में 33-1/3% एवं 16-2/3% पद (निर्धारित योग्यता के साथ) चिह्नित किए जाने चाहिए।
- 2) इंजीनियरी के सभी विभागों सहित कारखानों में हेल्परों की कोटि के लिए कारीगर संवर्ग के अधीन तकनीशियन कोटि में और आगे तकनीकी पर्यवेक्षक संवर्ग के कनिष्ठ इंजीनियर तथा वरिष्ठ इंजीनियर की कोटि में पदोन्नति के अवसर हैं।
- 3) परिवहन और वाणिज्य विभागों में कार्यरत निचले ग्रेड के सभी रेल सेवकों को परिवहन और वाणिज्य, दोनों शाखाओं के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नत किए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र समझा जाए।
- 4) लेवल-1/ग्रेड वेतन रु. 1800/- में 7 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों की कोटि को, जिनके पास इनमें से कोई एक योग्यता हो अर्थात् जिन्होंने श्रम/सामाजिक कल्याण में डिप्लोमा अथवा श्रम कानून में डिप्लोमा अथवा श्रम कानून में पेपर के साथ एलएलबी, कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्मिक प्रबंधन में पेपर के साथ एमबीए किया हो, वे कार्मिक एवं कल्याण निरीक्षक, लेवल-6/ग्रेड वेतन रु.4200/- के लिए पात्र हैं।
- 5) सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा(GDCE) के अंतर्गत अधिसूचित किसी उच्चतर पद के लिए, यदि उस पद के लिए अपेक्षित निर्धारित योग्यता रखता हो, जिसके लिए रेलवे भर्ती कक्ष से अधिसूचना जारी की जाती है।

(ख) गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां ((NTPC) : लेवल-2 एवं 3 /ग्रेड वेतन रु.1900/- एवं रु.2000/- में :

- 1) संवर्ग में ही उच्चतर ग्रेड के लिए पदोन्नति के सामान्य अवसर के अनुसार
- 2) सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा(GDCE) के अंतर्गत अधिसूचित किसी उच्चतर पद के लिए, यदि उस पद के लिए अपेक्षित निर्धारित योग्यता रखता हो, जिसके लिए रेलवे भर्ती कक्ष से अधिसूचना जारी की जाती है।
- 3) कार्मिक एवं कल्याण निरीक्षक के पद के लिए, यदि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो।
- 4) विधि संवर्ग में मुख्य विधि सहायक के पद के लिए, यदि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो।

(ग) कारीगर संवर्ग में तकनीशियन के रूप में : लेवल -2/ ग्रेड वेतन रु.1900

- 1) संवर्ग में ही उच्चतर ग्रेड के लिए पदोन्नति के सामान्य अवसर के अनुसार
- 2) बाद में लेवल-1 में सहायक लोको पायलट के रूप में प्रवेश Lateral induction as ALP in Level-1
- 3) कार्मिक एवं कल्याण निरीक्षक के पद के लिए, यदि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो।
- 4) विधि संवर्ग में मुख्य विधि सहायक के पद के लिए, यदि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो।
- 5) सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा(GDCE) के अंतर्गत अधिसूचित किसी उच्चतर पद के लिए, यदि उस पद के लिए अपेक्षित निर्धारित योग्यता रखता हो, जिसके लिए रेलवे भर्ती कक्ष से अधिसूचना जारी की जाती है।
- 6) लेवल-6/ग्रेड वेतन रु.4200/- में कनिष्ठ इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हेतु इंटर-अप्रेंटिस कोटा के लिए, यदि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो।

(घ) तकनीकी पर्यवेक्षक संवर्ग : लेवल-6/ग्रेड वेतन रु.4200/- में

- 1) लेवल-7/ग्रेड वेतन रु.4600/- में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए, संवर्ग में ही पदोन्नति के सामान्य अवसर के अनुसार
- 2) ग्रुप 'बी' पद के लिए, यदि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो।
- 3) सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा(GDCE) के अंतर्गत अधिसूचित किसी उच्चतर पद के लिए, यदि उस पद के लिए अपेक्षित निर्धारित योग्यता रखता हो, जिसके लिए रेलवे भर्ती कक्ष से अधिसूचना जारी की जाती है।

➤ वरिष्ठता क्रम को शासित करने वाले नियम :

रेलवे भर्ती बोर्ड अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों की वरिष्ठता पर निम्नानुसार विचार किया जाए :

- 1) जिन उम्मीदवारों को आरंभिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण विद्यालयों में भेजा जाता है उन्हें कार्य के पद पर पदस्थापित किए जाने से पहले प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता क्रम से संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता क्रम दिया जाएगा। जो पश्चवर्ती पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और जो बाद की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवारों से नीचे वरिष्ठता क्रम दिया जाएगा।
- 2) वैसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्हें प्रशिक्षण विद्यालय में कोई प्रशिक्षण नहीं लेना है, वरिष्ठता क्रम का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा दिए गए वरिष्ठता क्रम के आधार पर किया जाए।
- 3) जब दो या अधिक उम्मीदवारों को एक और समान परीक्षा/चयन प्रक्रिया में समान रूप से योग्य घोषित किया जाता है, तब उनके बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण जन्म-तिथि के द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिक आयु वाला उम्मीदवार वरिष्ठ माना जाएगा।
- 4) तथापि, जब कोई उम्मीदवार, जिसकी वरिष्ठता उपर्युक्त पैराग्राफ (1) और (2) के अनुसार निर्धारित की जानी है, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद अपेक्षित समय के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर

सकता है, तब नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी उसी परीक्षा/चयन प्रक्रिया में चयन किए गए उन सभी उम्मीदवारों के नीचे रखते हुए, जिन्होंने ड्यूटी पर उपस्थित होने की सूचना देने के लिए स्वीकृत समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है अथवा पश्चवर्ती परीक्षा/चयन प्रक्रिया में चयन किए गए उन उम्मीदवारों से भी नीचे, जिन्होंने उनसे पहले अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उसकी वरिष्ठता निर्धारित कर सकता है।

- 5) किसी पूर्ववर्ती चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवार बाद में चयनित उम्मीदवारों से वरिष्ठ होंगे, चाहे पदस्थापन की तिथि जो भी हो किन्तु उपर्युक्त पैराग्राफ (4) के अंतर्गत आने वाले मामले को छोड़कर।
- 6) परस्पर सहमति के आधार पर एक मंडल, कार्यालय अथवा रेलवे के एक संवर्ग से अन्य मंडल, कार्यालय अथवा रेलवे के समान संवर्ग में स्थानांतरित रेल सेवकों की ग्रेड में पदोन्नति की तिथि के आधार पर वरिष्ठता यथावत बनी रहेगी अथवा उन्हें उन रेल सेवकों की वरिष्ठता प्राप्त होगी, जिनके साथ उन्होंने परस्पर समझौता किया है, किन्तु इन दोनों में जो भी निचला हो।
- 7) प्रशासन के हित में एक संवर्ग से दूसरे में स्थानांतरित रेल सेवकों की वरिष्ठता को, स्थिति के अनुसार, ग्रेड में पदोन्नति की तिथि/ नियुक्ति की तिथि से विनियमित किया जाएगा।
- 8) निजी अनुरोध पर एक रेलवे से दूसरे रेलवे में स्थानांतरित रेल सेवकों को नए प्रतिष्ठान के पदोन्नति वाले समूह में संबंधित ग्रेड में उस समय पुष्टि प्राप्त, अस्थायी और स्थापनापन रेल सेवकों के नीचे वरिष्ठता क्रम आबंटित किया जाएगा, इसमें चाहे स्थानांतरित रेल सेवकों द्वारा पुष्टि-प्राप्ति की तिथि अथवा स्थापनापन या अस्थायी सेवा की अवधि जो हो। यह समान रेलवे के एक संवर्ग/मंडल से अन्य संवर्ग/मंडल में अनुरोध पर स्थानांतरण के मामलों में भी लागू होता है।
- 9) रेल सेवकों को उस वरिष्ठता सूची को देखने की अनुमति दी जाए जिसमें उनके नाम दर्ज हैं अथवा यदि आसानी से इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती हो तब उनके अनुरोध पर वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति की जानकारी दी जा सकती है। संबंधित कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची के प्रकाशन से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी वरिष्ठता स्थिति जानने के लिए अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जा सकती है। यह अवधि बीतने के बाद वरिष्ठता सूची में संशोधन से संबंधित किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाए।

अध्याय – 6

वेतन एवं भत्ते

➤ वेतन एवं भत्ते:

वर्तमान नियमों में विशेष रूप से वर्णित किन्हीं अपवादों को छोड़कर, रेल सेवक को उस तारीख से अपने पद की अवधि के लिए वेतन और भत्ते मिलना आरंभ हो जाएगा, जिस तारीख को उसने पद पर अपना योगदान दिया है जिस तारीख से वह उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना बंद करता है, उसी तारीख से उसे ये सब मिलना बंद हो जाएगा।

परन्तु जो अधिकारी बिना किसी प्राधिकार के अपनी झूठी पर अनुपस्थित रहता है, वह अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए कोई वेतन या भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा।

➤ वेतन और भत्ते की गणना करने की तारीख :

(1) सरकारी कर्मचारी जिस तारीख को किसी पद का कार्यभार ग्रहण करता है, यदि कार्यभार उस तारीख के पूर्वाह्न में हस्तांतरित किया जाता है, तो उसे उस पद पर अपने सेवाकाल से सम्बद्ध वेतन और भत्ते उसी तारीख से मिलना आरंभ हो जाएगा। यदि कार्यभार अपराह्न में हस्तांतरित किया जाता है तो उसे वेतन और भत्ते अगले दिन से मिलने शुरू होंगे। तथापि, वैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता है, जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी को किसी दिन के केवल उसी भाग के लिए उच्चतर दर पर भुगतान करने की जानी-पहचानी परिपाटी हो, जब उसने अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

(2) किस तारीख को विदेश में भर्ती हुए व्यक्ति को उसकी प्रथम नियुक्ति पर वेतन प्राप्त होना आरंभ होगा इसका निर्धारण उस प्राधिकारी के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा होगा, जिसने उसकी नियुक्ति की है।

➤ आरंभिक नियुक्ति पर वेतन की संरचना एवं वार्षिक वेतनवृद्धि :

मूल वेतन का निर्धारण आरंभिक नियुक्ति के लेवल (अर्थात् लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3, लेवल-5, लेवल-6, लेवल-7) के आधार पर, समय-समय पर लागू महंगाई भत्ता, पदस्थापन स्थान के आधार पर मकान किराया भत्ता (मूल वेतन का 24%/16%/8%) और पदस्थापन स्थान के आधार पर परिवहन भत्ता के अनुसार किया जाता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्य भत्ते भी हैं, जिनका भुगतान कार्यों तथा स्वीकार्यता के आधार पर वर्तमान नियमों के अनुसार किया जा सकता है। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई वेतन मैट्रिक्स, जो आरएस(आरपी) नियम, 2016 के तहत अधिसूचित है, अनुलग्नक -बी के रूप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति हेतु दो तिथियाँ अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई को निर्धारित हैं। किन्तु कर्मचारी अपनी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय अप-ग्रेडेशन के आधार पर 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को केवल एक वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

➤ प्रशिक्षण अवधि की गणना के लिए लाभ :

उन अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रशिक्षण अवधि को, जिनके लिए नियमित रोजगार पर रखे जाने से पहले पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है, नीचे वर्णित उद्देश्यों के लिए अर्हक सेवा माना जाता है :

क) वेतन वृद्धि का आहरण।

ख) पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों के उद्देश्य से।

ग) पासों की श्रेणी/स्तर की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से।

घ) विभागीय पदोन्नति सहित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पदोन्नति के लिए।

➤ निलम्बन के दौरान वेतन:

सक्षम प्राधिकारी के आदेश से निलम्बित या निलम्बन के अंतर्गत माना गया रेल सेवक निम्नलिखित भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात् -

- (1) (क) उस छुट्टी वेतन के बराबर रकम का निर्वाह भत्ता, जो रेल सेवक तब लेता, जब वह अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी या अर्द्ध औसत वेतन पर होता और इसके अतिरिक्त उस छुट्टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, यदि अनुमेय हो।

परन्तु जहां निलम्बन की अवधि तीन माह से अधिक हो, वहां जिस प्राधिकारी निलम्बन आदेश दिया है अथवा जिसके बारे में यह मान लिया गया हो कि उसने निलम्बन आदेश दिया है, वह प्रथम तीन माह की अवधि के बाद की किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा:

- (i) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि, जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसे कारणों से हुई है, जिसके लिए सीधे रेल सेवक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, तब निर्वाह भत्ते की रकम को यथोचित रकम तक बढ़ाया जा सकता है, किन्तु यह प्रथम तीन माह की अवधि के दौरान अनुमेय निर्वाह भत्ता के 50% से अधिक नहीं हो।
- (ii) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि, जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसे कारणों से हुई है, जिसके लिए सीधे रेल सेवक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तब निर्वाह भत्ते की रकम को यथोचित रकम तक घटाया जा सकता है, किन्तु यह प्रथम तीन माह की अवधि के दौरान अनुमेय निर्वाह भत्ता के 50% से अधिक नहीं हो।
- (iii) महंगाई भत्ता की दर, ऊपर उपखंड (i) तथा (ii) के अधीन अनुमेय यथास्थिति बढ़ाए अथवा घटाए गए निर्वाह भत्ते के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(ख) निलम्बन की तारीख को रेल सेवक को जितना वेतन प्राप्त हो रहा था उसके आधार पर समय-समय पर अनुमेय कोई अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता, बशर्ते कि वह ऐसे भत्ते प्राप्त करने के लिए उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करता हो।

- (2) उप नियम (i) के अधीन कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि रेल सेवक किसी अन्य नियोजन, कारोबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है, इस आशय का प्रमाणपत्र जमा नहीं कर दे।

➤ **भत्ते :** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुमेय भत्तों एवं प्राधिकार का ब्यौरा अनुलग्नक - ग के रूप में संलग्न है।

अध्याय – 7

सुविधाएं एवं लाभ

➤ आयु सीमा में छूट:

समूह 'ग' और समूह 'घ' की सभी रिक्तियों पर सीधी भर्ती के लिए उन सेवारत कर्मचारियों को, जिन्होंने रेलों में तीन वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, ऊपरी आयु सीमा में सामान्य कोटि के उम्मीदवार होने पर 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार होने पर 43 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार होने पर 45 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। जिन एवजियों ने लगातार अथवा खंडित अवधियों में तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, उनपर भी आयु सीमा की यही छूट लागू होगी।

- 1) सभी समूह 'ग' और 'घ' पदों में सीधी भर्ती के लिए विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं, जिनकी दोबारा शादी नहीं हुई है, के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.जा.) के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 38 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.जा./ज.जा.) उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- 2) यदि कोई उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी रोजगार सूचना में विनिर्दिष्ट किसी तारीख विशेष को न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमाओं के भीतर आता हो, तो उसे संबंधित रेलवे में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाए, चाहे क्यों न उस व्यक्ति ने किसी नियुक्ति में वास्तविक रूप से योगदान देने की तारीख को अधिकतम आयु सीमा पार कर ली हो।
- 3) जिन रेल कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है अथवा जो चिकित्सा की दृष्टि से अक्षम घोषित कर दिए गए हैं, उनके पुत्रों, पुत्रियों, पत्नियों, आश्रितों आदि की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करते समय ऊपरी आयु सीमा में अपेक्षित तथा औचित्यपूर्ण छूट दी जा सकती है। महाप्रबंधक भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों की खेल-कूद कोटा तथा सांस्कृतिक/स्काउट/गाइड कोटा में नियुक्ति करते समय आयु सीमा में छूट दे सकते हैं।

➤ संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) के अंतर्गत वित्तीय अप-ग्रेडेशन:

- (1) वार्षिक कैरियर प्रगति (एसीपी) योजना/1997 के स्थान पर संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) की शुरुआत दिनांक 01.09.2008 से की गई जिसका उद्देश्य गतिरोध को कम करना था।
- (2) संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय अप-ग्रेडेशन दिए जाएंगे और इनकी गणना सीधी भर्ती ग्रेड में क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्षों की सेवा पूरी होने के समय से की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अप-ग्रेडेशन तभी दिया जाएगा जब कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों तक एक ही ग्रेड वेतन/लेवल में रहा हो।
- (3) इस योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय अप-ग्रेडेशन के समय नियमित पदोन्नति पर दिया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ भी दिया जाएगा। इस अप-ग्रेडेशन से पहले के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन पर मिल रहे कुल वेतन में 3% की वृद्धि करके वेतन निर्धारित किया जाएगा।
- (4) तथापि, नियमित पदोन्नति के समय पुनः वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा यदि यह संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के तहत स्वीकृत ग्रेड वेतन के बराबर हो। यदि वास्तविक पदोन्नति के समय पाया जाता है कि संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के तहत दिए गए ग्रेड वेतन की अपेक्षा यह उच्चतर ग्रेड वेतन वाला पद है तब कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और केवल ग्रेड वेतन के अंतर का लाभ दिया जाएगा।
- (5) संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के उद्देश्यों के लिए 'नियमित सेवा' का प्रारंभ सीधी भर्ती अथवा आमेलन/पुनर्नियोजन द्वारा सीधी भर्ती ग्रेड के पद पर नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से

माना जाएगा। नियुक्ति-पूर्व प्रशिक्षण के आधार पर नियमित नियुक्ति किए जाने से पहले तदर्थ/ठेका के आधार पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी।

- (6) किसी नए विभाग में नियमित नियुक्ति से पहले समान ग्रेड वेतन वाले किसी पद पर अन्य सरकारी विभाग में विगत में की गई बिना ब्रेक लगातार नियमित सेवा को भी केवल संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के उद्देश्यों के लिए (और नियमित पदोन्नतियों के लिए नहीं) अर्हक नियमित सेवा के रूप में गणना की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के तहत मिलने वाले लाभ पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नए पद पर परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद ढंग से पूरी नहीं कर ली जाती है।

➤ **स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता हेतु पात्रता :**

स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता में 4 तत्व शामिल हैं :-

क) स्वयं तथा परिवार के यात्रा करने के लिए पात्रता।

ख) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने की स्थिति में, जिसकी दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो, मूल वेतन के 80% की दर से समग्र स्थानांतरण एवं पैकिंग अनुदान। वैसे स्थानों में स्थानांतरण होने पर, जिसकी दूरी पुराने स्थान से 20 कि.मी. से कम हो और यदि उसी शहर की सीमा में स्थानांतरण किया गया हो, तो समग्र स्थानांतरण अनुदान का एक तिहाई अनुमेय होगा, बशर्ते कि आवास परिवर्तन वास्तव में किया गया हो।

ग) व्यक्तिगत खर्च पर परिवहन के लिए निर्धारित दरों पर प्रभारों की प्रतिपूर्ति और

घ) वाहन के परिवहन पर लगे प्रभार की प्रतिपूर्ति।

➤ **कार्यग्रहण अवधि :**

- (1) किसी रेल सेवक का जनहित में स्थानांतरण किए जाने की स्थिति में उसे कार्यग्रहण करने के लिए समय दिया जाएगा जिससे वह या तो उसी स्थान पर या किसी नए स्थान पर नये पद का कार्यभार ग्रहण कर सके।
- (2) अधिकतम 180 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई अवधि अनुमेय नहीं है। दौरे पर यात्रा करने की स्थिति में, केवल यात्रा करने की वास्तविक अवधि मंजूर की जाएगी।
- (3) वैसे मामलों में, जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण शामिल हो और इसमें आवास बदलना भी शामिल हो, रेल सेवक को पुराने मुख्यालय और नए मुख्यालय के बीच 1000 कि.मी. और उससे कम, 1000 कि.मी. से अधिक एवं 2000 कि.मी. से अधिक दूरी होने पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए क्रमशः 10 दिनों, 12 दिनों एवं 15 दिनों की अवधि मंजूर की जाएगी।
- (4) यदि रेल कर्मचारी को उसी स्थान की सीमा में किसी नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना हो अथवा उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवास बदलना शामिल नहीं हो तो उसे कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक दिन से अधिक अवधि मंजूर नहीं की जाएगी।

➤ **चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार नियमों के अधीन लाभ :**

- (1) चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार की सुविधाएं सभी रेल कर्मचारियों, उनके परिवारजनों एवं आश्रित संबंधियों को (जैसा पास नियमों के अंतर्गत परिभाषित है) भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली में उल्लिखित विस्तृत नियमों के अनुसार निःशुल्क उपलब्ध होगी, चाहे कर्मचारी किसी समूह 'क', 'ख', 'ग' या 'घ' के तथा स्थायी या अस्थायी हों।

- (2) शिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा शासित शिक्षुओं से भिन्न अन्य सभी शिक्षुओं का केवल स्वयं उन्हें, परिवारजनों को नहीं, निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार की सुविधाएं उसी पैमाने पर ग्राह्य होंगी, जैसी रेल कर्मचारियों को उपलब्ध होती हैं, परन्तु ये रेल चिकित्सालयों व स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं तक सीमित होंगी।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा शासित प्रशिक्षुओं को छोड़कर सभी प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार सुविधाएं अनुमेय होंगी, किन्तु उनके परिवार के सदस्यों को नहीं, जैसा कि रेल कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान में उपलब्ध है, किन्तु रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य इकाइयों में यथा उपलब्ध केवल वर्तमान सुविधाओं तक सीमित रहेंगी।

- (3) जिन कोटियों के लिए वे प्रशिक्षु हैं, उन्हें चिकित्सा परिचर्या व उपचार के प्रयोजन हेतु उन्हीं कोटियों में वर्गीकृत किया जाए।
- (4) आहार प्रभार की वसूली हेतु, उन्हें मिलने वाली वृत्ति को वेतन माना जाना चाहिए। गैर-रेलवे संस्थानों अथवा क्षय रोग संस्थानों में, जहां रेल कर्मचारियों के लिए शय्याएं आरक्षित हैं, क्षतिपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- (5) सभी प्रशिक्षुओं सहित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 द्वारा शासित प्रशिक्षुओं को, यदि प्रशिक्षण के कारण और प्रशिक्षु का प्रशिक्षण लेने के दौरान घटित किसी दुर्घटना में व्यक्तिगत चोट पहुंचती है तब उनका निःशुल्क चिकित्सा उपचार किया जाए।

- (6) रेलवे चिकित्सा लाभार्थियों के संबंध में भोजन प्रभार हेतु मापदण्ड को प्र.मुकाधि के परिपत्र सं. 121/2018 के तहत परिपत्रित अनुदेशों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

➤ **यूएमआईडी (उमीद)** – पैन इण्डिया रेलवे के आधार पर समरूप चिकित्सा कार्ड तैयार करने के लिए द.म. रेलवे द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके लिए सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने एवं आश्रितों के व्यौरे ऑनलाइन अपलोड करें।

➤ **छुट्टी नियमों के अंतर्गत लाभ :**

- (1) रेल कारखानों के शिक्षु मेकनिकों के लिए शिक्षुता के किसी वर्ष में पूरे वेतन के साथ अधिकतम 16 दिनों की और चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर आधे वेतन के साथ अधिकतम 20 दिनों की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।
- (2) अन्य सभी विभागों में समूह 'ग' के पदों जैसे शिक्षु रेलगाड़ी परीक्षक, शिक्षु रेल पथ निरीक्षक, भंडार शिक्षु आदि के लिए प्रशिक्षणाधीन शिक्षुओं को, जिन्हें प्रशिक्षण के पश्चात् पर्यवेक्षण पदों पर पदस्थापित किया जाता है, शिक्षु मेकनिकों की भांति छुट्टी मंजूर की जा सकती है।
- (3) व्यवसाय शिक्षुओं को शिक्षुता के किसी भी वर्ष में पूरे वेतन के साथ अधिकतम 12 दिनों की और चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर आधे वेतन के साथ अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी मंजूर की जा सकती है।
- (4) सभी मामलों में, छुट्टी गैर-संचयी होगी और इससे प्रशिक्षण में रुकावट पड़ेगी तो कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।
- (5) सेवा में किसी व्यवधान के बिना पश्चवर्ती आमेसन पर यदि शिक्षु या परिवीक्षाधीन के रूप में प्रशिक्षण की अवधि को सेवा मान लिया जाता है, तो छुट्टी की उसी प्रकार पुनः गणना करने की अनुमति दी जाएगी जैसे नियमों को सामान्य रूप से लागू करने के लिए अनुमेय है।
- (6) किसी रेलवे विद्यालय में सेवारत रेल सेवक से भिन्न कोई स्थायी या अस्थायी रेल सेवक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों का औसत वेतन अवकाश पाने का हकदार है।
- (7) किसी रेलवे स्कूल में कार्यरत रेल कर्मचारी सहित स्थायी अथवा अस्थायी रेल सेवक, अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण कर लिए गए वर्ष के लिए 20 दिनों का अर्द्ध औसत वेतन अवकाश पाने का हकदार होगा।

- (8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी महिला रेल सेवक (शिशु सहित) के लिए, जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, 180 दिनों का मातृत्व अवकाश, इसके शुरु होने की तारीख से, स्वीकृत किया जा सकता है।
- (9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पुरुष रेल सेवक (शिशु सहित) के लिए, जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिनों की, अर्थात् बच्चे के जन्म की तारीख से 15 दिन पहले और बच्चा जन्म लेने की तारीख से छः महीने के भीतर पितृत्व अवकाश स्वीकृति किया जा सकता है।
- (10) बच्चा गोद लेने वाली रेलकर्मि माताओं के लिए , जिनकी दो से कम जीवित संतान हो, एक वर्ष की आयु तक का शिशु गोद लेने पर, नैसर्गिक माताओं के लिए स्वीकार्य मातृत्व अवकाश की तरह, 180 दिनों की 'बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी' स्वीकृत की जा सकती है।
- (11) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैसी महिला रेल सेवक एवं एकल पुरुष रेल सेवक (अर्थात् अविवाहित अथवा विधुर अथवा तलाकशुदा रेल सेवक) के लिए, जिसके 18 साल से कम आयु के (अशक्त बच्चे होने पर 22 वर्ष की आयु तक) छोटे बच्चे हैं, पूरे सेवाकाल के दौरान दो बच्चों की देखभाल करने, चाहे यह परीक्षा , बीमारी इत्यादि जैसी जरूरतों के दौरान उनके साथ रहने अथवा देखभाल करने के लिए हो, न्यूनतम 5 दिनों की तथा अधिकतम दो वर्षों (अर्थात् 730 दिन) की अवधि के लिए शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है।
- (12) कार्य से जुड़ी अथवा उस दौरान हुई बीमारी एवं लगी चोट के लिए अवकाश (WRIL): कार्यालय की स्थिति /कार्यालय के कार्य करने के परिणामस्वरूप /के कारण हुई बीमारी अथवा लगी चोट के लिए, अस्पताल में भर्ती रहने की सम्पूर्ण अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ता।
- (13) वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा उसी तरह की समस्याओं का अध्ययन करने अथवा विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए अध्ययन अवकाश। इस अवकाश की छुट्टी खाता से कटौती नहीं की जाती है।
- (14) सेवा में रहने के दौरान रेलवे पास के साथ 10 दिनों के औसत वेतन अवकाश का नकदीकरण।

➤ **पास नियमों के अंतर्गत लाभ:**

- (1) रेल सेवा का 5वाँ वर्ष समाप्त होने तक प्रति वर्ष 1 सेट पास और रेल सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के बाद इसके 3 सेट । इसके अलावा, प्रति वर्ष 4 सेट सुविधा टिकट आदेश (PTOs) प्राप्त करने की अनुमति है।
- (2) रेल कर्मचारियों के बच्चों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रथम बार लिखित परीक्षा/मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर शयनयान/II श्रेणी में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा।
- (3) तथापि, रेलवे में किसी पद को भरे जाने के उद्देश्य से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए किसी रेल सेवक के लिए, जिसपर वह नियोजित है, एक झूटी पास जारी किया जा सकता है। छुट्टी का उपभोग कर रहे कर्मिकों को चयन प्रक्रिया द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए गठित चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर उनको निःशुल्क पास दी जानी है। यात्रा करने और चयन स्थान पर ठहरने की अवधि को झूटी नहीं समझा जाएगा।
- (4) जब कोई रेल सेवक क्षेत्रीय रेल, जहाँ वह कार्यरत है, से बाहर जाकर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, तब वैसे मामलों में उसे रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञताप्राप्त चिकित्सा के लिए अन्य स्थान पर अवस्थित अस्पताल में भेजा जाता है तब जिस स्थान से उसे भेजा जाता है, उस स्थान से अस्पताल/औषधालय की अवस्थिति वाले स्थान तक और वहाँ से उसी स्थान पर वापसी के लिए विशेष पास जारी किया जा सकता है।
- (5) प्रशिक्षणार्थी अथवा प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त और वृत्तिका पाने वाले व्यक्ति केवल स्वयं के लिए पास लेने के हकदार होंगे।

➤ रनिंग कर्मचारियों के लिए लाभ :

- (1) रनिंग कर्मचारी, जैसे- सहायक लोको पायलट/लोको पायलट/गार्ड/शंटर, गाड़ी संचालन के प्रभार से सीधे जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित दरों पर रनिंग भत्ते पाने के हकदार हैं और इसमें “किलोमीटर भत्ता” और “किलोमीटर के बदले भत्ता” शामिल है किन्तु इसमें क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल नहीं है।
- (2) रनिंग कर्मचारी के मूल वेतन के 30% को वेतन के रूप में माना जाएगा, जो रनिंग भत्ता में वेतन तत्व को दर्शाता है।
- (3) रनिंग कर्मचारी रनिंग छुट्टी करने के लिए किलोमीटर भत्ता पाने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, वे विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते, जैसे- (i) रनिंग रूम सुविधाओं के लिए भत्ता, (ii) विश्राम में व्यवधान भत्ता, (iii) आउटस्टेशन (डिटेंशन) भत्ता, (iv) आउटस्टेशन (कार्यमुक्ति) भत्ता, (v) दुर्घटना भत्ता और (vi) कोई स्थानापन्न भत्ता पाने के हकदार हैं, यदि रनिंग कर्मचारियों के लिए छूट प्राप्त पदों के उच्चतर ग्रेडों अथवा किसी स्थिर नियुक्ति के कार्य संभाल रहे हों।
- (4) रनिंग कर्मचारी के मूल वेतन के 30% को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा :
 - (क) पास और पी.टी.ओ. का हकदार
 - (ख) चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार
 - (ग) शैक्षणिक सहायता
 - (घ) स्थिर पदों में वेतन का निर्धारण
 - (ङ) क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ता,
 - (च) मकान किराया भत्ता
 - (छ) आवास के लिए हकदार .
 - (ज) आवास के लिए किराया की वसूली.
 - (झ) महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता
 - (ञ) समयोपरि भत्ता
 - (ट) छुट्टी वेतन
- (5) यदि रनिंग कर्मचारी दिनांक 1-4-1979 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ/हो रहा हो तब सेवानिवृत्ति लाभ के उद्देश्यों के लिए उसके मूल वेतन को इसमें जोड़ा जाएगा। मूल वेतन के 55% को भी भविष्य निधि में अंशदान की वसूली करने के उद्देश्य से जोड़ा जाएगा।
- (6) जब रनिंग कर्मचारी अवकाश पर हों (आकस्मिक छुट्टी सहित) तब उनको उनके मूल वेतन और उसके 30% के बराबर छुट्टी वेतन तथा उस मूल वेतन पर देय अन्य भत्तों सहित महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
- (7) वित्त वर्ष 1982-83 (आकलन वर्ष 1983-84) से आयकर की कटौती के लिए , रनिंग कर्मचारी द्वारा अर्जित वास्तविक रनिंग भत्ता के 30% की गणना वेतन के रूप में की जाएगी और शेष 70% रनिंग भत्ता को आयकर अधिनियम, 1951 की धारा 10(14) के अधीन आयकर से छूट दिया जाएगा।

➤ रेलवे आवासों के आबंटन हेतु पात्रता :

क्रम सं.	7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल	आवासों के लिए पात्रता
1.	कर्मचारी, जिनका ग्रेड वेतन रु.1800 (लेवल-1) के बराबर अथवा कम है।	टाइप –I
2.	कर्मचारी, जिनका ग्रेड वेतन रु.1800 (लेवल-1) से अधिक और 2400 (लेवल-4) तक है।	टाइप – II
3.	कर्मचारी, जिनका ग्रेड वेतन रु.2400 (लेवल-4) से अधिक और 4200 (लेवल-6) तक है।	टाइप –III
4.	कर्मचारी, जिनका ग्रेड वेतन रु. 4200 (लेवल-6) से अधिक है।	टाइप –IV

5.	राजपत्रित अधिकारी, जिनका ग्रेड वेतन रु.6600 (लेवल-11) से कम है।	टाइप -IV
6.	राजपत्रित अधिकारी, जिनका ग्रेड वेतन रु.6600 (लेवल-11) है।	टाइप -IV स्पेशल
7.	राजपत्रित अधिकारी, जिनका ग्रेड वेतन रु.6600 (लेवल-11) से अधिक है।	टाइप -V

➤ **अन्य लाभ :**

- (1) प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षु/प्रशिक्षणार्थी समय-समय पर निर्धारित होने वाली दर पर वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे।
- (2) स्थायी और अस्थायी रेल सेवकों को, जो बाहरी व्यक्तियों पर लागू शिक्षु/प्रशिक्षणार्थी की विभिन्न कोटियों में भर्ती के नियम एवं शर्तों को पूरा करते हैं, बाहरी व्यक्तियों के साथ ही शिक्षु/प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता में बैठने की अनुमति दी जा सकती है और उन्हें शिक्षुओं की उस कोटि विशेष के लिए उल्लिखित वृत्ति की दर अथवा समय-समय पर अनुमेय उनके मूल वेतन के बराबर, जो भी अधिक हो, वेतन की स्वीकृति दी जा सकती है। शिक्षुओं के रूप में नियुक्त स्थायी और अस्थायी, दोनों तरह के रेल सेवकों के लिए भी उनके शिक्षु रहने की अवधि में शिक्षु के रूप में उनके वेतन के आधार पर मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाएगा।
- (3) शिक्षु मेकनिकों को उस कोटि में लागू यात्रा भत्ता की स्वीकृति दी जा सकती है, जिसमें वे अपने-अपने प्रशिक्षण के दौरान अपनी अनुपस्थिति की अवधि में शिक्षु हैं किन्तु उनके लिए अपनी यात्रा प्रशिक्षण के भाग के रूप में करनी जरूरी है और निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं दी गई है।
- (4) शिक्षुओं को शिक्षु/प्रशिक्षण अवधि पूरी होने की तिथि के बाद के कार्यदिवस को उपलब्ध पदों पर समायोजित किया जाए। शिक्षुओं का उपलब्ध पद पर समायोजन करने के लिए उपयुक्तता जांच शिक्षु/प्रशिक्षण अवधि पूरी होने से पर्याप्त पहले कर ली जाए। यदि परीक्षा अयोजित करने उत्तर पुस्तका का मूल्यांकन करने, कार्यालय आदेश जारी करने इत्यादि में प्रशासनिक कारणों से विलंब होती है तो शिक्षु प्रशिक्षणार्थी पूरी होने की तिथि के बीच की अवधि को प्रशिक्षण/शिक्षु की बढ़ाई गई अवधि माना जाएगा और शिक्षुओं को उसके लिए वृत्ति का भुगतान किया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी शिक्षु को पूर्व प्रभाव से किसी उपलब्ध पद पर समायोजित नहीं किया जाए।
- (5) बशर्ते कि उसके सेवा करार में अन्यथा उल्लिखित न हो, रेलवे प्रशासन द्वारा एक सप्ताह की सूचना पर शिक्षुता को समाप्त किया जा सकेगा। तथापि, यदि शिक्षु ऐसा व्यक्ति है जिसपर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान लागू होते हैं तब वह उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके बदले में सूचना अथवा मजदूरी का हकदार होगा।
- (6) शिक्षु कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम, 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों द्वारा, जो भी प्रत्येक मामले में लागू हो, शासित होंगे।
- (7) सभी स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत आते हैं।
- (8) कर्मचारी की मृत्यु हो जाने अथवा चिकित्सीय आधार पर उसके सेवानिवृत्त हो जाने पर उस भूतपूर्व कर्मचारी के पति/की पत्नी अथवा परिवार के आश्रित सदस्य की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार।
- (9) नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न भत्ते एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की मंजूरी।
- (10) पात्रता के अनुसार रेलवे आवासों के साथ-साथ पदस्थापना के पूर्ववर्ती स्थान में रेलवे आवास रोक कर रखने की सुविधाएं।

➤ **कर्मचारी शिकायतों का निवारण :** कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पूर्व रेलवे में निम्नलिखित तन्त्र क्रियाशील हैं :

- क) मंडल/मंडलेत्तर/मुख्यालय स्तरों पर गठित कर्मचारी शिकायत कक्ष,
- ख) CPGRAM एवं CPENGRAM पोर्टलों के माध्यम से,
- ग) अभ्यावेदन के माध्यम से,
- घ) शिकायत पंजी में शिकायतें दर्ज करके,

- ड) कल्याण पदाधिकारी द्वारा कर्मचारी शिकायत शिविर लगाकर,
 च) निवारण,
 छ) यूनियन/संघ के माध्यम से,

➤ कर्मचारी लाभ निधि :

- (1) भारतीय रेलों पर कर्मचारी लाभ निधि की स्थापना सन् 1931 में की गई थी।
- (2) वर्षों का समय बीतने के साथ ही इस निधि का आकार बढ़ गया है और आज की तारीख में रेल कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के कल्याण हेतु चलाए जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलापों का वित्तपोषण इसी निधि से किया जाता है :
 - क) शिक्षा,
 - ख) ग्रेड वेतन रु.2,400/-, लेवल-4 तक के कर्मचारियों की बच्चियों की उच्चतर तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।
 - ग) ग्रेड वेतन रु.2,400/-, लेवल-4 तक के कर्मचारियों की बच्चों की उच्चतर तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।
 - घ) महिला सशक्तीकरण संबंधी क्रियाकलापों के साथ-साथ संगोष्ठी, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और लिंग संवेदनशीलता शिविर इत्यादि।
 - ड) खेल-कूद के अलावा मनोरंजन ,
 - च) संस्थानों और क्लबों आदि में मनोरंजन की सुविधाएं,
 - छ) सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा,
 - ज) ग्रेड वेतन रु.4,600/-, लेवल-7 तक के कर्मचारियों के लिए तनाव, बीमारी से मुक्ति आदि,
 - झ) खेल-कूद संबंधी क्रियाकलाप,
 - ञ) स्काउट एवं गाइड संबंधी क्रियाकलाप,
 - ट) चिकित्सा की स्वदेशी प्रणाली सहित होमियोपैथी,
 - ठ) बाढ़ आने, भू-स्खलन होने, आग लगने अथवा किसी अन्य आपदा के समय तत्काल राहत,
 - ड) शारीरिक विकलांग/मानसिक रोगी रेल कर्मचारियों तथा उनके बच्चों की व्यावसायिक कौशलता का विकास सहित व्हील चेयर्स, अन्य उपादानों, विशेष सॉफ्टवेयर इत्यादि का क्रय और कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, शिविरों का आयोजन आदि तथा
 - ढ) विविध - होलीडे होम, विश्रामालयों में सुधार हेतु सहायता, मनोरंजन/सूचना सुविधा जैसे – रंगीन टीवी; बिजली के सामान जैसी सुविधाओं पर होने वाले खर्च के लिए अनुरक्षण निधि।

- होलीडे होम : कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपाय के रूप में हॉलीडे होम स्थापित किए गए हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पूर्व रेलवे में उपलब्ध होलीडे होम की सूची नीचे दी गई है :

क्र. सं.	स्थान	कमरों की सं.	शुल्क	आवेदन हेतु पता
1.	नैनीताल	4		
2.	दार्जिलिंग	2		
3.	हरिद्वार	4		
4.	वैद्यनाथधाम	2		
5.	वाराणसी	2		

उपर्युक्त के अलावा, पूर्व रेलवे में कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए केन्द्रीय कर्मचारी लाभ निधि की सहायता से सात होलीडे होम/विश्रामालय चल रहे हैं जैसे- मुम्बई एवं वेल्लोर (चिकित्सा हेतु प्रतिदिन क्रमशः रु. 200/- एवं 100/- की दर से), पुरी प्रतिदिन रु. 150/- की दर से), दीघा प्रतिदिन रु.150/- की दर से), पेल्लिंग प्रतिदिन 100/- की दर से), गैगटोक प्रतिदिन रु.100/- की दर से) और नई दिल्ली प्रतिदिन 200/- और 100/-(ड्यूटी पर) की दर से)।

➤ रेलवे में मजदूरी के भुगतान हेतु मजदूरी प्रणाली:

रेलवे में मजदूरी के भुगतान हेतु अपनाई गई भुगतान प्रणाली मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 नामक अधिनियम द्वारा दिशा-निर्देशित होती है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 3 के अधीन मजदूरी के भुगतान हेतु जिम्मेदार है, उन अवधियों का निर्धारण करेगा (इस अधिनियम में मजदूरी-अवधि कहा गया है) जब मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और किसी भी मजदूरी-अवधि को एक महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि (क) किसी रेलवे, फैक्टरी अथवा (औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठान) पर अथवा में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सातवें दिन की समाप्ति से पहले (ख) किसी अन्य रेलवे, फैक्टरी अथवा (औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठान) पर अथवा में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को दसवें दिन की समाप्ति से पहले, उस मजदूरी-अवधि के अंतिम दिन के बाद जिसके लिए मजदूरी देय है, मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त दृष्टि से, अलग-अलग मजदूरी-अवधियां निर्धारित की गई हैं, जो उक्त प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली के आधार पर स्थिति के अनुसार कैलेंडर माह अथवा मिला हुआ माह हो सकती हैं। साथ ही, वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत कारखाना कर्मचारियों की मान ली गई उपस्थिति सामान्यतया अनुमेय नहीं है। तथापि, महत्वपूर्ण त्यौहार जैसे अपवाद मामलों में कारखाना कर्मचारियों की मान ली गई उपस्थिति अनुमेय है। किन्तु यह वर्ष में 2 अथवा 3 अवसरों से अधिक नहीं हो और साथ ही रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के साथ वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति प्राप्त हो।

पुनः, महत्वपूर्ण त्यौहारों के लिए मजदूरी के अग्रिम भुगतान की अनुमति है। किन्तु, यदि इस तरह का अग्रिम भुगतान मजदूरी-अवधि की समाप्ति से पहले किया जाता है, तो बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेना अपेक्षित है।

➤ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम : अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य –

1. नियोजन की उन कोटियों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को बनाए रखने के लिए, जहां मजदूरी कम है जैसे गैर-संगठित श्रमिक,
2. कार्य के घंटे, मजदूरी के भुगतान एवं मजदूरी के त्वरित भुगतान को विनियमित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए।
3. श्रमिकों के वेतन से की जाने वाली आवश्यक कटौतियाँ।
4. इस अधिनियम के तहत शासित होने वाले किसी श्रमिक पर कुछ कार्यों तथा भूल-चूक जैसे- ड्यूटी से अनुपस्थिति, लापरवाही, धूम्रपान, कार्य का नुकसान इत्यादि के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिदिन की दर से मजदूरी की गणना करने के लिए 26 दिन को एक माह माना जाना चाहिए।

➤ मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936: अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य –

1. मजदूरी के त्वरित एवं नियमित अंतराल पर भुगतान हेतु।
2. अनधिकृत कटौती किए बिना मजदूरी का भुगतान।
3. अनुमेय कटौतियाँ।

यह मजदूरी, मजदूरी के भुगतान की जिम्मेवारी, मजदूरी का निर्धारण, मजदूरी भुगतान करने का समय, अधिकृत कटौतियाँ, जुर्माना आदि के संबंध में भी दिशानिर्देश उपलब्ध कराता है।

- **उत्पादकता आधारित बोनस (PLB):** रेल कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस देने की योजना 1979 में चालू की गई है। इसके अंतर्गत अस्थायी एवजी सहित सभी अराजपत्रित कर्मचारी आते हैं। उत्पादकता आधारित बोनस की गणना करने के लिए मजदूरी की ऊपरी सीलिंग सीमा रु.3500/- निर्धारित की गई है। उत्पादकता का निर्धारण प्रत्येक वर्ष केवल राजस्व यातायात टन किलोमीटर के आधार पर किया जाता है जो भारतीय रेल के आंकड़ों के संगत लेखा परीक्षित विवरण से लिया जाता है। उत्पादकता आधारित बोनस देने का उद्देश्य उत्पादकता का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ढंग से प्रेरित करना है।
- **प्रोत्साहन योजना :** कारखानों तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए रेलवे में कर्मचारियों सहित पर्यवेक्षकों के लिए प्रोत्साहन योजना विद्यमान है। शुरुआत में यह योजना चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना में लागू की गई थी और बाद में इसे अन्य रेलवे कारखानों तथा उत्पादन इकाइयों में लागू किया गया। कार्य एवं उत्पादकता की माप करने के लिए समय इस योजना की प्रमुख विशेषता है।
- **दिव्यांग (शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति) रेल कर्मचारियों के लिए देय विभिन्न लाभ:**

- (1) निर्धारित दर से दोगुना परिवहन भत्ता।
- (2) कतिपय शर्तों के साथ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट
- (3) चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति लेने पर शारीरिक विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 47 के तहत सुरक्षा एवं छुट्टी की मंजूरी
- (4) चार दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश।
- (5) अक्षम कर्मचारियों के लिए कार्यों की पहचान
- (6) भर्ती पश्चात् एवं पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण
- (7) समुचित समय के भीतर शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण कक्ष
- (8) कार्य की अत्यावश्यक को ध्यान में रखते हुए अक्षमता एवं विकास से संबंधित सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों में सम्मिलित होने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति, ।
- (9) स्थानांतरण/पदस्थापन में प्राथमिकता.
- (10) सरकारी आवास में प्राथमिकता.
- (11) कार्य स्थल में सुगम प्रवेश एवं विध्व मुक्त वातावरण
- (12) चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति लेने पर पति/पत्नी अथवा परिवार के आश्रित सदस्य की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान.
- (13) चिकित्सीय दृष्टि से विकोटिकृत घोषित तथा वैकल्पिक नौकरी पहले से उपलब्ध नहीं होने पर शारीरिक विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 47 के अनुसार कर्मचारी के लिए एक विशेष अधिसंख्य पद का सृजन ।

➤ **महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोक-थाम :**

- (1) पूर्व रेलवे के मुख्यालय सहित सभी मंडलों तथा कारखानों में कामकाजी महिलाओं का कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न रोकने के उद्देश्य से कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के अनुसरण में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी-अपनी आंतरिक शिकायत समितियाँ गठित की गई हैं। इसके मुख्य प्रावधानों को रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3सी में शामिल किया गया है।
- (2) कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत की जा रही जांच - पड़ताल लम्बित रहने के दौरान, स्थिति के अनुसार, आंतरिक

समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर किसी पीड़ित महिला रेलवे सेवक को 90 दिनों की विशेष छुट्टी दी जा सकती है और पीड़ित महिला रेलवे सेवक को इस नियम के तहत स्वीकृत की गई छुट्टियों की कटौती उसके छुट्टी खाते से नहीं की जाएगी।

सेवा की समाप्ति पर मिलने वाले लाभ

- (1) **केन्द्रीय समूह बीमा योजना -1980:** अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अंशदान की दर ₹ 30/- और राजपत्रित कर्मचारियों के लिए, मामले के अनुसार, ₹60 और ₹120 है। मृत्यु हो जाने की स्थिति में, केन्द्रीय समूह बीमा योजना के तहत अराजपत्रित कर्मचारियों को ₹ 30,000/- + बचत और उसपर मिलने वाले ब्याज तथा राजपत्रित कर्मचारियों को, मामले के अनुसार, ₹ 60,000/- और ₹ 1,20,000 + बचत और उसपर मिलने वाले ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- (2) **अव्यवहृत छुट्टी के एवज में नकद भुगतान:** छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से रेलवे सेवक के सेवानिवृत्त होने की तिथि को उसके खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी और अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी, यदि हो, दोनों के लिए अवकाश वेतन के बराबर एक साथ एकमुश्त में देय नकद राशि के भुगतान के लिए एक आदेश जारी करेगा जो अधिकतम 300 दिनों के लिए होगा। यदि कोई रेल सेवक त्याग पत्र देता है अथवा नौकरी छोड़ता है तब छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्वविवेक से उसके पक्ष में नौकरी छोड़ने की तारीख को उसके छुट्टी खाते में जमा औसत वेतन अवकाश के बराबर नकद की स्वीकृति दी जा सकती है, जो उस अवकाश का आधा और अधिकतम 150 दिनों का होगा।
- (3) **सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान :** यह सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को देय है। इस एकमुश्त लाभ को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा एवं सेवा उपदान / पेंशन प्राप्त करने की पात्रता आवश्यक है। सेवानिवृत्ति उपदान की गणना अर्हक सेवा पूरी करने के प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त एक माह के मूल वेतन का एक चौथाई ($\frac{1}{4}$ th) और महंगाई भत्ता को जोड़कर की जाती है। उपदान की राशि के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। 33 वर्ष या उससे अधिक की अर्हक सेवा के लिए देय सेवानिवृत्ति उपदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 16 गुना, किन्तु अधिकतम ₹ 20 लाख होगा। यदि किसी रेल सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को नीचे दर्शायी गई तालिका के अनुसार मृत्यु उपदान की राशि का भुगतान किया जाएगा:

अर्हक सेवा की अवधि	उपदान राशि की दर
(i) एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 2 गुना
(ii) एक वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 6 गुना
(iii) 5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
(iv) 20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हक सेवा पूरी करने के प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा किन्तु यह परिलब्धियों के 33 गुना से अधिक नहीं हो।

- (4) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी सेवक की मृत्यु / विकलांगता पर अतिरिक्त लाभ :** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले रेलवे कर्मचारी की मृत्यु / विकलांग हो जाने पर, उसका परिवार, पेंशन नियमों के अनुसार परिवार पेंशन एवं मृत्यु उपदान के रूप में अतिरिक्त राहत पाने के लिए पात्र होगा।

(5) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता हेतु पात्रता:

- क) स्वयं और परिवार के लिए यात्रा करने की पात्रता
- ख) यदि स्थानांतरण में स्टेशन परिवर्तन शामिल है और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 20 कि.मी. या उससे अधिक है तब मूल वेतन के 80% की दर से समग्र स्थानांतरण एवं पैकिंग अनुदान। वैसे स्टेशनों पर स्थानांतरण होने की स्थिति में जो पुराने स्टेशन से 20 किलोमीटर से कम दूरी पर अवस्थित हो और एक ही शहर की सीमा में स्थानांतरण होने की स्थिति में समग्र स्थानांतरण अनुदान का एक तिहाई स्वीकार्य होगा, बशर्ते कि वास्तव में आवास परिवर्तन किया गया हो।
- ग) निर्धारित दरों पर वाहन परिवहन पर शुल्क की प्रतिपूर्ति और
- घ) वाहन का परिवहन किए जाने पर शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(6) रेलवे आवासों को रोक रखना:

.	सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	4 माह की अवधि हेतु सामान्य किराया/लाइसेंस शुल्क का फ्लैट दर और अगले 4 माह की अवधि हेतु सामान्य किराया का दो गुना/लाइसेंस शुल्क के फ्लैट दर का दो गुना दर से नॉन-इयरमाकर्ड रेलवे आवास को रखे रहने की अनुमति।
2.	सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के मामले में	सामान्य किराया दर पर अधिकतम 2 वर्षों की अवधि हेतु
3.	पूर्ण चिकित्सीय रूप से अक्षमता के आधार पर सेवानिवृत्ति और जिनके मामलों में अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नियुक्ति देने की प्रक्रिया चल रही हो	सेवानिवृत्ति की तिथि से सामान्य किराये पर अधिकतम 2 वर्षों की अवधि हेतु।
4.	रेलवे कर्मचारियों के गुम होने के मामले में।	सामान्य किराये पर अधिकतम 3 वर्षों की अवधि हेतु।

(7) निर्धारित चिकित्सा भत्ता (एफएमए): पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को निर्धारित चिकित्सा भत्ता ₹1000/- रुपये का भुगतान पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (पीएसए) के पास निम्नलिखित दो आवश्यक शर्तें : (ए) पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी निकटतम स्वास्थ्य यूनिट से 2.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर निवास कर रहा है, और (बी) पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी ओपीडी की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है (विनिर्दिष्ट जटिल मामलों को छोड़कर)।

(8) रेल कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (RELHS-97): सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों तथा सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके पति या पत्नी को RELHS-97 के तहत निर्धारित अंशदान पर चिकित्सा की सुविधा।

- (9) **आपातकालीन स्थिति में कैशलेस उपचार योजना (सीटीएसई):** आपातकालीन स्थितियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए नामिकाबद्ध अस्पतालों में अंशदान पर कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना के तहत RELHS लाभार्थियों को "CTSE प्लास्टिक फोटो पहचान पत्र (CTSE कार्ड)" जारी किया जाएगा।

➤ **नई पेंशन योजना (एनपीएस):**

- a) नई पेंशन योजना 01.01.2014 से लागू हुआ है।
- b) यह योजना सभी सरकारी/रेल सेवकों के लिए अनिवार्य है जो 01/01/2004 को या उसके बाद सरकारी/रेल सेवा से जुड़े हैं।
- c) इसके दो टियर हैं अर्थात् टियर- I और टियर- II
- d) टियर- I में, सरकारी / रेलवे सेवक मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% की दर से अनिवार्य अंशदान करेगा और सरकार द्वारा 14% की दर से अंशदान किया जाएगा।
- e) अंशदान और निवेश रिटर्न नॉन-वीथड्रॉल पेंशन टियर- I खाते में जमा किए जाएंगे।
- f) केंद्रीय सरकार में 01/01/2004 से जुड़े नई भर्तियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन और एसआरपीएफ / जीपीएफ के प्रावधान उपलब्ध नहीं होंगे।
- g) नई प्रणाली के तहत आने वाला एक सरकारी / रेल सेवक 60 वर्ष की आयु में टियर- I से बाहर निकल सकता है।
- h) इस प्रणाली से बाहर निकलने पर, किसी आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी खरीदने के लिए पेंशन धन का 40% निवेश करना अनिवार्य होगा जो सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी और आश्रित माता-पिता / जीवनसाथी के लिए आजीवन पेंशन प्रदान करेगा
- i) प्रत्येक व्यक्तिगत अंशदाता को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) कार्ड जारी किया जाता है और उसमें 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, अतिरिक्त शुल्क पर पुनर्मुद्रण किया जा सकता है।
- j) नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी सेवक की मृत्यु / विकलांग हो जाने पर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान के साथ-साथ परिवार/विकलांगता पेंशन के रूप में अतिरिक्त राहत।
- k) **सेवानिवृत्ति उपरान्त प्रतिपूरक पास (PRCP):** 20 वर्ष या उससे अधिक रेलवे सेवा पूरा करने वाले अराजपत्रित कर्मचारी स्वयं, पत्नी / पति और बच्चों के लिए PRCP के 2 सेट पास पाने के पात्र हैं, बशर्ते वही समान स्थिति रेलवे कर्मचारियों की सेवा के दौरान के लिए लागू हो।
- l) **अवकाश गृह:** सेवानिवृत्त गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों पर प्रतिदिन ₹ 60/- की दर से रेलवे अवकाश गृह में ठहरने की अनुमति दी जा सकती है। सेवानिवृत्त रेल सेवकों को गर्मी की छुट्टियाँ, दशहरा, पूजा और क्रिसमस की छुट्टियाँ जिसमें सेवारत रेलवे कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाती है, के अलावा अन्य समयावधि के दौरान अवकाश गृह की कन्फर्म बुकिंग ठहरने की तिथि से सात दिन पहले दी जाएगी और कन्फर्म बुकिंग को ठहरने की तारीख से सात दिन पहले रद्द नहीं किया जाएगा। यह सुविधा उन कर्मचारियों को भी मिलेगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों में स्थायी विलयन के उद्देश्य से रेलवे सेवा से तकनीकी रूप से इस्तीफा देते हैं और सेवानिवृत्ति उपरान्त प्रतिपूरक पास पाने के पात्र हैं।

अध्याय – 8

नई भर्तियों के लिए करें और नहीं करें

करें	नहीं करें
अभिप्रमाणन प्रपत्र में सही/प्रासंगिक सूचना दें।	जाति एवं अन्य विवरण के संबंध में गलत सूचना नहीं दें।
एस-1/पीआरएएन फार्म को भरें। (यदि पीआरएएन सं. पहले से उपलब्ध हो तो दोबारा फार्म नहीं भरें और आगे की वसूली के लिए पीआरएएन सं. और अन्य विवरण उपलब्ध कराएं)	संरक्षा मानदण्डों का उल्लंघन नहीं करें।
अपना और परिवार का घोषणा पत्र जमा करें।	सेवा संबंधी किसी भी मामले में अभ्यावेदन की प्रति बाहरी प्राधिकारियों को नहीं भेजें। यह अत्यंत आपत्तिजनक कार्य है, जो आधिकारिक स्वामित्व के विपरीत एवं अच्छे अनुशासन को समाप्त कर देता है।
सही वैवाहिक स्थिति बताएं।	ऐसा कुछ भी न करें जो किसी रेल सेवक के लिए अशोभनीय हो।
पहचान पत्र के लिए फार्म भरकर जमा करें।	किसी व्यक्ति अथवा संगठन को किसी वित्तीय अथवा अन्य बाध्यताओं में नहीं डालें जो कार्यालयी कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित कर सकता हो।
रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के अधीन सभी प्रावधानों का पालन करें।	ऐसा कुछ भी नहीं करें जो किसी कानून, नियम, विनियम और स्थापित प्रथाओं के विरुद्ध हो अथवा हो सकता हो।
नामांकन फार्म भरकर जमा करें।	एक रेल सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करें और स्वयं/परिवार अथवा अपने मित्रों को वित्तीय अथवा महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रखने का निर्णय नहीं लें; स्वयं को किसी व्यक्ति के प्रति किसी वित्तीय अथवा अन्य बाध्यताओं में न डालें।
रेलवे नियमों के अधीन उपलब्ध चिकित्सा सुविधा पाने के लिए नाम दर्ज कराएं।	किसी भी कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में न फँसें।
सुनिश्चित करें कि सेवा अभिलेख में सभी प्रविष्टियाँ भेजे गए दस्तावेजों के अनुसार की गई हैं।	किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनीति में सक्रिय किसी संगठन का सदस्य न बनें अथवा अन्य रूप में उससे जुड़ें और साथ ही न तो किसी राजनीतिक आंदोलन अथवा क्रियाकलाप में भाग लें, उसके सहायताार्थ अंशदान दें अथवा किसी अन्य तरीके से उसकी सहायता करें।
नैतिकता एवं ईमानदारी के उच्च मानक बनाए रखें।	एक रेल सेवक के रूप में स्वयं किसी प्रदर्शन में शामिल न हों, जो भारत की सम्प्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल हो।
प्रत्येक रेल सेवक, जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी है, कार्यस्थल पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाए।	दहेज न तो दें अथवा लें अथवा उसके लेन-देन के लिए उकसाएं; अथवा स्थिति के अनुसार किसी दुल्हे अथवा दुल्हन के माता-पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में किसी दहेज की मांग करें।
राजनीतिक तटस्थता बनाए रखें।	रेल सेवकों के अपने-अपने परिवारों की देखभाल करने में विफल होने पर उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

INDUCTION HANDBOOK FOR DIRECT RECRUITS

PREFACE

This Induction Handbook has been penned with an idea to give fair knowledge to all new Recruits about the Organisation in which they are recruited to serve as well as their rights & responsibilities towards it as a Railway servant. Though all possible care has been taken to ensure accuracy and consistency, in the event of a conflict between this Handbook and extant orders/instructions on the subject, the latter will prevail. Any information given herein cannot be cited in any dispute or litigation, nor is it a substitute for a legal interpretation/ evidence. The user will be solely responsible for any consequence of the decision taken on the basis of information contained in this Handbook. It may further be noted that this office does not entertain references on service matters directly from Railway servants. Any request for clarification/redressal of grievances etc. should be taken up with the concerned authority through proper channel.

INDEX

<i>Chapter</i>	<i>Subject</i>	<i>Page No.</i>
<i>Chapter-1</i>	<i>Introduction</i>	<i>3</i>
<i>Chapter -2</i>	<i>Structure</i>	<i>4 - 5</i>
<i>Chapter- 3</i>	<i>Some important Definitions</i>	<i>6 - 7</i>
<i>Chapter- 4</i>	<i>General Conditions of Service</i>	<i>8 - 12</i>
<i>Chapter-5</i>	<i>Promotion & Training</i>	<i>13 - 17</i>
<i>Chapter-6</i>	<i>Pay & Allowances</i>	<i>18 - 19</i>
<i>Chapter - 7</i>	<i>Privileges and Benefits</i>	<i>20 - 29</i>
<i>Chapter - 8</i>	<i>Dos & Don'ts for New Recruits</i>	<i>30</i>
	<i>Annexure-A Annexure-B & Annexure-C enclosed</i>	

Chapter 1

INTRODUCTION

INDIAN RAILWAYS, the premier transport organization of the country is the largest rail network in Asia and the world's second largest under one management. The first Railway on the Indian sub-continent ran over a stretch of 21 miles from Bombay to Thane. The formal inauguration ceremony was performed on 16th April 1853, when 14 railway carriages carrying about 400 guests left Bori Bunder at 3.30 pm "amidst the loud applause of a vast multitude and to the salute of 21 guns." The East Indian Railway (EIR) Company was incorporated in 1845 to connect East India with Delhi. The first train ran here between Howrah and Hooghly a distance of 24 miles, on 15th August 1854.. Thus the first section of the East Indian Railway was opened to public traffic, inaugurating the beginning of railway transport on the Eastern side of the sub-continent.

The management of the East Indian Railway was taken over by the British Indian government on 1st Jan 1925. The Eastern Railway was formed on 14th April 1952 by amalgamating three lower Divisions of the East Indian Railway: Howrah, Asansol and Danapur, the entire Bengal Nagpur Railway (BNR) and the Sealdah Division of the erstwhile Bengal Assam Railway. On 1st Aug 1955, some portions of BNR were separated from Eastern Railway and became the South Eastern Railway. Three more Divisions: Dhanbad, Mughalsarai and Malda were formed later.

Till 30 September 2002 ER consisted of seven Divisions. On 1st October 2002 a new zone, the East Central Railway was carved out by separating the Eastern Railway's Danapur, Dhanbad and Mughalsarai Divisions from it. Presently, ER comprises four Divisions viz. Howrah, Sealdah, Asansol and Malda headed by Divisional Railway Managers (DRMs) and three Workshops, viz., Liluah, Kanchrapara and Jamalpur headed by Chief Works Managers (CWMs).

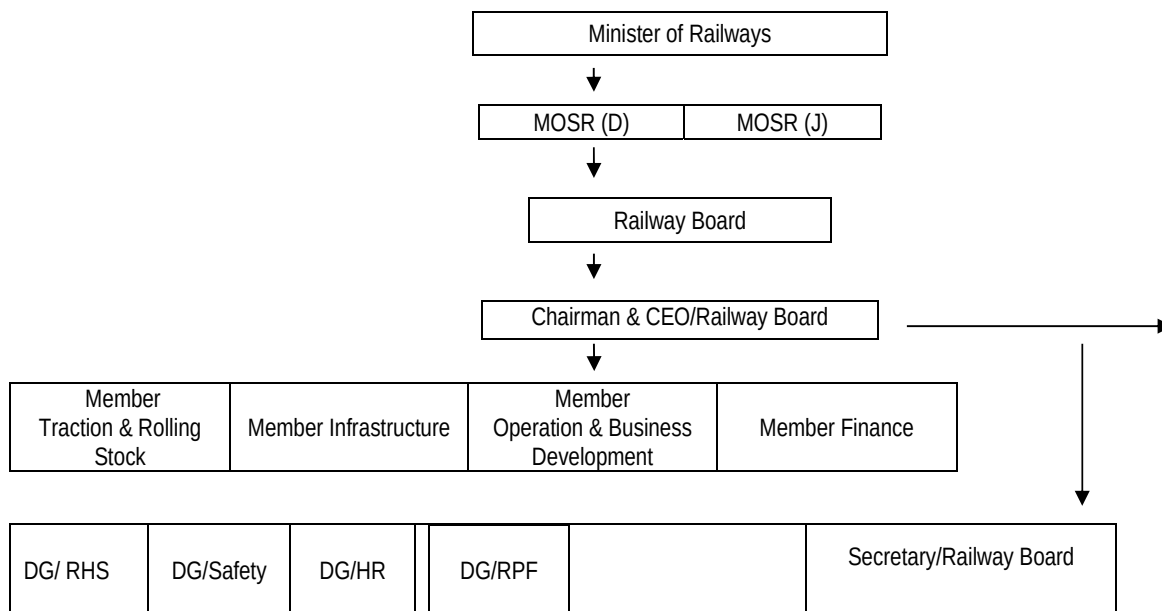
Chapter- 2

STRUCTURE

The President has framed rules for the convenient transaction of the business of the Government of India. The subjects allocated to the Ministry of Railways (Railway Board) are in charge of the Minister of Railways (MR) who is a Minister of Cabinet Rank with two Ministers of State for Railways (MOSR). The Railway Board is the Chief Administrative & Executive Body assisting the MR in discharging of his functions. It was constituted by a resolution of Govt. of India dated 18th February, 1905. The Railway Board consists of

1. Chairman & CEO, Railway Board – ex officio Principal Secretary to the Govt. of India.
and
2. Four Members viz. Member (Traction & Rolling Stock), Member (Infrastructure), Member (Operation and Business Development) and Member (Finance) and Four Director Generals (DGs) viz. RHS, HR, & RPF & Safety and Secretary, Railway Board.

ORGANISATION STRUCTURE OF MINISTRY OF RAILWAYS



On operational and management consideration, the Indian Railways have been divided into Sixteen Zones. These Zones are placed in the charge of General Managers who will be the Chief Administrative Officer answerable to Railway Board for all matters affecting the working of Railways. These Zones are as under:

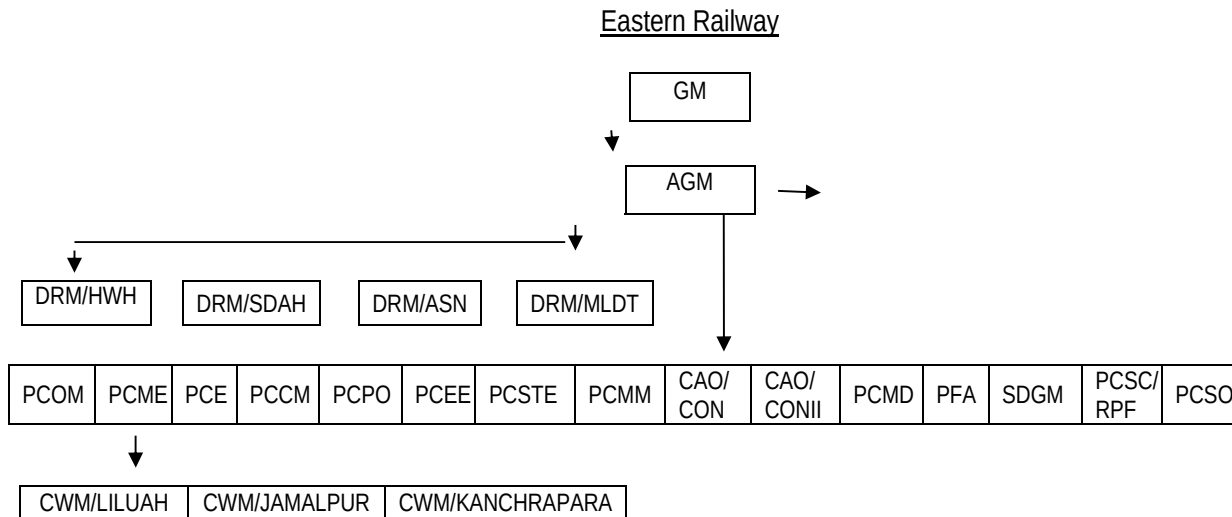
S.No.	Zonal Railway	Headquarters	Formed on
1.	Southern Railway	Chennai	14.04.1951
2.	Central Railway	Mumbai	05.11.1951
3.	Western Railway	Do	do
4.	Eastern Railway	Kolkata	14.04.1952
5.	Northern Railway	New Delhi	14.04.1952
6.	North-Eastern Railway	Gorakhpur	14.04.1952
7.	North-East Frontier Railway	Maligaon	15.01.1958
8.	South-Eastern Railway	Kolkata`	01.08.1955

9.	South-Central railway	Secunderabad	02.10.1966
10.	North-Central Railway	Allahabad	01.04.2003
11.	North-Western Railway	Jaipur	01.10.2002
12.	South-Western Railway	Hubli	01.04.2003
13.	West-Central Railway	Jabalpur	01.04.2003
14.	East-Central Railway	Hajipur	01.10.2002
15.	East-Coast Railway	Bhubaneshwar	01.04.2003
16.	South-East-Central Railway	Bilaspur	01.04.2003
<i>In addition to above, Metro Railway/Kolkata is functioning as Zonal Railway under the Ministry</i>			

In order to discharge the Administrative functions, each GM is assisted by AGM(s) and PHOD/CHODs & HODs of each Department viz., Operating, Engineering, Mechanical, Electrical, S&T, Accounts, Commercial, Personnel, Stores, Medical and Security.

Apart from the above sixteen Zonal Railways, there are six Production Units, viz. Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works, Integral Coach Factory, Rail-Wheel Plant, Diesel Component Works and Rail Coach Factory. Railway Recruitment Boards also function under the Railway Board. There are more organisations attached to Railway Board, such as Metro Rail/Kolkata, Metropolitan Transport Projects at Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, Central Organisation for Modernisation of Workshops New Delhi, Central Organisation for Railway Electrification/Allahabad, CRIS, Indian Railway Construction Company and Rail India Technical and Economic Service.

Zones are further divided into Divisions & Workshops headed by Divisional Railway Managers (DRMs) and Chief Works Managers (CWMs) respectively. The Stores Department also functions outside the Division under the Administrative Control of Pr. Chief Materials Manager (PCMM).



Other associates of the Ministry are, Indian Railway Conference Association (IRCA), Commissioner of Railway Safety, National Railway User's Council, Railway Tariff Enquiry Committee, Railway Claims Tribunals (RCT) and Railway Recruitment Boards/Cells.

CHAPTER-3

SOME IMPORTANT DEFINITIONS

Railway means a railway, or any portion of a railway, for the public carriage of passengers or goods, and includes— (a) all lands within the fences or other boundary marks indicating the limits of the land appurtenant to a railway; (b) all lines of rails, sidings, or yards, or branches used for the purposes of, or in connection with, a railway; (c) all electric traction equipments, power supply and distribution installations used for the purposes of, or in connection with, a railway; (d) all rolling stock, stations, offices, warehouses, wharves, workshops, manufactories, fixed plant and machinery, roads and streets, running rooms, rest houses, institutes, hospitals, water works and water supply installations, staff dwellings and any other works constructed for the purpose of, or in connection with, railway; (e) all vehicles which are used on any road for the purposes of traffic of a railway and owned, hired or worked by a railway; and (f) all ferries, ships, boats and rafts which are used on any canal, river, lake or other navigable inland -waters for the purposes of the traffic of a railway and owned, hired or worked by a railway administration.

[Ref.: Rule 31 of Railway Act, 1989]

Railway servant means a person who is a member of a service or holds a post under the administrative control of the Railway Board. It also includes a person who is holding the post of Chairman, Financial Commissioner or a Member of the Railway Board. Persons lent from a service or post which is not under the administrative control of the Railway Board to a service or post which is under such administrative control do not come within the scope of this definition. The term excludes casual labour.

Apprentice/Trainee means a person deputed for training in a trade or business with a view to employment in railway service, who draws pay at monthly rates from Government during such training but is not employed in or against a substantive vacancy in the cadre of a department.

Cadre means the strength or a service or a part of a service sanctioned as a separate unit.

Transfer means the movement of a railway servant from one headquarter station in which he is employed to another such station, either – (a) to take up the duties of a new post, or (b) in consequence of a change of his headquarters.

Substantive pay means the pay other than special pay, personal pay or emoluments classed as pay by the President under Sub-rule 35 (iii), to which a railway servant is entitled on account of a post to which he has been appointed substantively or by reason of his substantive position in a cadre.

Note: In the case of a person with a lien on a permanent post under a State Government, 'Substantive Pay' means the substantive pay as defined in the relevant rules of the State Government concerned.

[Ref.: Rule 103 of IREC, Vol.I]

Oath of allegiance.—All new entrants to service must take oath before the head of department/office or a gazetted railway servant nominated by him. Conscientious objector of oath taking may make solemn affirmation. The oath taking or affirmation shall be in the following form.

“I do swear/solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and with impartially, so help me God”.

[Ref.: Rule 221 of IREC, Vol.I]

Headquarters of a Railway servant.—(a) As a general rule, and subject to any special orders to the contrary in particular cases, the headquarters of a railway servant on the staff of the Railway Ministry are the headquarters, for the time being, of the Government of India.

(b) The headquarters of any other railway servant are either the station which has been declared to be his headquarters by the authority competent to prescribe his headquarters for the purpose of travelling allowance, or in the absence of such declaration, the station where the records of his office are kept.

Note.—An officer under suspensions regarded as subject to all other conditions or service applicable generally to railway servants and cannot leave the station without prior permission. As such, the headquarters of a Railway servant should normally be assumed to be his last place of duty. However, where an individual under suspension requests for a change of headquarters, there is no objection to a competent authority changing the headquarters, if it is satisfied that such a course will not put the Railway Administration to any extra expenditure like, grant of travelling allowance or other complications.

[Ref.: Rule 234 of IREC, Vol.I]

Family means a railway servant's wife/husband, legitimate children and stepchildren residing with and wholly dependent upon him/her. It also includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon him/her. Provided further that for Rule 615, it includes only such of the dependent relatives as are eligible for passes under the Pass Rules. Not more than one wife is included in this term. The term "legitimate children" includes those adopted under the law.

[Ref.: Rule 103(17) of IREC, Vol.I]

Lien means the title of a Railway servant to hold on regular basis either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post, including a tenure post, to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation. Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

[Ref.: Rule 103(28) of IREC, Vol.I]

Chapter – 4

GENERAL CONDITION OF SERVICE

There are certain provisions/instructions, knowledge of them are essential for all new entrants to service. Some of the important such provisions are as follows:

- Adherence to the provisions laid down in Railway Services (Conducts) Rules, 1966, in letter and spirit, is compulsory. Any violation of the provision renders a railway servant liable to disciplinary action. For details of Railway Services (Conduct) Rules, 1966, see Annexure-A.

[Ref.: Appendix-I of IREC, Vol.I]

- The furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification, and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

[Ref.: Form ER-G6]

- No person who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the lifetime of such spouse, shall be eligible for appointment to service; and

- No woman whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage, or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to service.

- Every person, on entering railway service, shall declare his date of birth which shall not differ from any declaration expressed or implied for any public purpose before entering railway service. The date of birth as recorded in accordance with these rules shall be held to be binding and no alteration of such date shall ordinarily be permitted subsequently.

[Ref.: Rule 225 of IREC, Vol.I]

- Any person being considered for appointment on compassionate ground, should give an undertaking in writing that he/she will maintain properly the other family members who have been dependent on the Railway servant and in case it is proved subsequently that the family members are being neglected or are not being properly maintained by him/her, his/her appointment may be terminated forthwith under the GM's power without following the procedure prescribed under Disciplinary Rules/Temporary service rules.

[Ref.: RBE No. 44/2002 (PCPO/ER's Sl. No. 62(05)/2002)]

- Wherever it is found that a Govt./Railway servant who was not qualified or eligible in terms of Recruitment rules etc., for initial recruitment in service or had furnished false information or produced a false certificate in order to secure appointment, he/she should not be retained in service.

[Ref.: RBE No. 110/93 (PCPO/ER's Sl. No. 102/93)]

- Complaints of the failure of Railway servants to look after their families should be investigated and if prima facie case exists they are liable to disciplinary action.

[Ref.: RBE No. 62/2005 (PCPO/ER's Sl. No. 40(04)/2005)]

- The appointing authority should satisfy itself that the character and antecedents of the person proposed to be appointed are such as do not render him unsuitable for appointment to Government service in accordance with the instructions issued by the Railway Board to Railway administrations from time to time.

[Para 101 of Section-D of Chapter-I of IREM, Vol.I.]

- Persons recruited as Apprentices or Trainees shall be required to make security deposits during their period of training/apprenticeship as required by the individual railway administrations.

[Para 119 of Sub-Section-II of Chapter-1 of IREM, Vol.I]

- No railway servant is entitled to pay or allowances for any time he may spend beyond the limits of his charge without proper authority.

[Ref.: Rule 235 of IREC, Vol.I]

- Unless in any case it be otherwise distinctly provided, the whole time of a railway servant is at the disposal of the Government which pays him, and he may be employed in any manner required by proper authority, without claim for additional remuneration, whether the services required of him are such as would ordinarily be remunerated from the Consolidated Fund of Government of India, from a local fund or from the funds of a body incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government.

[Ref.: Rule 237 of IREC, Vol.I]

- The lien of a permanent Railway servant appointed under another Central/State Government or office may be retained on the Railway for a period of two years (three years in exceptional cases). If he is not permanently absorbed within this period in the new post, he should immediately on expiry of the said period, either resign from the Railway service or revert to his parent office.

[Ref.: Rule 244 of IREC, Vol.I]

- No Railway servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

- Unless the President, in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, a Railway servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the Railway Service; Provided that a reasonable opportunity to explain the reason for such absence shall be given to that Railway servant before provisions of Sub-Rule (2) are invoked.

[Ref.: Rule 510 of IREC, Vol.I]

- Unless the authority competent to grant leave extends the leave, a railway servant who remains absent after the end of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence and the period shall be debited against his leave account as though it were leave on half average pay, to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave. Wilful absence from duty after the expiry of leave renders a railway servant liable to disciplinary action.

[Ref.: Rule 518 of IREC, Vol.I]

- An interruption in the service of a railway servant shall lead to forfeiture of his past service, except in the following cases namely: - (a) authorised leave of absence; (b) unauthorised absence in continuation of authorised leave of absence so long as the post of absentee is not substantively filled; (c) suspension, where it is immediately followed by reinstatement whether in the same or a different post, or where the railway servant dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of compulsory retirement, while under suspension; (d) transfer to non-qualifying service in an establishment under the control of the Government if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest; (e) joining time while on transfer from one post to another.

[Ref.: Rule 42 of Pension Rules, 1993]

- A two years probation period is mandatory in all recruitment grades and where initial training period is prescribed, such as in the case of Apprentice PWIs, Traffic Apprentices etc., the probation period will start after a successful completion of training. The appointee should satisfactorily complete the probation. A railway servant who has successfully completed the probation may be considered for confirmation. A probation period of 12 months should be prescribed in all grades of promotion.

[Paras 111 to 113 of Part-II of Section-F of IREM, Vol.I]

- When a railway employee, who is residing within the jurisdiction of a Railway doctor, is unable to attend duty by reason of sickness, he must produce, within 48 hours, a sick certificate from the competent Railway doctor in the prescribed form. It is essential that if leave of absence is required on medical certificate, a request for such leave should be supported by a sick certificate from the Railway doctor.
- When a Railway employee residing outside the jurisdiction of a Railway doctor requires leave on medical certificate, he should submit, within 48 hours, a sick certificate from a registered medical practitioner. Such certificate should state the nature of the illness and the period for which the Railway employee is likely to be unable to perform his duties. The competent authority may, at its discretion accept the certificate or, in cases where it has reasons to doubt the bonafides, refer the case to the Authorised Medical Officer for advice or investigation.
- The medical certificates from the Registered private practitioners produced by the employee in support of their applications for leave may be rejected by the competent authority only after a Railway medical officer has conducted the necessary verifications and on the basis of the advice tendered by him after such verifications.
- The submission of sick certificate shall be tantamount to only an application for leave on medical certificate, and shall not be held to carry with it permission to quit the station, unless such permission is expressly given by the competent Railway doctor.

[Ref.: Para 538 of IRMM, Vol.I]

- Grant of leave: - The grant of a certificate under the provisions under Leave Rules does not in itself confer upon the Railway employee any right to leave. The certificate should be forwarded to the authority competent to grant leave and the orders of that authority should be awaited.

[Ref.: Para 551 of IRMM, Vol.I]

- Wherever, in any matter connected with his service rights or conditions, a Government/Railway servant wishes to press a claim or to seek redressal of a grievance, the proper course for him is to address his immediate official superior, or Head of his office, or such other authority at the appropriate level who is competent to deal with the matter in the organisation. Such submission of representations directly to other authorities by-passing the prescribed channel of communication has to be viewed seriously and appropriate disciplinary action should be taken against those who violate these instructions.

[Ref.: RBE No.162/15 (PCPO/ER's Sl. No. 4/16)]

REQUEST TRANSFER

Ordinarily, a railway servant shall be employed throughout his service on the railway or railway establishment to which he is posted on first appointment and shall have no claim as of right for transfer to another railway or another establishment. In the exigencies of service, however, it shall be open to the President to transfer the railway servant to any other department or railway or railway establishment including a project in or out of India. In regard to Group C and Group D railway servants, the power of the President under this rule in respect of transfer, within India may be exercised by the General Manager or by a lower authority to whom the power may be re-delegated.

Railway Ministry's decision.—Requests from railway servants in Groups C & D for transfer from one railway to another on grounds of special cases of hardships may be considered favourably by the railway administration. Such staff transferred at their request from one railway to another shall be placed below all existing confirmed and officiating staff in the relevant grade in the promotion group in the new establishment, irrespective of date of confirmation or length of officiating service of the transferred employees.

[Ref.: Rule 226 of IREC, Vol.I]

In terms of extant procedure, request transfers are allowed from one seniority unit to another in the following manner:

- a) On bottom seniority in grades having direct recruitment against vacant direct recruitment quota posts subject to the condition that the employee requesting transfer fulfils the qualification prescribed for direct recruitment to the post; and

- b) On mutual exchange basis in any grade in the corresponding cadre on own request or seniority of the employee with whom the exchange takes place, whichever of the two is lower. This is subject to condition that employees seeking mutual transfer are belonging to the same category, i.e. General/OBC with General/OBC, SC with SC and ST with ST. However, mutual transfer in the recruitment grades will also be allowed without this restriction provided both the employees seeking mutual transfer should have been recruited directly from open market.
- c) The condition of corresponding cadre has been dispensed with in case of employees working in Level-1 (erstwhile Grade Pay Rs.1800).
- d) Mutual transfer may also be permitted between employees working in corresponding cadre of two different grades only in recruitment grade of the cadre with bottom seniority in their respective new units.
- e) One-way own request transfer on bottom seniority will not be considered till completion of five years of joining the Railway.
- f) Exemption from the condition of 5 years of service is given vide RBE No. 12/17 (PCPO's sl. No. 15/17) for mutual transfer, transfer on spouse ground, Railway servants who are care-giver of disabled child and physically handicapped Railway servants.
- g) All cases of transfer on Spouse grounds will be dealt and decided in terms of instructions laid down in RBE No. 23/2010 (PCPO's Sl. No. 21/2010).
- h) All such requests will have to be made with all correct and complete details in the prescribed proforma and sent through the controlling authority for registration with the concerned Personnel Branch offices.

Forwarding of applications from serving railway employees for posts outside Railways:

- a) Railway employees may be given 4 opportunities in a year to apply in response to notices of Government Departments/Public Sector Undertakings/autonomous bodies wholly or substantially financed and controlled by Central or State Government except where holding of any such applications is considered justified in the public interest by the competent authority.
- b) Applications in response to UPSC advertisement will not be counted against the four opportunities mentioned above.
- c) When a railway employee desires to apply for a post in a private concern he should first offer to resign or retire from railway service.
- d) Applications of Govt. servants for other posts should not be forwarded when disciplinary proceedings against them are contemplated whether for major or minor penalty.
- e) Where a Government servant has applied through proper channel for a post in the same or some other Department, and is on selection, required to resign the previous post for administrative reasons, such resignation may be called as Technical Resignation and all service benefits in such cases will be regulated under instructions issued vide RBE No. 21/2017 (PCPO's Sl. No. 26/2017)

Chapter – 5

PROMOTION & TRAININGTRAINING:

The major challenges before Indian Railways in providing services matching with customers' expectations, in resource generation through improved productivity and in assimilating rapid changes in technology can be met effectively only through continuous up-gradation of knowledge and skills of Railway men and women by developing right attitude in them. Role of training in achieving this cannot be over emphasised. It has rightly been said that in work environment merely knowing what is to be done is not sufficient. It is equally important to know how and why it has to be done.

Considering the importance of Training, the 'Manual on Management of Training' (hitherto known as the Manual) has been published by the Railway Board in sync with the "National Training Policy" of Govt. of India.

In a work organisation, training is a learning process in which learning opportunities are structured in a planned manner so as to develop employees' knowledge, skills and attitude, necessary for effective performance of their work, thereby achieving organisational aims and objectives by the most cost effective measures available. As per the Manual, Training activities include:

- Direct Training (Tutor/Trainer based)
- Work Based Projects
- Individual Study
- On-the-job Coaching/mentoring
- Desk instructions/performance aids
- Open learning
- Workshops
- Conferences/Exhibitions
- Secondments/Visits.

Broadly, Training can be categorised under the following four types, viz. (1) Initial/Induction training (for the purpose of orientation of new entrants in the organisation), (2) Refresher training (for the purpose of refreshing), (3) Promotional Training (for the purpose of preparing staff for higher responsibilities) and (4) Special training for Safety etc. (for the purpose of providing specialised knowledge).

The Indian Railways have a huge network of 297 Training Centres where railway servants undergo training in initial, refresher, promotional and specialised training programme. With a view to make training more relevant and useful, some qualitative changes have been introduced. These are as under:

- Mandatory Yoga training for all employees to help cope with stress,
- Soft Skills/Customer- Care training for frontline staff was also started to provide better- customer interface,
- A separate plan head for Training/HRD has also been notified to take care of new work related to training,
- Improvement in Messing facilities.

Besides, having regard to C&AG's report of Corporate safety Plan (2003-13), the provision of the initial and periodic refresher training course for all employees (both safety & non-safety and maintenance staff) on fire-fighting/use of fire extinguishers has been introduced.

List of Training Centres, including MDZTC and MDDTCs, functioning in Eastern Railway: Following training centres are functioning in Eastern Railway:-

Multi-Disciplinary Institute (MDZTI)	Zonal Training	Zonal Railway Training Institute(ZRTI)/Bhuli/ Dhanbad
Multi-Disciplinary Institutes	Divisional Training	a) Divisional Traffic Training Centre/ Madhupur/ Asansol, b) Divisional Traction Training Centre/ Bamangachi/ Howrah, c) Carriage & Wagon Training Centre/ Naihati/ Sealdah, d) Signal & Telecom Training Centre/Malda.
Basic Training Centres		a) Basic Training Centre/Jamalpur & Liluah b) STC/BTC /Kanchrapara
Specialized Training Centres		a) S&T – Signal & Telecom Training Centre/Liluah b) Electrical – Electrical Loco Training Centre/Asansol & Pilot Training School/Jamalpur c) Engineering – Engg. Training Centre/ Beliaghata/ Sealdah (already developed as Advanced Track Training Centre) d) Security – RPF Training Centre/Kanchrapara e) Mechanical – Freight Stock & MEMU/DEMU BOX 'N' Training Centre/Andal and LHB, ICF, Power Car, TL & AC – Tikiapara C&W Training Centre.

Project Saksham-II, 2019: With a view to ensure that each employee is imparted training, 'Project Saksham' was launched on 30/10/2017. Approximately, 13 lakh Railway employees had been given 5-days on-job training from January, 2018 to September, 2018. On the same lines, "Project Saksham-II, 2019" has been launched on 20/03/2019. Under this scheme, a 5 days on-job training programme will be held for nine months commencing from 01/04/2019 to 31/12/2019.

Mission Satyanishtha - launched on 27th July 2018 aims at sensitizing all railway employees about the need to adhere to good ethics and to maintain high standards of integrity at work. Talks and Lectures on the subject are being organised all over the Indian Railways today for this purpose. The objectives of the Mission are:

1. To train every employee to understand the need and value of ethics in Personal and Public life.
2. To deal with ethical dilemmas in life and Public Governance.
3. To help understand the policies of Indian Railways on ethics and integrity and the employee's role in upholding the same.
4. To develop inner governance through tapping inner resources.

CAREER PROGRESSION AND PROMOTION:

There are six methods of recruitment i.e. (a) promotion (b) direct recruitment (c) deputation (d) absorption (e) re-employment (f) short-term contract. The percentage of vacancies to be filled by each method that may be prescribed for a particular post or Service depends on a judicious blending of several considerations.

The manner in which recruitment to a particular grade or group of posts should be made, has necessarily to be determined with reference to the qualifications, experience and previous training required for efficiently manning the post. It is also necessary to ensure that persons employed in the lower grades of the service or lower posts have adequate opportunities of promotion so that incentive to good work is maintained. Keeping these considerations in views, detailed Recruitment Rules for appointment in non-gazetted posts under various Departments have been

prescribed in Sub Section-III, Section-B, Chapter-I of Indian Railway Establishment Manual, Vol. I (Revised Edition 1989). Besides, there are guidelines contained in this Chapter on promotional avenues available for the staff working in the lowest grade i.e. in Level-1 (GP Rs. 1800).

Apart from the above, there is a scope for General Departmental Competitive Examination (GDCE)/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) for career progression of new recruits. The scope of GDCE has been widened to include all categories of posts which are having a direct recruitment quota 25% and more. The channel of LDCE and GDCE can be availed by the young, talented and qualified staff working in lower grades for fast track progression to higher grades. The currency of the scheme of GDCE has since been extended from time to time and was last extended up to 31/03/2020.

Similarly, the Scope of LDCE has been provided in relevant Recruitment Rules for various posts on the Railways, the prominent of them are namely, the post of Technician Gr.III/Level-2 against qualified quota, the posts of Commercial Clerks, Ticket Collectors, Trains Clerks, Office Clerks, Stores Clerks, etc. in Level-2 against 16-2/3% department quota, Chief S&WI Inspector/Level-7 against 20% quota, Intermediate Apprentice Quota for promotion to the post of Junior Engineer in Level-6 etc. For appearing in LDCE/GDCE, one has to fulfil the eligibility conditions viz., educational qualification and residency etc., prescribed under existing instructions.

Other important aspects related to promotion are as under:

- Promotion includes promotion from lower grade to higher grade, from one class to another class and from one group to another group. A Railway servant may be promoted to fill any post whether a "Selection" post or a "Non-selection" post only if he is considered fit to perform the duties attached to the post.
- There will be only two categories of posts-" Selection Posts" and "Non-selection posts"."Selection posts" are posts, grades or classes which have been notified as such with the approval of the Railway Board on the consideration that promotions to them are required to be made on the basis of positive act of selection made with the help of Selection Boards, as per procedure prescribed for this purpose, from amongst the staff eligible for selection. The selection for promotion to a selection post shall be made either based on the merit and seniority both or only on the merit according to the mode of filling up the posts.
- The employee refusing promotion expressly or otherwise (i.e. not only he does not give in writing his refusal but also does not join the post for which he has been selected) is debarred for future promotion for one year.
[Para 224 of IREM, Vol.I]
- No exemption should be given from passing a prescribed promotional course wherever pre-requisite for further promotion to a grade in a cadre. When employees are booked for promotional course, they should be relieved immediately.
[Para 227 of IREM, Vol.I]

Standard Avenue of Promotion (AVC) in some important popular categories:

(A) Group C in Level-1/GP Rs. 1800 (erstwhile Group 'D'):

- 1) Railway servants in Group 'D' categories for whom no regular avenue of promotion exists 33-1/3% & 16-2/3% (with prescribed qualification) of the posts in the lowest grade of Commercial-cum-Ticket Clerk, Trains Clerks, Office Clerks, Stores Clerks, etc. should be earmarked for promotion.
- 2) Category of Helpers in all Engineering Departments including Workshops having avenue of promotion in Technician category under Artisan Cadre and further on in the category of Junior Engineer and Sr. Section Engineer in Technical Supervisor Cadre.
- 3) All railway servants in the lowest grade working in Transportation and Commercial Departments should be eligible for consideration for promotion to higher grades in both the Transportation and Commercial branches.

- 4) Category of staff in Level-1/GP 1800/- with 7 years of service and are in possession of any of the qualifications viz., Diploma in Labour/Social Welfare or Diploma in Labour Law or LLB with papers in Labour Laws, PG Dip in Personnel Management or MBA with papers in Personnel Management awarded by an Institution of Govt. of India are eligible for Staff & Welfare Inspector in Level-6/GP Rs.4200
- 5) For any higher post notified under GDCE, if possessed the required prescribed qualification of the post for which notification from RRC is issued.

(B) Non-Technical Popular Categories (NTPC): in Level-2 & 3/GP. Rs.1900 & 2000:

- 1) For higher grades within the cadre as per normal promotional avenue.
- 2) For any higher post notified under GDCE, if possessed the required prescribed qualification of the post for which notification from RRC is issued.
- 3) For the post of Staff & Welfare Inspector, if otherwise eligible as per extant guidelines.
- 4) For the post of Ch. Law Assistant in the Law Cadre, if otherwise eligible as per extant guidelines.

(c) Artisan Cadre as Technician in Level-2/GP Rs. 1900:

- 1) For higher grades within the cadre as per normal promotional avenue.
- 2) Lateral induction as ALP in Level-1
- 3) For the post of Staff & Welfare Inspector, if otherwise eligible as per extant guidelines.
- 4) For the post of Ch. Law Assistant in the Law Cadre, if otherwise eligible as per extant guidelines.
- 5) For any higher post notified under GDCE, if possessed the required prescribed qualification of the post for which notification from RRC is issued.
- 6) For Inter-Apprentice quota for promotion to the post of Junior Engineer in Level-6/GP Rs.4200, if otherwise eligible as per extant guidelines.

(D) Technical Supervisor Cadre in Level-6/GP Rs.4200:

- 1) For the post of Sr. Section Engineer in Level-7/GP Rs. 4600 as per normal avenue of promotion within the cadre.
- 2) For Group 'B' post, if otherwise eligible as per extant guidelines.
- 3) For any higher post notified under GDCE, if possessed the required prescribed qualification of the post for which notification from RRC is issued.

➤ **Rules Governing Assignment of Seniority:**

The seniority of candidates recruited through the Railway Recruitment Board or by any other recruiting authority should be determined as under:

- 1) Candidates who are sent for initial training to Training Schools will rank in Seniority in the relevant Grade in the order of merit obtained in the examination held at the end of the training period before being posted against working post. Those who join the subsequent courses and those who pass the examination in subsequent chances will rank junior to those who had passed the examination.
- 2) In the case of candidates who do not have to undergo any training in training school, the seniority should be determined on the basis of the merit order assigned by the Railway Recruitment Board or other recruiting authority.
- 3) When two or more candidates are declared to be of equal merit at one and the same examination/ selection, their relative seniority is determined by the date of birth the older candidate being the senior.
- 4) When, however, a candidate whose seniority is to be determined under paragraphs (1) and (2) above cannot join duty within a responsible time after the receipt of orders of appointment, the appointing authority may determine his seniority by placing him below all the candidates selected at the same examination/selection, who have joined within the period allowed for reporting to duty or even below candidates selected at subsequent examination/ selection who have joined before him.
- 5) Candidates selected for appointment at an earlier selection shall be senior to those selected later irrespective of the dates of posting except in the case covered by paragraph (4) above.

- 6) Railway servants transferred on mutual exchange from one cadre of a division, office or railway to the corresponding cadre in another division, office or railway shall retain their seniority on the basis of the date of promotion to the grade or take the seniority of the railway servants with whom they have exchanged, whichever of the two may be lower.
- 7) Seniority of railway servants on transfer from one cadre to another in the interest of the administration is regulated by the date of promotion/date of appointment to the grade as the case may be.
- 8) The seniority of railway servants transferred at their own request from one railway to another should be allotted below that of the existing confirmed, temporary and officiating railway servants in the relevant grade in the promotion group in the new establishment irrespective of the date of confirmation or length of officiating or temporary service of the transferred railway servants. This applies also to cases of transfer on request from one cadre/division to another cadre/division on the same railway.
- 9) Railway servants may be permitted to see the seniority lists in which their names are placed, or if this cannot conveniently be arranged, they may be informed, on request, of their place on the seniority list. Staff concerned may be allowed to represent about the assignment of their seniority position within a period of one year after the publishing of the seniority list. No cases for revision in seniority lists should be entertained beyond this period.

Chapter – 6

PAY & ALLOWANCES➤ Pay and Allowances:

Subject to any exceptions specifically made under extant rules, a railway servant shall begin to draw the pay and allowances attached to his tenure of post with effect from the date he assumed the duties of the post, and shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties.

Provided that an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence.

➤ Date of reckoning pay and Allowances:

(1) Government servant will begin to the pay and allowances attached to his tenure of post with effect from the date on which he assumes the duties of that post if the charge is transferred before noon of that date. If the charge is transferred in the afternoon, he commences to draw them from the following day. This rule does not, however, apply to cases in which it is the recognised practice to pay a Government servant at higher rate for more important duties performed during a part only of a day.

(2) The date from which a person recruited overseas shall commence to draw pay on first appointment shall be determined by the general or special orders of the authority by whom he is appointed.

➤ Salary Structure on initial Appointment and Annual Increment :

Basic Pay Depending on the level of initial appointment (i.e. L-1, L-2, L-3, L-5, L-6, L-7) Dearness Allowance applicable from time to time, House Rent Allowance (HRA) depending upon place of posting (24%/16%/8% of Basic Pay) and Transport Allowance, depending upon place of posting. There are other various allowances which may be paid as per extant instructions depending on the functions and admissibility. Pay Matrix recommended by 7th CPC as notified under RS(RP) Rules, 2016 is enclosed in Annexure-B

In addition, there shall be two dates for grant of annual increment namely, 1st January and 1st July of every year. Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial up-gradation.

➤ Benefit for counting of training period:

The training period of non-gazetted employees who are required to undergo training prescribed for posts before they are put on regular employment is treated as qualifying service for following purposes:

- a) Drawal of increment.
- b) For the purpose of pension & pensionary benefits.
- c) For the purpose of determining the eligibility of class/scale of Passes.
- d) For departmental promotion including promotion under LDCE.

➤ Pay during suspension:

A railway Servant under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of the competent authority shall be entitled to the following payments, namely-

(1) (a) A subsistence allowance at an amount equal to the leave salary which the Railway servant would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay and in addition dearness allowance, if admissible, on the basis of such leave salary.

Provided that where the period of suspension exceeds 3 months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first 3 months as follows:

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding 50 per cent of the subsistence allowance admissible during the period of the first three months , if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, not directly attributable to the railway servant;
- (ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount not exceeding 50 percent of the subsistence allowance admissible during the period of the first three months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the railway servant;
- (iii) the rate of dearness allowance will be based on the increased or, as the case may be, decreased amount of subsistence allowance admissible under sub-clauses (i) and (ii) above

(b) Any other compensatory allowances admissible from time to time on the basis of pay of which the railway servant was in receipt on the date of suspension subject to the fulfilment of other conditions laid down for the drawl of such allowances.

(2) No payment under sub-rule (1) shall be made unless the railway servant furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment business, profession or vocation.

➤ Allowances: Details of Allowances with authority admissible in 7th CPC are enclosed as Annexure-C.

Chapter – 7

PRIVILEGE AND BENEFITS➤ Relaxation of the age limit:

- 1) For direct recruitment to all Group 'C' & 'D' vacancies, serving employees who have put in three years continuous service on the Railways will be given age relaxation upto the upper age limit of 40 years, in the case of general category candidates, 43 years in the case of OBC candidates and 45 years in the case of ST/SC candidates. Same age concession will be applicable to such of the substitutes as have put in three years service continuous or in broken spells.
- 2) For direct recruitment to all Group 'C' and Group 'D' posts, the Upper age limit in the case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands, who are not remarried, shall be relaxed Upto the age 35 years. In such cases, there will be further relaxation upto the age of 38 years for 'other Backward Community (OBC)' candidates, and upto 40 years for Scheduled Caste / Scheduled Tribes (SC/ST) candidates.
- 3) A candidate who is within the minimum and maximum age limits on a particular date mentioned in the employment notice issued by a Railway Recruitment Board may be treated as eligible for appointment against a post on the Railway concerned even though the person concerned may have exceeded the maximum age limit on the date of actually joining an appointment.
- 4) The upper age limit may be relaxed to the extent warranted and justified while making appointment on compassionate grounds of sons, daughters, wives, wards etc. of Railway servants who die while in service or are medically incapacitated. The General Managers may also relax the age limit while making recruitment of outstanding sportsmen against the sports quota and against cultural/scouts/guides quota.

➤ Financial upgradation under MACP Scheme:

- (1) Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) was introduced w.e.f. 01/09/2008 replacing ACP Scheme/1997 with a view to mitigate stagnation.
- (2) There shall be three financial upgradations under the MACPS, counted from the direct entry grade on completion of 10, 20 and 30 years service respectively. Financial upgradation under the Scheme will be admissible whenever a person has spent 10 years continuously in the same grade-pay/Level.
- (3) Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. The pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation.
- (4) There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. At the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.
- (5) 'Regular service' for the purposes of the MACPS shall commence from the date of joining of a post in direct entry grade on a regular basis either on direct recruitment basis or on absorption/re-employment basis. Service rendered on adhoc/contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into reckoning.
- (6) Past continuous regular service in another Government Department in a post carrying same grade pay prior to regular appointment in a new Department, without a break, shall also be counted towards qualifying regular service for the purposes of MACPS only (and not for the regular promotions). However, benefits under the MACPS in such cases shall not be considered till the satisfactory completion of the probation period in the new post.

➤ T.A. Entitlements on Transfer:

TA on Transfer includes 4 components: -

- a) Travel entitlement for self and family
- b) Composite Transfer and packing grant @ 80% of the basic pay, in case of transfer involving a change of station located at a distance of or more than 20 kms from each other. In cases of transfer to stations which are at a

distance of less than 20 kms from the old station and of transfer within the same city, one third of the composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved.

- c) Reimbursement of charges on transportation of personal effects at the prescribed rates and
- d) Reimbursement of charges on transportation of conveyance.

➤ **Joining Time:**

- (1) Joining Time shall be granted to a Railway servant on transfer in public interest to enable him to join the new post either at the same or a new station.
- (2) No joining time is admissible in the case of temporary transfer for a period not exceeding 180 days. Actual transit *time* as in the case of journey on tour shall only be allowed.
- (3) In the cases involving transfer from one station to another and also involving change of residence, the Railway servant shall be allowed joining time 10 days, 12 days and 15 days w.r.t. the distance between the old headquarters and the new headquarters is 1000 kms or less, more than 1000 kms and more than 2000 kms respectively.
- (4) Not more than one day's joining time shall be allowed to a Railway servant to join a new post within the same 'station or which does not involve change of residence from one station to another.

➤ **Benefit under Medical attendance and treatment Rules:**

- (1) Medical attendance and treatment facilities shall be available, free of charge, to all "Railway employees", their "family members" and "dependent relatives", (as defined under Pass Rules) irrespective of whether the employees are in Group A, B, C or D, whether they are permanent or temporary, in accordance with the detailed rules as laid down in Indian Railway Medical Manual.
- (2) Medical attendance and treatment facilities, free of charge, will be admissible to all Apprentices other than those governed by the Apprentice Act, 1961, but not to their family members, on the same scale as available to Railway employees, but confined only to the extant facilities as available in Railway hospitals and health units.
- (3) For the purpose of medical attendance and treatment they may be classified according to the categories for which they are Apprentices.
- (4) For the purpose of recovery of diet charges, the stipend drawn by them should be treated as pay. No reimbursement facilities are available in non-Railway institutions or T.B institutions where beds have been reserved for Railway employees.
- (5) Free medical treatment may be accorded to all Apprentices, including those governed by the Apprentice Act, 1961, when personal injuries are caused to them by accidents arising out of and in the course of the training as Apprentices.
- (6) Criteria for Diet Charges in respect of Railway Medical Beneficiaries will be regulated as per instructions circulated under PCPO's Sl. No. 121/2018.

- **UMID** – Software developed by SCR for preparation of uniform Medical Card on Pan Indian Railway basis, for which all serving and retired employees are requested to upload details of self & dependents online.

➤ **Benefit under Leave Rules:**

- (1) Apprentice Mechanics in Railway Workshop may be granted leave on full stipend for a period not exceeding 16 days and on half stipend on medical certificate for a period not exceeding 20 days in any year of apprenticeship.
- (2) Apprentices under training for Group C posts in all other departments who are posted to supervisory posts after training such as Apprentice Train Examiners, Apprentice Permanent Way Inspectors, Stores apprentices etc. may be granted leave like Apprentice Mechanics.
- (3) Trade apprentices may be granted leave on full stipend for a period not exceeding 12 days and leave on half stipend on medical certificate for a period not exceeding 15 days in any year of apprenticeship.
- (4) In all cases, leave will be non-accumulative and no leave shall be granted if it would interfere with the training.
- (5) On subsequent absorption, without a break, if the period of apprenticeship or training as probationer, is treated as service, recalculation of leave may be allowed as is permissible under the normal operation of the rules.
- (6) A railway servant permanent or temporary other than one who is serving in a railway school shall be entitled to 30 days leave on average pay in a calendar year.
- (7) A railway servant, permanent or temporary including the one who is serving in a railway school, shall be entitled to leave on Half Average Pay of 20 days in respect of each completed year of service.

- (8) A female railway servant (including an apprentice) with less than two surviving children may be granted Maternity Leave by an authority competent to grant leave for a period of 180 days from the date of its commencement.
- (9) A male Railway servant (including an apprentice) with less than two surviving children, may be granted Paternity Leave by an authority competent to grant leave for a period of 15 days, during the confinement of his wife for childbirth, i.e., up to 15 days before, or up to six months from the date of delivery of the child.
- (10) An adoptive mother on the railways with less than two surviving children may be granted leave of 180 days as 'Child Adoption Leave' on adoption of a child upto one year of age, on the lines of maternity leave admissible to natural mothers.
- (11) A female railway servant and single male railway servant (means an unmarried or widower or divorcee railway servant) having minor children below the age of eighteen years (upto the age of 22 years in case of disabled children) may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave, for a minimum period of 5 days and the maximum period of two years (i.e. 730 days) during the entire service for taking care of upto two children, whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness etc.
- (12) Work related illness and injury leave (WRIL): For illness and injury that is attributable to or aggravated in the performance of in consequence of official position official duties with full pay and allowance during the entire period of hospitalization.
- (13) Study leave to study scientific, technical or similar problems or to undergo special courses of instruction. Such leave is not debited against the leave account.
- (14) Encashment of Leave on Average Pay up to 10 days along with Railway Pass while in service.

➤ **Benefit under Pass Rules:**

- (1) 1 set of pass per year up to the end of 5th year of railway service and 3 sets per year after 5 years of Railway service. In addition, 4 sets of Privilege Ticket Orders per year are admissible.
- (2) Free travelling facility in SL/II Class to the ward of Railway employees called for written test/viva-voce for appointment on compassionate grounds for the first time.
- (3) A Railway servant summoned for interview in connection with the filling of a post on the railway on which he is employed may however be issued a duty pass. When called upon to appear before Selection Boards constituted to fill vacancies by Selection, the staff on leave are to be granted free passes. The period of journey and the stay at the place of selection will not be treated as duty.
- (4) In cases where a railway servant falls seriously ill outside the Zonal Railway on which he is working and is referred to a hospital located on another station for specialised treatment by the Railway Medical Officer, he may be given a Special Pass available from that place to the location of the hospital/dispensary to which he has been referred and back to the same place.
- (5) Persons appointed as trainees or apprentices and draw stipend are eligible for pass for self-only.

➤ **Benefits for Running staff:**

- (1) Running staff viz. ALP/LPs/Guards/Shunters, are entitled to Running Allowances at the prescribed rates for the performance of duties directly connected with charge of moving trains and includes a "Kilometrage Allowance" and "Allowance in lieu of kilometrage" but excludes special compensatory allowances.
- (2) 30% of the basic pay of the running staff will be treated to be in the nature of pay representing the pay element in the Running Allowance.
- (3) Running staff are entitled to Kilometrage Allowance for the performance of running duties. In addition, they are entitled to Special Compensatory Allowances, viz. (i) Allowance in lieu of Running Room facilities, (ii) Breach of rest allowance, (iii) Outstation (Detention) Allowance, (iv) Outstation (Relieving) Allowance, (v) Accident Allowance and (vi) An officiating Allowance when undertaking duties in higher grades of posts open to running staff or in stationary appointments.
- (4) 30% of the basic pay of running staff shall be reckoned as pay for the following purposes :
 - (a) Entitlement to Passes and P.T.Os.
 - (b) Medical attendance and treatment.
 - (c) Educational assistance.
 - (d) Fixation of pay in stationary posts.
 - (e) Compensatory (City) Allowance,

- (f) House Rent Allowance.
 - (g) Entitlement to quarter.
 - (h) Recovery of rent for quarters.
 - (i) Dearness Allowance/Addl. Dearness Allowance.
 - (j) Overtime Allowance,
 - (k) Leave Salary.
- (5) For the purpose of retirement benefits, 55% of basic pay shall be taken into account in the case of running staff retired/retiring on or after 1-4-1979. 55% of basic pay shall also be reckoned as pay for the purposes of recovery of subscription towards Provident Fund.
 - (6) When running staff are on leave (including casual leave) they shall be paid their leave salary based on their basic pay plus 30% thereof and the other allowances including Dearness Allowance/Addl. Dearness Allowance due on such basic pay plus 30% thereof.
 - (7) For the purpose of deduction of Income-Tax, 30% of the actual Running Allowance earned by the running staff shall be reckoned as pay and the balance 70% of the Running Allowance shall be exempted under section 10(14) of the Income-Tax Act, 1951, with effect from the financial year 1982-83 (Assessment Year 1983-84).

➤ **Eligibility for Allotment of Railway Quarters:**

Sl. No.	Level as per 7 th PC	Eligible for Quarters
1.	Staff with Grade Pay equal to or less than Rs. 1800 (L-1)	Type –I
2.	Staff with Grade Pay more than Rs. 1800 (L-1) and upto 2400 (L-4)	Type – II
3.	Staff with Grade Pay more than Rs. 2400 (L-4) and up to 4200 (L-6)	Type –III
4.	Staff with Grade Pay more than Rs. 4200 (L-6)	Type –IV
5.	Gazetted Offices with Grade Pay less than Rs. 6600 (L-11)	Type –IV
6.	Gazetted Officers with Grade Pay Rs. 6600 (L-11)	Type-IV Special
7.	Gazetted Officers with Grade Pay more than Rs. 6600 (L-11)	Type –V

➤ **Other benefits:**

- (1) During the period of training apprentices/trainees are entitled to such stipend and allowances as may be prescribed for them from time to time.
- (2) Permanent and temporary railway servants, who fulfill the terms and conditions of recruitment to various categories of apprentices/trainees as applicable to outsiders, may be allowed to compete for appointment as apprentices/trainees along with outsiders and may be granted pay equivalent to the rate of stipend laid down for that particular category of Apprentices or their substantive pay as admissible to them from time to time whichever is higher. Both permanent and temporary railway servants appointed as apprentices will also be granted house rent allowance during the period of their apprenticeship on the basis of their pay as apprentices.
- (3) Apprentice mechanics may be granted travelling allowance applicable to the category to which they are apprentices in respect of the period of their absence from HQ in connection with their training provided they are required to undertake such journey as part of the training and that free board is not provided.
- (4) The apprentices should be absorbed in the working posts on the working day following the date of completion of the apprenticeship/ training period. The suitability of the apprentices for absorption against working post should be judged well in advance of the expiry of the apprenticeship/training period. In case where there is delay in holding examinations, valuation of answer books, issue of office orders etc. owing to administrative reasons, the period intervening the date of completion of the apprenticeship training period as extended period of training apprenticeship and the apprentices should be paid stipend for that. In no case an apprentice should be absorbed against a working post with retrospective effect.
- (5) Except as Otherwise provided in his service agreement the apprenticeship shall be liable to termination by the Railway Administration on one week's notice. However, if the Apprentice is one to whom the provisions of the Industrial Dispute Act, 1947, apply he shall be entitled to notice or Wages in lieu thereof in accordance with the provisions of that Act.

- (6) Apprentices will be governed, by the provisions of workmen's Compensation Act, Factories Act, 1948 and Industrial Disputes Act, 1947, as may be applicable in each case.
- (7) All permanent and temporary staff are covered under RS(D&A) Rules.
- (8) Consideration for appointment compassionate grounds in favour of the spouse or dependent family member of the ex-employee in case of death or on retirement on medical grounds.
- (9) Various Allowances under the provisions of rules and grant of annual increment.
- (10) Facilities of Railway Accommodations as per entitlement as well as retention of railway accommodation in the previous place of posting.

➤ **Redressal of Staff Grievances:** Following machineries are functioning in Eastern Railway to redress staff grievances:

- a) Staff Grievances Cell constituted at Division/extra-division/HQrs. levels,
- b) Through CPGRAM & CPENGRAM portals,
- c) By way of representations,
- d) By way of putting grievances in Grievance Register,
- e) Organisation of staff grievance camp by Welfare Officer,
- f) Nivaran,
- g) Through Union/Association,

➤ **Staff Benefit Fund:**

- (1) Staff Benefit Fund was established on the India Railways in 1931.
- (2) Over the years, the Fund has grown in stature and on date, the following activities are financed out of the fund for the welfare of the Railway employees and their children:
 - a) Education,
 - b) Scholarship for higher technical/ professional education of Girl children of staff in grade pay up to GP 2,400/Level-4,
 - c) Scholarship for higher technical/ professional education of Male children of staff in grade pay up to GP 2,400/Level-4,
 - d) Women empowerment activities including seminar, camps, training programmes and gender sensitization camps etc.,
 - e) Recreation other than sports,
 - f) Recreational facilities at Institutes and Clubs etc.,
 - g) Promotion of Cultural Activities,
 - h) Relief of distress, sickness, etc for staff in grade pay up to GP 4600/Level-7,
 - i) Sports activities,
 - j) Scouts & Guides activities,
 - k) Indigenous system of medicine including Homoeopathy,
 - l) Immediate relief in times of crisis arising out of floods, famines, landslides, fire or any other calamity,
 - m) Developing occupational skills of physically/mentally challenged railway employees and their wards including purchase of wheel chairs, other aids, special software etc., and organizing workshops, seminars, camps etc. and
 - n) Miscellaneous - Support for improvement in holiday homes, rest houses, entertainment/ information facility, viz. Colour TV; electrical appliances/ maintenance fund for recurring expenses on such facilities.

- **Holiday Homes:** Holiday Homes have been established as a measure of amenity of staff. The list of holiday homes under Eastern Railway for non-gazetted railway employees is as under:

Sl. No.	Place	No. of Suites	Charges	Address for Application
1.	Nainital	4	Rs.30/- per day.	GM(P), Eastern Railway, 17, N.S. Road, Kolkata – 1
2.	Darjeeling	2		
3.	Haridwar	4		
4.	Baidyanath Dham	2		
5.	Varanasi	2		

In addition, there are seven Holiday Homes/Rest Houses are functioning in Eastern Railway for employees and their family members under the ages of Central Staff Benefit Funds, viz. Mumbai & Vellore (for medical purposes @ Rs.250/- & Rs. 200/- & 250/- per day respectively), Puri (@ Rs. 300/- per day), Digha (@ Rs. 300/- per day), Pelling (@Rs. 300/- per day), Gangtok (@Rs. 300/- per day) and New Delhi (@ Rs. 300/- and Rs. 100/- [on duty] per day).

- **Wages system of wages payment in Railways:**

Wages system of wages payment in Railways is guided by the act called The Payment of Wages Act, 1936. According to section 4 of the act, every person responsible for the payment of wages under section 3 shall fix periods (in this Act referred to as wage-periods) in respect of which such wages shall be payable and no wage-period shall exceed one month. The act also provides that the wages of every person employed upon or in (a) any railway, factory or [industrial or other establishment] upon or in which less than one thousand persons are employed, shall be paid before the expiry of the seventh day, (b) any other railway, factory or [industrial or other establishment], shall be paid before the expiry of the tenth day, after the last day of the wage-period in respect of which the wages are payable.

In view of above, different wage-periods have been fixed, which may be either calendar month or communicating months, as the case may be, depending upon operation of the said establishments. Further, assume attendance for the workshop staff is normally not permissible under the extant instructions. However, in exceptional cases such as important festivals, assume attendance for workshops staff may be permitted. But, the same is not more than 2 or 3 occasions in a year and that too with the approval of Railway Board with concurrence of FA&CAO.

Further, advance payment of wages for the purpose of important festivals is permissible. But, if such advance payment is made before expiry of wage-period, Board's sanction is pre-requisite.

- **Minimum wages Act:** Aims and objectives of the act –

1. To secure minimum rates of wages in those categories of employment where wages are low such as unorganized labour,
2. To lay down the procedure for regulating the hours of work, payment of wages and also prompt payment of wages.
3. Necessary deductions that can be made from the pay of workers.
4. A worker governed under this Act can be fined for certain acts & omissions viz. absence from duty, negligence, smoking, damage to work etc. Under this act 26 days should be taken as a month for the purpose of calculating wages at the daily rate.

- **Payment of Wages Act, 1936:** Aims and objectives of the act –

1. For payment of wages promptly and at regular intervals
2. Payment of wages without unauthorized deduction
3. Permissible deductions

It also provides guidelines regarding wages, responsibility for payment of wages, fixation of wages, time of payment of wages, authorized deductions, fines etc.

- **Productivity Linked Bonus (PLB):** The scheme for grant of productivity linked bonus to railway employees has been introduced in 1979. It covers all non-gazetted staff including substitutes with temporary status. The upper ceiling limit of wage for calculating PLB has been fixed Rs.3500/-.The productivity is determined solely on the basis

of Revenue Traffic Tonne Kilometres each year as derived from the relevant audited statement of statistics of the Indian Railways. PLB is to be intended as substantial motivation towards achieving higher productivity.

- **Incentive Scheme:** For increasing the productivity of Workshops and Production Units, incentive scheme has been in existence in railways for the employees including supervisors. The scheme was initially introduced in CLW and was extended later to other railway workshops & production units. Essential feature of the scheme is the Time for measuring the work and productivity.
- **Various benefits admissible to Divyang (PwD) Railway Employees:**
 - (1) Transport Allowance at double the rate prescribed.
 - (2) Exempted from passing the Type writing test under certain conditions.
 - (3) Protection of Section 47 of PWD Act, 1995 in case of seeking retirement on medical grounds and grant of leave.
 - (4) Four day additional Casual Leave.
 - (5) Identification of jobs for disabled employees.
 - (6) Post recruitment and pre-promotional training.
 - (7) Grievance Redressal Cell for disposal of grievances within a reasonable time.
 - (8) Grant of 10 days special casual leave in a calendar year, subject to exigencies of work, for participating Conference/Seminar/Workshops/Trainings related to disability & development.
 - (9) Preference in transfer/posting.
 - (10) Preference in Govt. accommodation.
 - (11) Accessibility and barrier free environment at work place.
 - (12) Provision of compassionate appointment of spouse of dependent family member in case of retirement on medical grounds.
 - (13) Creation of a Special Supernumerary post for the employee declared medically decategorised and an alternative job is not ready available as per section 47 of PWD Act, 1995.
 - (14) Reservation in promotion to the extent of 4%.
- **Prevention of Sexual Harassment of Woman Employees:**
 - (1) All the Divisions and Workshops along with Eastern Railway Hqrs. have respective Internal Complaints Committees for prohibition of sexual harassment on working women at work place constituted in terms of Board's guidelines aligned in line of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 & Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013. Its main provisions are incorporated under Rule 3C of Railway Services (Conduct) Rules, 1966.
 - (2) Special leave up to a period of 90 days may be granted to an aggrieved female Railway Servant on the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, during the pendency of inquiry under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the leave granted to the aggrieved female Railway Servant under this rule shall not be debited against the leave account.

Terminal Benefits

- (1) **CGIS-1980:** The rate of subscription for non-gazetted staff is Rs. 30/- and for Gazetted staff Rs. 60/- & Rs. 120/- , as the case may be. In case of death, Payment of CGIS @ Rs. 30,000/- + with savings & interest thereof for non-gazetted staff and Rs. 60,000/- and Rs.1,20,000 + with savings & interest thereof for Gazetted employees.
- (2) **Cash Payment in lieu of unutilized leave:** The authority competent to grant leave shall, suo-motu, issue an order granting cash equivalent of leave salary for both leave on average pay (LAP) and leave on half average pay (LHAP), if any, at the credit of the Railway servant on the date of retirement payable in one lump sum, subject to a maximum of 300 days. In case of resignation or quitting of service , A railway servant may be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of leave on average pay at his credit on the date of cessation of service to the extent of half of such leave at his credit subject to a maximum of 150 days.

- (3) Retirement Gratuity & Death Gratuity: This is payable to the retiring Government servant. A minimum of 5 years' qualifying service and eligibility to receive service gratuity/pension is essential to get this one time lump sum benefit. Retirement gratuity is calculated @ 1/4th of a month Basic Pay plus Dearness Allowance drawn on the date of retirement for each completed six monthly period of qualifying service. There is no minimum limit for the amount of gratuity. The retirement gratuity payable for qualifying service of 33 years or more is 16 times the Basic Pay plus DA, subject to a maximum of Rs. 20 lakhs. If a railway servant dies while in service, the amount of death gratuity shall be paid to the family in the manner indicated in the Table below:

Length of qualifying service	Rate of gratuity
(i) Less than one year	2 times of emoluments
(ii) one year or more but less than 5 years	6 times emoluments
(iii) 5 years or more but less than 20 years	12 times of emoluments
(iv) 20 years or more	Half of emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to maximum of thirty-three times emoluments.

- (4) Additional Benefit on death/disability of Government servant covered by NPS: Railway employees covered under NPS in case of death/disability, the family would be eligible for additional relief in the form of Family Pension and Death Gratuity, as admissible under Pension Rules.

(5) TA entitlements on retirement:

- Travel entitlement for self and family
- Composite Transfer and packing grant @ 80% of the basic pay, in case of transfer involving a change of station located at a distance of or more than 20 kms from each other. In cases of transfer to stations which are at a distance of less than 20 kms from the old station and of transfer within the same city, one third of the composite transfer grant will be admissible, provided a change of residence is actually involved.
- Reimbursement of charges on transportation of personal effects at the prescribed rates and
- Reimbursement of charges on transportation of conveyance.

(6) Retention of Railway Quarters:

1.	Retirement and VR	Permitted to retain non-earmarked railway accommodation for <u>a period of 4 months</u> at normal rent/flat rate of licence fee and the <u>next 4 months</u> at the rate double the normal rent/ double the flat rate of licence fee
2.	In case of death while in service	Maximum period upto 2 years on normal rent
3.	Retired on grounds of total medical incapacitation and in whose cases compassionate appointment of any of their family members is in process	Maximum period upto 2 years on normal rent from the date of retirement
4.	In case of missing railway employees	Maximum period of retention on normal rent as 3 years

- (7) Fixed Medical Allowance (FMA): FMA @ Rs. 1000/- pm will be paid to pensioners/family pensioners only after submission of the undertaking to Pension Sanctioning Authority (PSA), subject to fulfilment of two following mandatory conditions: (a) the pensioner/family pensioner is residing beyond 2.5 Kms from the nearest health unit, & (b) the pensioner/family pensioner is not availing the facility of OPD (except in cases of specified chronic diseases).

- (8) RELHS-97: Medical Facilities to retired railway employees & their family members and the Spouses of employees die in harness under RELHS-97 on prescribed contributions.

- (9) **Cashless Treatment Scheme in Emergency (CTSE):** A scheme for cashless treatment in empanelled hospitals for retired employees and their dependent family members in emergency situations is also available on contributions. Under this scheme, a "CTSE Plastic Photo Identity Card' (CTSE Card)" will be issued to RELHS beneficiaries
- **New Pension Scheme (NPS):**
- a) NPS has come into operation w.e.f. 01/01/2004.
 - b) The system is mandatory for all Govt./railway servants who join Govt./Railway service on or after 01/01/2004.
 - c) It has two Tiers i.e. Tier-I and Tier-II.
 - d) In Tier-I, Govt./Railway servants shall compulsorily make a contribution at the rate of 10% of the basic pay and DA and a contribution at the rate of 14% will be made by the Govt.
 - e) The contributions and the investment returns would be deposited in a non-withdrawable pension tier-I account.
 - f) The provisions of defined benefit pension and SRPF/GPF would not be available to new recruits in the Central Govt. service joining w.e.f. 01/01/2004.
 - g) A govt./Railway servant covered under the new system can exit at or attaining the age of 60 years from tier-I.
 - h) At exit, it would be mandatory to invest 40% of the pension wealth to purchase an annuity from an IRDA regulated life insurance company which will provide for pension for the lifetime of the employee and dependent parents/spouse at the time of retirement.
 - i) Every individual subscriber is issued a Permanent Retirement Account Number (PRAN) card and has a 12 digit unique number. In case of the card being lost or stolen, the same can be reprinted with additional charges.
 - j) Additional Relief on death/disability of Government servants covered by New Defined Contribution Pension System (NPS) in the form of family/disability pension as well as DCRG.
- k) **Post Retirement Complementary Pass (PRCP):** Non-gazetted employees with railway service of 20 years & more are eligible to get 2 sets of PRCP for self, wife/husband and children only subject to same conditions applicable to railway employees in service.
- l) **Holiday Homes:** Retired non-gazetted Railway employees may be permitted to occupy Railway holiday homes on stipulated terms and conditions @ Rs. 60/- per day.. The retired Railway servants shall be given confirmed booking of Holiday Homes during periods other than Summer Vacations, Dussehra, Pooja & Christmas Holidays, seven days prior to the date of occupation and the confirmed bookings shall not be cancelled during the last seven days preceding the date of occupation, in preference to a serving Railway employee. This facility will also be available to the employees who resign technically from railway service for the purpose of permanent absorption in Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies and are entitled to Post Retirement Complimentary Passes.

Chapter – 8

Dos & Don'ts for New Recruits

Dos	Don'ts
Furnish correct/relevant information in the Attestation form.	Don't furnish false information regarding caste and other details
Fill up S-1/PRAN form. (If PRAN no. is already available, should not fill up the form again and provide the PRAN number & other details for further recovery)	Don't violate safety norms.
Furnish Self & family declaration.	Don't send the copy of representation on any service matter to outside authorities. This is most objectionable practice, contrary to official propriety and subversive of good discipline.
Furnish correct marital status.	Do nothing which is unbecoming of a railway servant.
Fill up Form for Identity Card.	Don't place under any financial or other obligations to any individual or organisation which may influence in the performance of official duties
Abide by all provisions under the Railway Services (Conduct) Rules, 1966.	Don't do anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;
Furnish Nomination form.	Don't misuse his/her position as railway servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for self/ family or his/her friends; don't place self under any financial or other obligations to any individual
Enroll for Medical Facility available under Railway Rules.	Don't indulge in any act of sexual harassment of any woman at any work place.
Ensure all entries in the SR (Service Record) are made as per documents furnished.	Don't be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics and also not to take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.
Maintain high ethical standards and honesty.	Don't engage himself/herself as a Railway servant or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India.
Every Railway servant who is in charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at the work place.	Don't give or take or abet the giving or taking of dowry; or demand directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.
Maintain political neutrality.	Failure of Railway servants to look after their families is liable to be taken up under DAR.

APPENDIX I

THE RAILWAY SERVICES (CONDUCT) RULES, 1966

1.Short title. -(1) These rules may be called the Railway Services (Conduct) Rules 1966.

(2) They shall come into force at once.

2. Definition. - In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) 'Government' means, in relation to -

- (i) gazetted officers holding posts in the Railway Board, the President;
- (ii) other gazetted officers, the Railway Board;
- (iii) non-gazetted officers, in the Railway Board, the Secretary, Railway Board;
- (iv) other non-gazetted officers in offices directly under the administrative control of the Railway Board, the Heads of the offices concerned; and
- (v) other non-gazetted officers, the General Managers of the Railway Administrations concerned:

Provided that for purposes of sub-rules (2) and (3) of rule 5, sub-rule (i) of rule 8, sub-rule (i) of rule 10, rule 12, rule 14, **sub-rules (1) of rule 15**, sub-rule (3) of rule 16, sub-rule (1) of rule 19 and rule 21, 'Government' means the Railway Board in the case of all non-gazetted railway servants.

(Authority: Railway Board's letter No.E (D&A) 2006/GS 1-9 dated 01.12. 2006)—ACS NO—101

(b) "railway servant" means a railway servant as defined in rule 103 (43*) of the Indian Railway Establishment Code.

*Railway Servant means a person who is a member of a service or who holds a post under the administrative control of the Railway Board and includes a post in the Railway Board. Persons lent from a service or post which is not under the administrative control of the Railway Board to a service or post which is under such administrative control do not come within the scope of this definition.

Explanation.- A railway servant whose services are placed at the disposal of a company, corporation, organisation or a local authority shall, for the purposes of these rules, be deemed to be a railway servant notwithstanding that his salary is drawn from sources other than the Consolidated Fund of India.

(c) "means of family" in relation to a railway servant includes -

- (i) the wife or husband, as the case may be, of the railway servant, whether residing with the railway servant or not but does not include a wife or husband, as the case may

- be, separated from the railway servant by a decree or order of a competent court;
- (ii) son or daughter or step-son or step-daughter of the railway servant and wholly dependent on him, but does not include a child or a step-child who is no longer in any way dependent on the railway servant or of whose custody the railway servant has been deprived by or under any law;
- (iii) any other person related whether by blood or marriage to the railway servant or to the railway servant's wife or husband, and wholly dependent on the railway servant.

Railway Ministry's decision. -- The son/daughter will come within the purview of this rule only if he or she is dependent upon the Railway servant.

(E(D&A) 77 GS1-13 dot. 14-7-1977.)

3. **General.** -- (1) Every railway servant shall at all times-

- (i) maintain absolute integrity;
- (ii) maintain devotion to duty;
- (iii) do nothing which is unbecoming of a railway servant;
- (iv) commit himself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values;
- (v) defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;
- (vi) maintain high ethical standards and honesty;
- (vii) maintain political neutrality;
- (viii) promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties;
- (ix) maintain accountability and transparency;
- (x) maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section;
- (xi) maintain courtesy and good behaviour with the public;
- (xii) take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;
- (xiii) declare any private interests relating to his public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest;
- (xiv) not place himself under any financial or other obligations to any individual or organisation which may influence him in the performance of his official duties;

- (xv) not misuse his position as railway servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or his friends;
- (xvi) make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;
- (xvii) act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the under-privileged sections of society;
- (xviii) refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;
- (xix) maintain discipline in the discharge of his duties and be liable to implement the lawful orders duly communicated to him;
- (xx) maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information, disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the State, strategic, scientific or economic interests of the State, friendly relation with foreign countries or lead to incitement of an offence or illegal or unlawful gain to any person;
- (xxi) perform and discharge his duties with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities.

(Authority - Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS1-3 dated 12.01.2015)..acs no.125

(2) (i) Every railway servant holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all railway servants for the time being under his control and authority;

(ii) no railway servant shall, in the performance of his official duties, or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgement except when he is acting under the direction of his official superior;

(iii) the direction of the official superior shall ordinarily be in writing, and where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter; and

(iv) a railway servant who has received oral direction from his official superior, shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.

Explanation I. —A railway servant who habitually fails to perform the task assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected of him shall be deemed to be lacking in devotion to duty within the meaning of clause (ii) of sub-rule (1).

Explanation II. —Nothing in clause (ii) of sub-rule (2) shall be construed as empowering a railway servant to evade his responsibilities by seeking instructions

from or approval of, a superior officer or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities.

Railway Ministry's decision. —In the light of the provisions of Rule 3(2)(ii) it is impressed upon all Railway servants that—

- (i) Oral instructions should not, as far as possible, be issued by senior officers to their subordinates;
- (ii) if the oral instructions are issued by any senior officer they should be confirmed by him in writing immediately thereafter;
- (iii) if a junior officer seeks confirmation to the oral instructions given by the senior, the latter should confirm it in writing, whenever such confirmation is sought;
- (iv) a junior officer who has received oral orders from his superior officer should seek confirmation in writing as early as practicable;
- (v) whenever a member of the personal staff of Minister communicates an oral order on behalf of the Minister, it should be confirmed by him in writing immediately thereafter;
- (vi) If junior officer received oral instructions from the Minister or from his personal staff and the orders are in accordance with the normal rules, regulations or procedures, they should be brought to the notice of the Secretary, or the concerned Members of the Railway Board or the Head of the Department, as the case may be, for information.
- (vii) if a junior officer received oral instructions from the Minister or from his personal staff and the orders are not in accordance with the norms, rules, regulations or procedures, they should seek further clear orders from the secretary, the concerned Member of the Railway Board or the Head of the Department, as the case may be, about the line of action to be taken, stating clearly that the oral instructions are not in accordance with the rules, regulations, norms, or procedures.

(No. E(D&A) 78 GSI-9 dt. 14-12-78).

3 A. Promptness and Courtesy

No Railway servant shall—

- (a) in the performance of his official duties, act in a discourteous manner;
- (b) in his official dealings with the public or otherwise adopt dilatory tactics or willfully cause delays in disposal of the work assigned to him.

3 B. Observance of Government's policies.

Every railway servant shall, at all times—

- (i) act in accordance with the Government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage;
- (ii) observe the Government's policies regarding prevention of crime against women.

(Authority: Railway Board's letter No. E (D & A) 95 GS1-5 dt.14.9.95)

3 C. Prohibition of sexual harassment of working women.

- (1) No Railway servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at any work place.
- (2) Every Railway servant who is incharge of a work place shall take appropriate

steps to prevent sexual harassment to any woman at the work place.

Explanation. - (I) For the purpose of this rule,-

- (a) "sexual harassment" includes any one or more of the following acts or behaviour (whether directly or by implication) namely :-
 - (i) Physical contact and advances; or
 - (ii) a demand or request for sexual favours; or
 - (iii) making sexually coloured remarks; or
 - (iv) showing pornography; or
 - (v) any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of a sexual nature.
- (b) the following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment :-
 - (i) implied or explicit promise of preferential treatment in employment; or
 - (ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in employment; or
 - (iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or
 - (iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or
 - (v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.
- (c) "workplace" includes,-
 - (i) any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central Government;
 - (ii) hospitals or nursing homes;
 - (iii) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto;
 - (iv) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey;
 - (v) a dwelling place or a house."

(Authority - Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS1-4 dated 12.01.2015)—acs no.124

4. Employment of near relatives of railway servants in Company or firm enjoying Government patronage. —(1) No railway servant shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company or firm;

(2) (i) No Group A Officer shall, except with the prior sanction of the Government permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has official dealings or in any other company or firm having official dealings with the Government:

Provided that where the acceptance of the employment cannot await prior permission of the Government or is otherwise considered urgent, the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Government and the fact of such acceptance shall at once be reported to the Government.

(ii) A railway servant shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm, intimate such acceptance to the Government and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with that company or firm:

Provided that no such intimation shall be necessary in the case of a Group 'A' Officer if he has already obtained the sanction of, or sent a report to the Government under clause(i).

(2) No railway servant shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person, if any member of his family is employed in that company or firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the railway servant shall refer every such matter or contract to his superior officer or authority and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of such officer or authority.

5. Taking part in politics and elections. —(1) No railway servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(2) It shall be the duty of every railway servant to endeavour to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be subversive of the Government as by law established and where a railway servant is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of or assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Government.

(3) If any question arises whether a party is a political party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-rule (2) the decision of the Government thereon shall be final.

(3) No railway servant shall canvass, otherwise interfere with, or use his influence in connection with or take part in, an election to any legislature or local authority.

Provided that —

- (i) a railway servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;
- (ii) a railway servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation. – The display by a railway servant on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub-rule.

Railway Ministry's decision. – (1) Railway servants wishing to join the Bharat Sevak Samaj should obtain prior permission from the Head of the Department. This permission will not, however, absolve them from the observance, at all times, of the rules and instructions relating to the conduct and behaviour of the Railway servant.

(E (D & A) 64 GS1 dot. 27-05-1964.)

Railway Ministry's decision. – (2) The Railway servants should not only be impartial but they should appear to be impartial in relation to the elections. They should not take part in any election campaign nor should they canvass. They should always take scrupulous care not to lend their names, official position of authority to assist one group as against another. Any disregard of these instructions will be considered as serious act of indiscipline. Their attention is drawn to the provisions in section 134 – A of the Representation of the People Act, 1951 which reads as under:

If any person in the service of the Government, acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend upto 3 months or with fine or with both.

(E (D & A) 66 GS1-15 dt. 27-12-66)

Railway Ministry's decision. —(3) Political neutrality of Railway servants—It is essential that Railway servants should not only maintain political neutrality but should also appear to do so and they should not participate in the activities of, or associate themselves with any organization in respect of which there is the slightest reason to think that the organization has a political aspect or with organisations banned by the Government.

(E (D & A) 69 GS1-25 dt. 31-1-1970).

(NS Policy/19 dt. 11-3-1976).

6. Joining of Associations or Unions by Railway Servants. – No railway servants shall join, or continue to be a member of an association or union the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

Note. – It is not permissible for a gazetted railway servant to join any association of non-gazetted railway servant like a Railway Employees Union,. When a non-gazetted railway servant who is a member of a Railway Employees' Union is promoted to gazetted rank, either in an officiating or permanent capacity he shall resign his membership of such Union. If, however, the officer concerned satisfies the General Manager of the railway concerned that by such resignation he will lose financially or otherwise under any beneficent scheme organized by such Union such

as death or accident insurance, he may be permitted to continue as an ordinary member, but not as office bearer or representative, of that Union. The responsibility for satisfying the General Manager in this respect will rest with the officer concerned.

7. Demonstration. —No railway servant shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence.

Railway Ministry's decision. — (1) Where peaceful and orderly meetings or demonstrations are held during the lunch interval without obstructing in any manner the free passage to and from the office, there would be no objection to the holding of such meetings or demonstrations nor would the participating staff render themselves liable to disciplinary action thereby. The same position will apply in respect of peaceful and orderly meeting and demonstration during half an hour interval prior to the start of working hours and the half an hour interval succeeding the close of working hours.

Railway Ministry's decision. —(2) The position regarding the scope of this Rule is clarified as under:

- (i) Demonstration, meetings and processions, which are orderly and peaceful and are held outside office premises and outside working hours, should not be interfered with.
- (ii) The wearing of badges while at work should not be interfered with unless the badges have inscriptions or slogans which may offend against the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or which may amount to contempt of court, defamation or incitement to an offence. The colour of the badge or arm band should not be considered in any case.
- (iii) Demonstration or the raising of slogans or other such disorderly conduct should not be permitted within office premises and disciplinary proceedings should be started against those found indulging in such action within office premises.

(No. E(D & A) 63 GS1-3 dt. 27-4-1964.)

Railway Ministry's decision.—(3) It will be in order to take disciplinary action in respect of demonstration anywhere, even far away from office premises and at any time even on a holiday , resorted to by a railway servant, even in the capacity of a Trade Union worker, if that activity could be proved to be one falling within the prohibitive activities listed in this rule.

(No. E(L)66 UT 1-79 dt. 12-1-1966.)

Railway Ministry's decision. — (4) Peaceful and orderly meetings and demonstrations held during lunch intervals or during half an hour interval prior to the start of working hour and the half an hour interval succeeding the close of the working hours, without obstructing in any manner the free passage to and from the office do not infringe the provisions under this rule.

(No. E(L) 77 UT 1-79 dot. 26/28-7-1967.)

Railway Ministry's decision.—(5) The principle of 'No work no Pay' should not be circumvented in any way including by grant of leave to a railway servant for the period of absence caused due to participation in a strike.

(No. E(LR) II77 ST 1-126 dt. 15-7-1978.)

Railway Ministry's decision. – (6) If an application for casual leave is presented by a railway servant specifically for the purpose of participation in a demonstration, it is open to the competent authority to refuse casual leave for this purpose. If in spite of refusal, and employee absents himself from duty, he can be treated to have been unauthorisedly absent, with all the attendant consequences of unauthorised absence.

(No. E (G) 79 LE 1-10 dt. 19-6-1980.)

8. Connection with press or other media.---

- (1) No Railway servant shall, except with the previous sanction of the Government, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of, any newspaper or other periodical publication or electronic media.
- (2) Nothing in sub-rule (1) shall apply in case a Railway servant in the bonafide discharge of his official duties publishes a book or participates in a public media.
- (3) A Railway Servant publishing a book or participating in a public media shall, at all times, make it clear that the views expressed by him are his own and not that of Government.

(Authority: Railway Board's letter No. E (D&A) 95 GS 1-6 dated 14-9-95)

9. Criticism of Government.—No railway servant shall, in any radio broadcast, telecast through any electronic media or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion—

- (i) which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Central Government or State Government ;
- (ii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any State; or
- (iii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any foreign State:

Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by a railway servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

Railway Ministry's decision.—Serving Railway employees, if they, in their individual capacity or in their capacity of office bearer of association (including federation/unions of railway employees) or editor/publishers office bearers of journals issued by such association (including federation/union) pass resolutions making statement and/or expressing opinion on issues which involve violation by the individual employees of this Rule become liable for disciplinary action.

((E (D&A) 68GS1-6 dot. 24-6-1968.)

10. Evidence before Committee or any other Authority.—(1) Save as provided in sub-rule (3) no railway servant shall, except with the previous sanction of the Government, give evidence in connection with, any enquiry conducted by any person, committee or authority.

2. Where any sanction has been accorded under sub-rule (1), no railway servant shall in the course of giving such evidence criticise the policy or any action of the Central Government or of a State Government.

3. Nothing in this rule shall apply to—

- (a) evidence given at any enquiry before an authority appointed by the government, Parliament or a State Legislature; or
- (b) evidence given in any judicial inquiry; or

(c) evidence given at any departmental inquiry ordered by authorities subordinate to the Government.

11. Communication of Official Information. - Every Railway servant shall, in performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and the rules made thereunder:

Provided that no Railway servant shall, except in accordance with any general or special order of the Government or in performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof or classified information to any Railway servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or classified information."

(Authority: Railway Board's letter No. E(D&A) 2005/GS1 dated 21.02.06)—ACS NO.97

12.Subscription.—No railway servant, shall, except with the previous sanction of the Government or of the competent authority, ask for or accept contributions to or otherwise associate himself with the raising, of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

Railway Ministry's decision.—(1) The association of Railway servants with the selling of tickets for charity show or for any purpose whatsoever attract the provisions of this rule and prior permission of the Government would be necessary for this purpose. Sale of Tickets by Railway employees to the members of the general public is likely to invite public criticism and should not be permitted.

(E(D&A) 68 GS 1-7 dt 19/22-8-1968.)

Railway Ministry's decision. —(2) The powers under this Rule may be exercised by the General Managers in respect of all staff working under them for collection of subscription for celebrating religious festivals only. Permission should be given on the specific conditions that only voluntary subscription are collected and no pressure of any kind is brought on them on the collection of these funds.

(E(D&A) 68 GS1-7 dt.30-1-1969.)

13.Gifts. —(1) Save as provided in these Rules, no Railway servant shall accept, or permit any member of his family or (any other person acting on his behalf) to accept , any gift.

Explanation. —The expression "gift' shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage

provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the govt. servant.

Note. —(1) A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift.

Note. —(2) A Railway servant shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc. having official dealings with him.

(2) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious and social practice, a Railway Servant may accept gifts from his near relatives or from his personal friends having no official dealings with him, but shall make a report to the Government, if the value of such gift exceeds –

(i) rupees twenty five thousand in the case of a Railway servant holding any Group 'A' post;

(ii) rupees fifteen thousand in the case of a Railway servant holding any Group 'B' post;

(iii) rupees seven thousand five hundred in the case of a Railway servant holding any Group 'C' post.

(Authority - Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS1-3 dated 12.01.2015)...acs no.126

(3) In any other case, a Railway servant shall not accept any gift without the sanction of the Government if the value exceeds –

(i) rupees one thousand and five hundred in the case of Railway servants holding any Group 'A' or Group 'B' post; and

(ii) rupees five hundred in the case of Railway Servants holding any Group 'C' or Group 'D' post.

(Authority: Railway Board's letter No. E(D&A)2004/GS1-2 dated 15.03.2004)—**ACS NO.91**

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2) and (3), a Railway Servant, being a member of the Indian delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries if the market value of gifts received on one occasion does not exceed rupees one thousand. In all other cases, the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

(5) A Railway Servant shall not accept any gifts from any foreign firm which is either contracting with the Government of India or is one with which the Railway servant had, has or is likely to have official dealings. Acceptance of gifts by a Railway servant from any other firm shall be subject to the provisions of sub-rule (3).

(Authority: Railway Board's letter No. E(D&A) 96 GS 1-8 dated 17.01.1997.)

Railway Ministry's decision. – 1 The acceptance of tips is misconduct and may be treated as a good and sufficient reason for taking disciplinary action.

(E (D&A) 61 GSI-15 dt. 19-9-61.)

Railway Ministry's decision. —2 Gifts received or given by a railway servant in the form of cash attract the provisions of the Rule even though it is a transaction between father and son.

(E(D&A) 64 GS1-5 dt. 25-2-65.)

Railway Ministry's decision. –3 Receipt of presents by Railway servants at the time of their marriage in form of cash, ornaments, cloths or other articles, otherwise than as consideration for marriage, from relative and personal friends and others will be regulated by the above Rule. Purchase of items of movable property for giving presents at the time of marriage or on other occasions will be regulated by Rule 18 (3), like any other transaction of movable property.

(E (D&A) 65 GS112 dt. 23-4-66.)

(E (D&A) 65 GS1-20 dt. 7-7-70.)

Railway Ministry's decision. – 4 Making or acceptance of gifts amongst "Near Relatives" which include father, mother, son, daughter etc. requires the approval of the competent authority in terms of sub rule (5) above.

(E (D&A) 69 GSI-20 dt. 5-1-70.)

Railway Ministry's decision – 5 The following are the instructions in regard to receipt, retention and disposal of gifts of high valuation received by Railway servants from foreign dignitaries and foreign firms.

1. The presents of symbolic nature like a ceremonial sword, ceremonial robe etc. may be retained by the recipient.
2. The gifts of the value not exceeding Rs. 1000/- may also be retained.
3. Railway servant shall report the receipt of gifts, the value of which exceeds Rs. 1000 to the department indicating the value. The Department will refer the matter to Toshakhana for valuation of the gifts. If it is found that the value is Rs. 1000/- or less the gift will be returned to the recipient. If however, the value exceeds Rs. 1000/- it will be retained by in Toshakhana and the recipient will, have the option to purchase it from Toshakhana by paying the difference between the value as estimated and Rs. 1000/-.
4. Acceptance of gifts from foreign firms with whom the Railway servant has had or has or is likely to have official dealing either, directly or indirectly by virtue of his official position as well as acceptance of gifts from firms which are contracting firms with the government are prohibited.

(E (D & A) 76 GSI-31 dt. 22-12-76.)

13-A. Dowry.-- No Railway servant shall ---

- (i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or
- (ii) demand directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanations:- For the purpose of this rule 'dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961.

In this Act, "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly—

- (a) by one party to a marriage to the other party to marriage; or
 - (b) by the parents of either party to a marriage or by any other person, to either party to the marriage or to any other person;
- at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dower or mahr in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies.

Explanation I. ---For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties.

Explanation II. ---The expression "Valuable security" has the same meaning as in Section 30 of the Indian Penal Code.

14. Public demonstrations in honour of Railway servants. —No railway servant shall except with the previous sanction of the Government receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meetings of entertainment held in his honour, or in the honour of any other Government servant :

Provided that nothing in this rule shall apply to ---

- (i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of a railway servant or any other Government servant on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of any Government; or
- (ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainments arranged by public bodies or institutions.

Note. —Exercise of pressure or influence of any sort on any railway servant to induce him to subscribe towards any farewell entertainment even if it is of a substantially private or informal character and the collection of subscriptions from Group 'C' and Group 'D' employees under any circumstances for the entertainment of any railway or other Government servant not belonging to Group 'C' and Group 'D' is forbidden.

Railway Ministry's decision. --- 1. Officers in Group 'A' service upto the J.A. Grade should furnish promptly particulars of all invitations received by them from foreign missions in India and accept them only after obtaining the necessary clearance from the Railway Board. Officers in Group 'B' service and below are debarred from accepting such invitations except in very rare cases. All officers, so permitted, should submit a list of any important and interesting talks or other discussions held with the representative of the foreign mission on matters of interest to the Railway Board.

(E (D&A) 57 GSI-3 dt. 8-1-57.)

Railway Ministry's decision. ---2. Railway servants should refrain from associating themselves with functions inappropriate and inconsistent with the rule of detached impartiality such as to declare buildings etc. open or to lay the foundation stones of new buildings or to allow roads, bridges, parks or public institutions such as hospitals, schools or colleges to be named after them. When occasions which have a cultural and sociological significance arise, especially in remote areas, prior permission of their superior officer should be obtained.

(E (D&A) 60 GSI-8 dt. 27-3-61.)

Railway Ministry's decision. ---3. While no subscription should be collected from class III and class IV staff when any entertainment is held in honour of a Class II or Class I Officer it is not the intention of the rule that when an entertainment is held in honour of Class III/Class IV staff, a class I or class II Officer should not attend the function as a guest by invitation or on a contributory basis.

(E (D&A) 60 GSI-8 dt. 4-11-67.)

15. Private trade or Employment.---(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) no Railway Servant shall, except with the previous sanction of the Government---

- (a) engage directly or indirectly in any trade or business, or
- (b) negotiate for, or undertake, any other employment, or
- (c) hold an elective office, or canvass office for a candidate or candidates for an elective office, in any body, whether incorporated or not, or
- (d) Canvass in support of any business of insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by any member of his family or
- (e) take part except in the discharge of his official duties, in the registration, promotion or management of any bank or other company registered or required to be registered, under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force, or of any co-operative society for commercial purposes.
- (f) participate in or associate himself in any manner in the making of-
 - i. a sponsored media (radio or television) programme; or
 - ii. a media programme commissioned by Government media but produced by a private agency; or
 - iii. a privately produced media programme including video magazine;

Provided that no previous permission shall be necessary in case where the Railway Servant participates in a programme produced or commissioned by Government media in his official capacity.

(Authority: Railway Board's Letter No. E(D & A) 96GS1-8 dated 7-1-97)

(2) A railway servant may, without the previous sanction of the Government—

- (a) undertake honorary work of a social or charitable nature, or
- (b) undertake occasional work of a literary, artistic or scientific character, or
- (c) participate in sports activities as an amateur, or

- (d) take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of an elective office) of a literary, scientific or charitable society or of a club or similar organisation the aims or objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or any other law for the time being in force, or,
- (e) take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of an elective office) of a co-operative society substantially for the benefit of railway servants, registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force.

Provided that:---

- i. he shall discontinue taking part in such activities, if so directed by the Government ; and
- ii. in a case falling under clause (d) or clause (e) of this sub-rule, his official duties shall not suffer thereby and he shall, within a period of one month of his taking part in such activity, report to the Government giving details of the nature of his participation.

(3) Every railway servant shall report to the Government if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(4) Unless otherwise provided by general or special orders of the Government, no Railway servant may accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

Explanation. –The term ‘fee’ used here shall have the meaning assigned to it in Rule 103(18)-R.I.

Railway Ministry’s decision. —(1) It is not permissible for a Railway servant to take an Insurance Agency in his own name and canvass for the same.

(E (D&A) 58 GSI-40 dt. 7-3-58.)

Railway Ministry’s decision. – (2) Railway servants should not ordinarily be allowed to accept part time employment whether under Government or elsewhere, even though such employment is after office hours.

(9E(D&A) 58 GSI-29 dt. 16-1-59.)

Railway’s Ministry’s decision.---(3) Railway servants, holding recognized qualification for any system of medicine may be granted permission by the Heads of Departments to undertake medical practice during spare time, on a purely charitable basis without detriment to his official duties. This will not apply to those who possess the qualification and are employed as physicians, surgeons etc., on the Railways.

(E (D&A) 64 GSI-5 dt. 30-5-64 and 10-11-65.)

Railway’s Ministry’s decision.---(4) No railway servant should negotiate for commercial employment during service without obtaining the prior permission of

the Head of the Department and such permission should not be given unless there are any special reasons for doing so.

(E(G) 6 EM 1-2 dt. 26-3-66.)

15-A. Sub-letting and vacation of Government accommodation.

(1) Save as otherwise provided in any other law for the time being in force, no Railway servant shall sub-let, lease or otherwise allow occupation by any other person of government accommodation which has been allotted to him.

(2) A Railway servant shall, after the cancellation of his allotment of Government accommodation vacate the same within the time-limit prescribed by the allotting authority.

(Authority: Railway Board's letter No. E (D&A) 96 GS1-8 dt. 17.01.1997.)

16. Investment, lending and borrowing. —(1) No Railway Servant shall speculate in any stock, share or other investment:

Provided that nothing in this sub0rul shall apply to occasional investments made through stock brokers or other persons duly authorized and licensed or who have obtained a certificate of registration under the relevant law.

Explanation – Frequent purchase or sale or both, of shares, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-rule.

(2) (i) No Railway servant shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties. For this purpose, any purchase of shares out of the quotas reserved for Directors of Companies or their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to embarrass the Railway servant.

(Authority: Railway Board's letter No. E (D&A) 96 GS 1-8 dt. 17.01.1997.)

(2) (ii) No Railway servant who is involved in the decision making process of fixation of price of an Initial Public Offering or Follow-up Public Offering of shares of a Central Public Sector Enterprise shall apply, either himself or through any member of his family or through any other person acting on his behalf, for allotment of shares in the Initial Public Offerings or Follow-up Public Offerings of such Central Public Sector Enterprise".(Authority: Railway Board's letter No.E(D&A) 2009/GS1-4 dated 14-07-09)—**acs no.108**

(3) If any question arises whether any transaction is of the nature referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2), the decision of the government thereon shall be final.

(4) (i) No railway servant shall, save in the ordinary course of business with a bank or a public limited company either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf—

(a) Lend or borrow or deposit money, as a principal or an agent, to or from or with, any person or firm or private limited company with whom he is likely to have official dealings or otherwise place himself under pecuniary obligation to such person or firm or private limited company; or

(b) lend money to any person at interest or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid.

Provided that a railway servant may give to, or accept from, a relative or a personal friend, a purely temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a bonafide tradesman or make an advance or pay to his private employee.

Provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered into by a railway servant with the previous sanction of the Government.

(ii) When a railway servant is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (4), he shall forthwith report the circumstances to the competent authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority.

Railway Ministry's decision. —Loan taken from LIC by the Railway servant against their Insurance policies will be covered by the exception provided in the above rule and permission of the Government will not be necessary.

(E (D&A) 68 GSI/21 dt. 21-11-1968.)

17. Insolvency and Habitual indebtedness. --- (1) A railway servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. A railway servant against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvent shall forthwith report the full facts of the legal proceeding to the Government.

Note.---- The burden of proving that the insolvency or indebtedness was the result of circumstances which, with the exercise of ordinary diligence, the railway servant could not have foreseen, or over which he had no control and had not proceeded from extravagant or dissipated habits, shall be upon the railway servant.

(2) The following procedure shall be followed in the case of non-gazetted railway servants: -

(i) The report required under sub-rule (1) above shall be submitted by the railway servant to his immediate superior who should forward it through the normal channel to the authority competent to remove or dismiss the employee from service. Except where such authority requires guidance or clarification from a higher authority, it shall consider and pass appropriate orders thereon. A railway servant desiring to seek the benefit of the Insolvency Act shall apply to the Head of his Department, or to such authority as the government may specify in this behalf, for permission to file a Schedule in a Court of Law. Same time, he shall explain in such form as the Government may prescribe in this behalf all the circumstances which led to his financial embarrassment. The said authority will then consider his case in the light of those circumstances.

If the railway servant can prove that the indebtedness was the result of circumstances, which, with the exercise of ordinary diligence, he could not have foreseen or over which he had no control, and did not proceed from extravagant or dissipated habits and if as the result of investigation, the said authority considers that sufficient justification exists for the retention of the employee in service, he may permit him to have recourse to the court.

Otherwise he should take steps either to dismiss or remove the employee from service as the circumstances of the case may warrant . If a railway servant asks for permission to seek the benefit of the Insolvency Act for second time such permission may not be granted by an authority lower than the General Manager or Head of Office who, if he decides to retain the employee in service, shall report the circumstances to the Railway Board for information. As the Railway Co-operative Credit is often the creditor in such a case and other railway servants are sureties for the debtor, the said authority will, in deciding whether or not the debtor should be retained in railway service, consider the effect of this dismissal or removal on the railway and on his fellow employees.

1. No. E (D&A) 58 GSI-6 dt. 15-3-58 and 27-6-66.
2. No. E (D&A) 60 GSI-5 dt. 7-6-60..
3. No. E(D&A) 60 GSI-5 dt. 30-1-61.
4. No. E(D&A) 64 GSI-6 dt. 25-2-65.
5. No. E(D&A) 69 GSI-14 dt. 14-8-69.
6. No. E(D&A) 75 GSI-3 dt. 9-3-75 .
7. No. E(D&A) 76 GSI-2 dt. 30-4-76.

(ii) A railway servant who seeks the assistance of the Insolvency Court without the previous permission of the competent authority shall render himself liable to removal from service .

(iii) A railway servant who is arrested for debt is liable for dismissal.

(iv) Steps will be taken from time to time by the head of an office to ascertain from pay sheets, etc. whether any railway servant under him are in habitual state of indebtedness. If a moiety of the pay of a railway servant is being frequently attached for debit has been continuously so attached for a period exceeding two years or is attached for a sum which under ordinary circumstances he could not repay within two years, such railway servant shall be considered liable for dismissal.

(v) Every case falling under (iii) or (iv) shall be considered in the light of the instructions contained in clause (i) above before it is finally decided whether or not the railway servant concerned should be dismissed or removed but in exceptional circumstances such railway servant should not be retained in service.

(3) A railway servant shall also report to the Government or to such authorities as may be specified in this behalf the facts when a portion of his salary is constantly being attached, has been continuously attached for a period exceeding two years or is attached for a sum which, in ordinary circumstances, cannot be paid within a period of two years.

(4) When a moiety of a railway servant's salary is attached, the report by his superior officer to the Government competent authority should show what is the

proportion of the debts to the salary; how far they detract from the debtor's efficiency as a railway servant; whether the debtor's position is irretrievable; and whether in the circumstances of the case, it is desirable to retain him in the post occupied by him when the matter was brought to notice; or in any post under the Government.

18. Movable, immovable and valuable Property.---(1) (i) Every railway servant shall on his first appointment to the railway service submit a return of his assets and liabilities, in such form as may be prescribed by the Government, giving full particulars regarding—

- (a) the immovable property inherited by him, owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;
- (b) the shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned, acquired, or held by him;
- (c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him ;
- (d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly.

Note.1 —Sub-rule (1) shall not ordinarily apply to Group 'D' railway servants, but the Government may, in appropriate cases, direct that it shall apply to any of such railway servants or any class of such railway servants.

Note.2--- In every return, the values of items of movable property worth less than Rs. 10,000 may be added and shown as a lump sum. The values of articles of daily use such as clothing, utensils, crockery, books and the like, need not be included in such return.

Note.(3)(1) (i) --- Where a railway servant already belonging to a service or holding a Post is appointed to any other government or Railway service or post, he shall not be required to submit a fresh return under this clause.

(ii) Every railway servant belonging to any service or holding any post included in Group A or Group B shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the Government in this regard giving full particulars regarding the immovable property the inherited by him or owned or acquired by him on held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

(2) No railway servant shall, except with the previous knowledge of the Government acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family:

Provided that the previous sanction of the Government shall be obtained by the Railway servant if any such transaction is with a person having official dealings with him.

(3) Where a railway servant enters into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of a member of his family, he shall,

within one month from the date of such transaction, report the same to the Government, if the value of such property exceeds two months' basic pay of the Railway servant:

Provided that the previous sanction of the Government shall be obtained by the Railway servant if any such transaction is with a person having official dealings with him. **(Authority - Railway Board's letter No.E (D&A) 2011 GS1-3 dated 11.7.2011) acs no.118**

Note.1—Purchase of items of movable property for giving presents at the time of marriage will be regulated by rule 18(3) above like any other transactions in movable property (Railway Board's letter No. E(D&A) 65 GSI-12 dated 23-4-1966.)

Note 2.--- The powers of the Government so far as sub-rule (3) is concerned, may be exercised by—

(i) General Manager and the Chairman, Railway Rates Tribunal, in respect of both gazetted and non-gazetted officers under their respective administrative control; and

(ii) Senior Deputy General Managers on Zonal Railways in respect of gazetted officers below the Senior Administrative Grade and non-gazetted officers subject to the condition that the powers hereby delegated are not further delegated by them to lower authorities so far as cases of gazetted officers are concerned.

(4) The Government or any authority empowered by it in this behalf may, at any time by general or special order, require a railway servant to furnish, within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the Government or by the authority so empowered, include the details of the means by which, or the source from which, such property was acquired.

(5) The Government may exempt any category of railway servants belonging to Group 'C' or Group 'D' from any of the provisions of this rule except sub-rule (4). No such exemption shall, however, be made without the concurrence of the Railway Board, who will consult the Ministry of Home Affairs (Now Cabinet Secretariat, Department of personnel).

Explanation I. —For the purpose of this rule, the expression 'movable property' includes—

(a) jewellery, insurance policies the annual premium of which exceeds two months' basic pay of the railway servant, shares, securities and debentures;**(Authority - Railway Board's letter No.E (D&A) 2011 GS1-3 dated 11.7.2011) acs no.118**

(b) All loans, whether secured or not, advanced or taken by the Government servant.

(c) motor cars, motor cycles, horses, or any other means of conveyance; and

(d) refrigerators, radios, radiograms and television sets.

Explanation II. —For the purposes of this rule, “lease” means, except where it is obtained from, or granted to, a person having official dealings with the railway servant, a case of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent.

Railway Ministry’s decision 1.—It is undesirable for Railway servants to bid at auctions arranged by their own department or under orders of which the auction is conducted and if he does so it would be regarded as indulging in conduct unbecoming of a railway servant under the rules.

(E (D&A) 58 GS-1-6 dt. 15-3-58 & 27-6-66.)

Railway Ministry’s decision 2. —The intention of proviso to sub-rule (2) & (3) regarding bonafide deal is to assure that—

- (i) the transaction proposed to be entered into is for bonafide purposes;
- (ii) the acquisition/sale of property in question is at fair prevailing market prices and does not involve any element of profiteering or speculation;
- (iii) there is no reasonable ground to hold that the transaction in question is the result of the exercise of any undue official influence by the officer e.g. in return of any official favours conferred or likely to be conferred upon the prospective seller/buyer of the property; and

- (iv) there is nothing otherwise objectionable in return to the proposed transaction.

(E (D&A) 60 GS-1-5 dt. 7-6-60.)

Railway Ministry’s decision 3. —The term “Regular and reputed dealer” means a person or firm who deals in a particular item and keeps regular accounts of lists, its transaction and who has regular business premises. A co-operative housing society registered under the Co-operative Society’s Act, 1912 or any corresponding law in force also falls under this definition.

(E (D&A) 60 GS-1-5 dt. 30-1-61.)

Railway Ministry’s decision 4. -- Whenever a Railway servant wishes to build a house, the following procedure should be followed: -

(a) Before starting construction of the house, he should report or seek permission as the case may be and after completion of the house, he should report to the prescribed authority.

(b) The details in proforma prescribed should be furnished wherever it is possible to do so. Wherever it is not possible to furnish the details about purchase of movable property acquired for the construction of the house, the Railway servant concerned should mention the covered area on which the building is proposed to be erected and the estimated cost of the building .

(c) In case where the expenditure to be incurred on repairs or minor construction work in respect of any immovable property belonging to a Railway servant, is estimated to exceed Rs. 1,000/- sanction of the prescribed authority is required.

Railway Ministry’s decision 5. ---The factum of giving or receiving money between father and son can be termed as a transaction of movable property within the meaning of Rule 18 (3).

(E (D&A) 64 GS-1-6 dt. 25-2-65.)

Railway Ministry's decision 6. ---In exercise of the powers conferred by rule 24 read with Rule 2(a) (ii) of these rules, the Railway Board hereby directs as follows:

- (i) Powers exercised by the Railway Board under rule 18(2) of the above rules shall be also exercisable by the General Managers, all Indian Railways, Production Units and the Director General, RDSO in respect of Gazetted officers under their respective administrative control subject to the condition that all cases of such sanction accorded by them shall be reported to the Railway Board, and
- (ii) Powers exercisable by the Railway Board under rule 18(3) of these rules shall be also exercisable by Director General, RDSO in respect of gazetted officers under his administrative control.

(E (D&A) 69 GS-1-11 dt. 14-8-69.)

Railway Ministry's decision 7. —Railway servants should not buy or sell property to or from a firm with whom he has official dealings. In exceptional cases, however, permission may be granted only after careful enquiry into the officer's dealing with the firm and after it is satisfactorily established that he was not conferred and is not likely to confer any official favour upon the party concerned.

(E (D&A) 69 GS-1-3 dt. 9-5-75.)

Railway Ministry's decision 8. —While no permission of the Government is necessary for taking Life insurance Policy or making fixed deposits in Banks under sub-rule (3) above, permission is required to be obtained to join a Chit Fund.

(E (D&A) 69 GS-1-36 dt. 13-12-76.)

Railway Ministry's decision 9. —The provision of Delhi Rent Control Act and similar other provisions in other States, wherever applicable, should be observed by Railway servants while taking rent advance for property held by them.

(E (D&A) 69 GS-1-2 dt. 30-4-76.)

Railway Ministry's decision 10. —It is clarified that transactions entered into by the spouse or any other member of family of a railway servant out of his or her own funds (including stridhan, gifts, inheritance etc.) as distinct from the funds of the railway servant himself in his or her own name and in his or her own right, would not attract the provision of sub-rule (2) and (3) of Rule 18.

Railway Ministry's Decision No.11: Supervisory staff of Group 'C (class-III) on railways working in scales of pay the maximum of which is Rs.900/- and above, should also submit an annual return regarding the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him, or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person. The return should be submitted within three months of his first appointment in the grade and thereafter in the month of January every year.

[No.E(D&A) 78 GS1-14 dated 24.10.1980]

Railway Ministry's Decision No.12: The following categories of Commercial Staff in all grades, viz.- Reservation Clerks, Parcel Clerks, Booking Clerks,- TTEs and TCs, should, besides submitting a property return on their initial appointment as required in Rule 18 (1) (i) of the Conduct Rules, should also submit a return of

their property at the time of every promotion, as also at the time of submitting documents for pension (approximately two years prior to superannuation).

[No.E(D&A) 85 GS1-13 dated 10.2.1986]

Railway Ministry's Decision No. 13: Sale and purchase of shares, securities, debentures, etc. are to be treated as transactions in movable property. An intimation is to be given under Rule 18(4) to the prescribed authority in the proforma laid down in the following cases:

- (i) Group 'A' and 'B' Officers - If the cumulative transactions i.e., sale, purchase or both in shares, securities, debentures or mutual funds scheme etc. exceeds Rs.50,000/- during the calendar year.
- (ii) Group 'C' and 'D' Officers - If the cumulative transactions i.e., sale, purchase or both in shares, securities, debentures or mutual funds scheme etc., exceeds Rs.25,000/- during the calendar year.

The above intimation will be in addition to the intimation(s) required to be given under Rule 18(3) in respect of individual transactions in shares, securities, debentures, etc. which exceeds the amounts prescribed therefor.

[E(D&A)92 GS1-2 dated 17/21.05.1992]

(Authority: Railway Board's letter No.E(D&A) 2007/GS 1-1 dated 26/10/2007]

-ACS No.104)

18-A. Restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property out side India and transaction with foreigners, etc.—Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 18. No railway servant shall except with the previous sanction of the Government –

- (a) Acquire, by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, any immovable property situated outside India.
- (b) dispose of, by sale, mortgage, gift or otherwise, or grant any lease in respect of any immovable property situated outside India which was acquired or is held by him either in his own name or in the name of any member of his family;
- (c) enter into any transaction with any foreigner, foreign Government, foreign organization or concern—
 - (i) for the acquisition, by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, or any immovable property.
 - (ii) for the disposal of, by sale, mortgage, gift or otherwise , or the grant of any lease in respect of, any immovable property which was acquired or is held by him either in

his own name or in the name of any member of his family.

19. Vindication of Acts and Character of Railway servants.—(1) No railway servant shall, except with the previous sanction of the Government, have recourse to any Court or to the Press for the vindication of any official act which has been subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.

Provided that if no such sanction is received by the railway servant within a period of three months from the date of receipt of his request by the Government, he shall be free to assume that the permission as sought for has been granted to him.

(Authority: Railway Board's letter No., E(D&A) 96 GS1-5 dated 24-12-96)

(2) Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a railway servant from vindicating his private character and or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in his private capacity is taken, the railway servant shall submit a report to the Government regarding such action.

Railway Ministry's decision 1.—Railway servants seeking redress of their grievances arising out of their employment of conditions of service should in their own interest and also consistently with official propriety and discipline first exhaust the normal official channels of redress before they take the issue to a court of law. Any attempt by Railway servants to seek redress from the court of law or such matters (even in cases where such a remedy is legally admissible) without first exhausting the normal official channels of redress can only be regarded as contrary to official propriety and subversive of good discipline and may well justify the initiation of disciplinary action against them.

(E (D&) 62 RG6-21 dt.5-2-64 & E (D&A) 69 RG 6-37 dt. 14-2-67.)

20. Canvassing of Non-official or other Influence. —No railway servant shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.

Railway Ministry's decision.—Railway servants are advised to strictly refrain from bringing pressure from the M.Ps and other influential outsiders to secure benefits out of turn or regarding any matter arising out of their service. If such occasions arise, the name of the officer or the member of the staff concerned will be brought to the notice of the Head of the Department for such disciplinary action as may be considered necessary.

(E (D&A) 70 RG6-9 dt. 7-7-71.)

21.Restrictions Regarding Marriage.—(1) No railway servant shall enter into, or contract, a marriage with a person having spouse living: and,

(2) No railway servant, having a spouse living shall enter into, or contract, a marriage with any person.

(3) A railway servant who has married or married a person other than of Indian Nationality shall forthwith intimate the fact to the Government. Provided that the government may permit a railway servant to enter into, or contract, any such marriage as is referred to in clause (1) or clause (2), if it is satisfied that—

(a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such railway servant and other party to the marriage ; and

(b) there are other grounds for so doing .

22. Consumption of intoxicating Drinks and Drugs. —(1) A railway servant shall—

(a) strictly abide by the law relating to intoxicating drinks or drugs during the course of his duties and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug,

(b) refrain from consuming any intoxicated drink or drug in a public place;

(2) A railway servant shall not—

(a) appear in a public place in a state of intoxication;

(b) use any intoxicating drink or drug to excess;

(c) if he belongs to the category of running staff (both local and traffic) or is connected directly with train passing, have taken or used any intoxicating drinks or drugs within eight hours of the commencement of duty or take such drinks or drugs during the course of duty.

Explanation. —For the purpose of this rule, “Public place” means any place or premises (including conveyance to which the public have, or are permitted to have, access whether on payment or otherwise.

22-A Prohibition regarding employment of Children below 14 years of age.—No Railway servant shall employ to work any child below the age of 14 years.

(Authority: Railway Board’s letter No.E(D&A) 99 GS1-3 dated 7-1-2000)

23. Interpretation. —The power of interpreting these rules is reserved to the president.

24. Delegation of Powers. —The Government may, by general or special order, direct that any power exercisable by it under these rules shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by such officer or authority as may be specified in the order.

25. Repeal and Savings. —The Railway Services (Conduct) Rules, 1966, contained in Appendix VI of the Indian Railways Establishment Code, Volume I, shall cease to be in force except as respects things done or omitted to be done.

Obligation to abide by all administrative Instructions.
—Notwithstanding anything contained in these rules, a railway servant shall be governed by all the administrative instruction that may be issued from time to time in regard to the conduct of railway servants.

.....

Appendix- II
END

16. Power to relax.-Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

17. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these Rules, it shall be referred to the Railway Board for decision.

SCHEDULE

[See rules 3(vi) and 7(2)]

PART – A

Pay Matrix

Revised Pay Structure for posts in Group ‘C’, ‘B’, & ‘A’ except posts for which different revised pay structure is issued separately

Existing Pay Band	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
Existing Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000			
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600	
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900	
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400	
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100		
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300		
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600		
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100		
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700			
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200			
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800			
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600			
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600			
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800			
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200			
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200				
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300				
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600				
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800					
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900					
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100					
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700						
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100						
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600						
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300						
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100						
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100						
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200						
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500						
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900						
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500						

Existing Pay Band	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
Existing Grade Pay	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000			
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13A	14	15	16	17
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200						
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100						
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200						
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400							
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000							
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700							
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600							
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700							
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500								

Notes:

1. The revised pay structure is applicable to all categories of Railway servants irrespective of their designations strictly on the basis of the existing pay structure except as may be specifically prescribed otherwise by Ministry of Railways (Railway Board).
2. The existing classification of Railway servants in Group 'C', 'B' & 'A' on the basis of the existing pay structure will continue in the revised pay structure till further orders except as may be specifically prescribed otherwise by Ministry of Railways (Railway Board). No change in the classification should be made in the revised pay structure.

FORM OF OPTION

[See Rule 6 (2)]

*1. I, _____ hereby elect the revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

*2. I, _____ hereby elect to continue on Pay Band and Grade Pay of my substantive / officiating post mentioned below until:

* the date of my next increment / the date of my subsequent increment raising my pay to Rs. _____ / I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure / the date of my promotion/upgradation to the post of _____.

Existing Pay Band and Grade Pay _____

Signature _____

Name _____

Designation _____

Office in which employed _____

* To be scored out, if not applicable.

UNDERTAKING

I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in these Rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature _____

Name _____

Designation _____

Date :

Place :

SUMMARY

S.No.	Name of the Allowance	Rates prior to 7 th CPC	New Rates as per MoF Resolution dated 06.07.2017	RBE No. & date
1	Special Running Staff Allowance (Additional Allowance)	₹ 1000/- + DA p.m to Loco Pilot (Mail) ₹ 500/- + DA p.m to Loco Pilot (Passenger) ₹ 500/- + DA p.m to Mail Guard	₹ 2250/- p.m to Loco Pilot Mail/Express ₹ 1125/- p.m to Loco Pilot Passenger/ Motorman ₹ 1125/- p.m to Guard Mail/Express ₹ 750/- p.m to Loco Pilot Goods ₹ 750/- p.m to Sr. passenger Guard	85/2017 dt 10.08.2017
2	Special Train Controllers' Allowance	New Allowance	₹ 5000/- per month to Section Controllers and Chief Controllers	86/2017 dt 10.08.2017
3	Risk and Hardship Allowance for Track Maintainers	New Allowance	₹ 2700/- p.m for Level-8 and below ₹ 3400/- for Level-9 and above Granted to Track Maintainers-I, II, III and IV	87/2017 dt 10.08.2017
4	Tenure Allowance to Officers posted in Railway Board and RDSO	10% of Basic Pay subject to a ceiling of ₹ 4000/-	10% of Basic Pay subject to a ceiling of ₹ 9000/-	181/2017 & 182/2017 dt. 04.12.2017
5	Breakdown Allowance	₹ 80/- p.m to Helper Gr. II/ Helper Gr. I/ Other staff Gr. 'D' Staff (GP 1300,1400,1650,1800/ PB-1) ₹ 120/- p.m to Technician Gr. III (GP 1900/ PB-1) ₹ 160/- p.m to Technicians Gr. II, Technicians Gr. I and Supervisors (GP 2400,2800/ PB-1) ₹ 200/- p.m to Sr. Technicians/Junior Engineers and staff in higher scales (GP 4200 & Above/ PB-2)	₹ 270/- p.m to Helper Gr. II/ Helper Gr. I/ Other staff Gr. 'D' Staff (Level 1) ₹ 405/- p.m to Technician Gr. III (Level 2) ₹ 540/- p.m to Technicians Gr. II, Technicians Gr. I and Supervisors (Level 4 and 5) ₹ 675/- p.m to Sr. Technicians /Junior Engineers and staff in higher scales (Level 6 and above)	106/2017 dt 30.08.2017
6	National Holiday Allowance	₹ 170/- for Pay in Pay Band + GP upto 7260 ₹ 212/- for Pay in Pay Band + GP = 7261-9700 ₹ 280/- for Pay in Pay Band + GP = 9701 and above	₹ 384/- per day to Level-1 and 2 ₹ 477/- per day to Level- 3 to 5 ₹ 630/- per day to Level- 6 to 8(limited to non-gazetted staff)	108/2017 dt 30.08.2017

7	Flag Station Allowance	₹ 120/- per month	ABOLISHED. Eligible employees to be governed by "Extra Work Allowance" @ 2% of Basic Pay per month	121/2017 dt. 05.09.2017
8	PCO Allowance	7.5% of Basic Pay for eligible staff in GP 4600. 15% of Basic Pay for eligible staff up to GP 4200.	6% of basic Pay for Section Engineers and Sr. Section Engineers (Level-7 in Pay Matrix) 12% of Basic Pay for Non-Supervisory Staff and Jr. Engineers (Upto Level-6)	112/2017 dt 30.08.2017
9	Special Allowance to Chief Safety Officers/Safety Officers	7.5% of Basic Pay for eligible staff	6% of Basic Pay	111/2017 dt 30.08.2017
10	Special LC Gate Allowance to Track Maintainer	₹ 450/- per month	₹ 1000/- p.m upto Level-8 ₹ 1200/- p.m for Level-9 and above Granted to Track Maintainers deployed for manning any of the Engineering Gates	110/2017 dt 30.08.2017
11	Coal Pilot Allowance	₹ 45 for the First Trip ₹ 15 for every subsequent trip	₹ 102/- for the First Trip ₹ 34/- for every subsequent trip	92/2017 dt 11.08.2017
12	TA/DA for Railway officials			103/2017 dt. 24.08.2017
13	Children Educational Allowance	CEA @ ₹ 1500/- p.m Hostel Subsidy @ ₹ 4500/- p.m	CEA @ ₹ 2250/- p.m Hostel Subsidy @ ₹ 6750/- p.m	147/2017 dt. 12.10.2017
14	Overtime Allowance			175/2017 dt. 28.11.2017
15	Constant Attendant Allowance	₹ 4500/- p.m	₹ 6750/- p.m	101/2017 dt 24.08.2017
16	Conveyance Allowance			89/2017 dt 10.08.2017
17	Daily Allowance on Tour			84/2017 dt 08.08.2017
18	Fixed Medical Allowance (FMA)	₹ 500/- p.m	1000/- p.m	75/2017 dt 28.07.2017
19	Hard Area Allowance	25% of Basic Pay to Central Government employees on their posting to the Nicobar and Lakshadweep groups of Islands	20% of Basic Pay to those posted in Nicobar Group of Islands and Minicoy in Lakshadweep Islands 12% of Basic Pay for those posted in Lakshadweep Group of Islands	95/2017 dt 16.08.2017
20	Health and Malaria Allowance	₹ 600/- per month	₹ 1000/- p.m upto Level-8 ₹ 1200/- p.m for Level-9 and above	159/2017 dt 27.10.2017
21	House Rent Allowance	30% of Basic Pay for Class-X cities 20% of Basic Pay for Class-Y cities 10% of Basic Pay for Class-Z cities	24% of Basic Pay for Class-X cities 16% of Basic Pay for Class-Y cities 8% of Basic Pay for Class-Z cities	71/2017 dt 19.07.2017

22	Cycle (Maintenance) Allowance	₹ 90/- p.m	₹ 180/- p.m	93/2017 dt. 11.08.2017
23	Non-Practising Allowance (NPA)	25% of Basic Pay	20% of Basic Pay	82/2017 dt 04.08.2017
24	Nursing Allowance	₹ 4800/- per month	₹ 7200/- per month	166/2017 dt. 13.11.2017
25	Ration Money Allowance	₹ 95.52 per head per day	₹ 97.85 per head per day	17/2017 dt. 28.02.2017
26	Refreshment Allowance	₹ 240/- per day per head	₹ 540/- per day per head	RSPB No. 03/2017
27	Special Compensatory (Remote Locality) Allowance.		Subsumed in Tough Location Allowance	91/2017 dt 11.08.2017
28	Special Duty Allowance	37.5 percent of Basic Pay for AIS officers and 12.5 percent of Basic Pay for other employees	10% of Basic Pay for personnel serving in North Eastern region and Ladakh	88/2017 dt 10.08/2017
29	TA for retiring employees			117/2017 dt. 01.09.2017
30	TA on Transfer			117/2017 dt. 01.09.2017
31	Training Allowance	30 percent of Basic Pay in the National/Central Training Academies and Institutes for Group 'A' officers and 15 percent of Basic Pay in other training establishments	24% of Basic Pay to Faculty Members in National/Central Training Academies and Institutes for Group 'A' Officers 12% of Basic Pay to Faculty Members in other Training Establishments	145/2017 dt. 06.10.2017
32	Transport Allowance (TPTA)			80/2017 dt 03.08.2017
33	Bad Climate Allowance	₹ 600/- p.m for GP > 5400 ₹ 360/- p.m for others	Subsumed in Tough Location Allowance-III (R3H3 of Risk and Hardship Matrix) ₹ 1000/- to Level-8 and Below ₹ 1200 to Level-9 and above	91/2017 dt. 11.08.2017
34	Kit Maintenance Allowance		Subsumed in Dress Allowance	141/2017 dt. 03.10.2017
35	Out of Pocket Allowance		Discontinued	RSPB No. 04/2017
36	Shoe Allowance	₹ 900/- per annum	Subsumed in Dress Allowance	141/2017 dt. 03.10.2017
37	Sunderbans Allowance	₹ 90 for pay in Pay Band < 5600 ₹ 180 for pay in Pay Band 5600-8400 ₹ 270 for pay in Pay Band 8401-11200 ₹ 360 for pay in Pay Band 11201- 16800	Subsumed in Tough Location Allowance-III (R3H3 of Risk and Hardship Matrix) ₹ 1000/- to Level-8 and Below ₹ 1200 to Level-9 and above	91/2017 dt. 11.08.2017

38	Tribal Area Allowance	₹ 600/- p.m for GP > ₹5400 ₹ 360/- p.m for others	Subsumed in Tough Location Allowance-III (R3H3 of Risk and Hardship Matrix) ₹ 1000/- to Level-8 and Below ₹ 1200 to Level-9 and above	91/2017 dt. 11.08.2017
39	Dress Allowance	New Allowance which subsumes Kit Maintenance Allowance, Shoe Allowance, Uniform Allowance and Washing Allowance.	₹ 20,000/- per annum to Officers of RPF/RPSF ₹ 10,000/- per annum to PBOR of RPF and Station Masters ₹ 5,000/- per annum to other categories of staff who were supplied uniforms and are required to wear them regularly ₹ 1800/- per month to Nurses	141/2017 dt. 03.10.2017
40	Compensatory (Construction or Survey) Allowance	₹ 1500/- p.m for GP > 5400 ₹ 1000/- p.m for others	₹ 3400/- p.m for Level 9 and above ₹ 2700/- p.m for Level 8 and below	156/2017 dt. 12.12.2017
41	Project Allowance	₹ 2250/- p.m for GP > 5400 ₹ 1500/- p.m fo others	₹ 2700/- p.m upto Level-8 ₹ 3400/- p.m for Level-9 and above	156/2017 dt. 12.12.2017